साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष : 12 अंक : 51 | प्रति सोमवार, इंदौर 30 जुलाई से 6 अगस्त 2018 | पृष्ठ : 12 | मूल्य : 2 रुपए

अंतर्राष्ट्रीय चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध विकासशील देशों के लिए फायदेमंद रहेगा

वर्तमान चीन और अमेरिका का व्यापार युद्ध, खत्म करेगा दोनों की दादागिरी

वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच में भारी आयतों को लेकर क्षेत्रीय प्रवेश कर व अन्य कर लगाकर आयातों को न्यूनतम करने की जो होड़ लगी हुई है। वह विश्व में चीन और अमेरिका की बढ़ती हुई विश्व पर दादागिरी खत्म करने के लिए बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा हुआ पूंजीपति ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ। उसने अपने लाभ के लिए दूसरे पूंजीपति राक्षसों यथा वालमार्ट, जैसों के पर काटने शुरू कर दिए। उसने अपने देश की वास्तविक प्रगति उत्पादन बढ़ाने, देश के युवाओं को रोजगार देने, देश की प्रगति के लिए विश्व व्यापार आतंकी संगठन के शर्तों को भी मानने से साफ मना कर दिया। इसे दुनिया के महा धूर्त चालाक और बहू शोषणकारी पूंजीपतियों के इस विश्व व्यापार संगठन के कार्यो का मूल उद्देश्य ही था दुनिया के विकास विकासशील विकसित देशों की सरकारों को खरीदकर वहां पर पहले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, माल एवं सेवा कर जैसे कानून बनवाकर वहां के प्राकृतिक और मानव निर्मित लाभकारी स्त्रोतों पर कब्जा कर वहां की टुकड खोर सरकारों के नेताओं अधिकारियों को टुकड़े डालकर वहां की जनता का चहुँओर शोषण गुलाम बनाकर मोटा लाभ कमाया जाता रहे। जैसा कि हमारे देश में हमारा ही पानी, हमारी ही बोतल, हमारा ही बाजार हमारे ही लोगो के बीच बेचकर हजारों करोड़ का धन विदेशी कंपनियां ले जा रही है। यही व्यवस्था मेक्सिको में थी। उन्हीं का पानी,

विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को मानने से अमेरिका का साफ इनकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विश्व पर वर्चस्व को समाप्त करने में काम आएगा

उन्हीं के लोगों को भारी कीमत मिलने पानी की कृत्रिम कमी पैदा करने के कारण इसे लोगों ने समझा आज से 10 वर्ष पूर्व उन्होंने ऐसी कंपनियों को खदेड़कर बाहर कर दिया। यही हाल भारत में ना केवल पानी वरन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का करने के लिए भारत में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लाखों करोड़ खर्च कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 थोपा गया। यूरोप में इन कंपनियों ने यह हाल शॉपिंग मॉल कल्चर के अंतर्गत पिछले 25 वर्षों से चल रहा है जिसके कारण सभी लघु उद्योग, लघु व्यवसाय छोटी दुकानें बंद कर दिये। इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए बदले में वहां पर भी गरीबों को सरकार की तरफ से अनुदानित खरीदने की व्यवस्था कर दी गई जैसा कि वर्तमान में भारत में हो रहा है। उन्ही के फायदे के लिए भारत में भी 165 देशों की तरह माल एवं सेवा कर थोप दिया। इसके पीछे भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए छोटे फेरी वालो, फुटपाथ पर, धंधा करने वालों को उजड़ा गया ठेले तोड़े गए। छोटी दुकानों में धंधा करने वालों छोटे लघु उद्योगों को खत्म करने यह जीएसटी कानून इतना दुष्कर बनाया गया और उसने दंडात्मक कार्रवाई के साथ कारावास की व्यवस्था भी की गईताकि सभी छोटे दुकानदार छोटे व्यवसाय लघु उद्योग सब खत्म हो जाए और हो गए। इसलिए इस विश्व व्यापार संगठन को शीघ्र समाप्त हो जाना चाहिए। जिसकी शुरुआत अमेरिका से स्वयं कर दी है। दूसरी और चीन ने जिस प्रकार से अपने यहां के मजदूर, कर्मचारी, जनता का विदेशी कंपनियों के उत्पादन के लिए 12 से 14 घंटे मजदूरी लेकर शोषण की जो नीति अपना रखी है वह भी वहां की जनता को घोर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे रहा है। साथ ही जिस प्रकार से चीन अपने यहां अविश्वसनीय, दिखाऊ, सस्ता और काम चलाऊ माल बनाकर पूरी दुनिया के बाजारों में छाया हुआ है। उससे उन देशों के उद्योग धंधे, व्यापार-व्यवसाय चौपट होने से वहां बेरोजगारी की समस्या बढ़ चुकी है। जैसा कि भारत में 25 वर्षों से हो रहा है। इससे अमेरिका, यूरोप व दुनिया के अधिकांश देश भीी पीड़ित हो चुके है, और यही कारण है कि वह चीनी माल के आयात पर प्रवेश कर व अन्य कर लगा चीनी माल के आयात को कम करना चाहता है। जो विश्व व्यापार संगठन की मुक्त व्यापार की अवधारणा का उल्लंघन है। बदले में चीन भी अमेरिकी सामान के साथ यही कर रहा है। पर दो सांडों की लड़ाई में बागड़ भले ही खराब हो जाए परंतु छोटों का लाभ तो होगा ही।

शिवराज के 13 साल चारों तरफ भ्रष्टाचार बेमिसाल, डर से कोई विधानसभा सत्र पूरा नहीं

मप्र के मुमं शिवराज सिंह चौहान चुनाव के निकट आ जाने पर आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं जबकि उन्होंने 13 साल में हर कदम भारी भ्रष्टाचार किए हैं, और बेशर्मी के साथ स्वयं भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जन-धन से प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अरबों करोड़ों रुपए के 13 वर्ष में विज्ञापन बांटे। अपने विरुद्ध चलने वाले व्यापम जैसे प्रकरणों में जन धन से हजारो करोड रुपए खर्च किए। खूब चारों तरफ भ्रष्टाचार किया, खूब जनता को लूटा, फिर भी ऋण लेकर घी पीया। व्यापमं घोटाला, रेत व अन्य खनजि खनन, महिला बाल विकास आपूर्ति, बिजली से हजारों करोड़ प्रतिदिन की कमाई, स्वास्थ्य विभाग में 15 योजनाओं में औषधियों की खरीद, कृषि खाद, बीज, तालाब निर्माण, स्प्रिंकलर आप्रि में, उद्यानकी मे सब्जियों फूलों फलो औषधियों, वन दिमाग में वृक्षारोपण 53 प्रजाति के अरबों वृक्षों की कटाई, भावांतर, शिक्षक भर्ती घोटाला, बी ओ टी सड़कों के नाम दुगनी चौगुनी दरो पर ठेके, सॉफ्टवेयर के नाम पर 2000 करोड का घोटाला, परिवहन विभाग में पहले सरकारी बसों को खत्म किया अपने नेताओं की बसें चलवाई। सरकारी बसों की चलवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जाती रही। सिंहस्थ में रुपए 40 से 50 हजार करोड़ की बर्बादी कर मोटा पैसे हजम किया गया।भूमाफियाओं शराब माफियों के इशारे पर नाचना, स्कूलों कॉलेजों में मुफ्त लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल, स्कूलों की ड्रेस, पुस्तकें लाखों करोड़ की छात्रवृत्ति बांटने के नाम हजारों करोड हजम, ग्रामीण विकास मे शौचालय, झोपड़ी, इंदिरा आवास, सीमेंट सड़कों का निर्माण, खेत का पानी खेत मैं तालाब निर्माण, बड़े शहरों मैं बीआरटीएस निर्माण में 60% की सैकड़ों करोड का ऋण हजम, शहरीय विकास में सफाई के नाम हजारों करोड पार्षदों से लेकर महापौर निगम आयुक्त ने, जनभागीदारी के नाम कंक्रीट की सड़के बनाने के नाम पर, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के नाम, मनरेगा का हजारों करोड, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, जे एन आर यु एम का हजारों करोड़, ग्रामीणों को पट्टे बांटने के नाम, हजारों हेक्टेयर वन, नजुल, चरनोइ, सरकारी भूमि, भूमाफियाओं कॉलोनाइजरों को देकर अवैध कालोनियां कटवाई, जिसमें हजारों करोड़ का लेनदेन हुआ, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर बांधों के निर्माण, वनों एवं पुनर्स्थापना विस्थापन के नाम हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। जल संसाधन और नर्मदा घाटी में 20 से ज्यादा अनावश्यक जल उद्ववहन परियोजनाओ के निर्माण के नाम हजारों करोड हजम करने का नियोजन, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, लोक-स्वास्थ्य-यांत्रिकीय, सभी लूट विकास प्राधिकरणों, निगम पालिकाओं, गृह निर्माण मंडल आदि मैं हाल ही में सामने आए लाखो करोड के इंटिंडरगि घोटाले, खाद्य नागरिक आपूर्ति में **शेष पेज 3 पर**

विश्व में प्रदूषण के लिए यूरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार

मानवीय संयुक्त घोर गिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लालच ने हीं पूरी दुनिया को भारी प्रदूषण की आग में झोंक, न केवल बर्बाद किया बरन आने वाली मानव पीढ़ियों के साथ, ही जल थल और नभ मैं निवास व विचरण करने वाले वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए भी पूर्ण रूप से नष्ट करने का खतरा खड़ा कर दिया है। अधिकांश कंपनियां यूरोप और अमेरिका की है। जिन्होंने जीवाश्म ईंधन या पेट्रोल डीजल किसका प्रयोग स्वचालित वाहनों में प्रयोग किया जाता है। इस पेट्रोल डीजल के उपयोग से निकलने वाला धुआं और उसके अन्य प्रदूषणकारी तत्वों के साथ इस जीवाश्म ईंधन के शुद्धिकरण से प्राप्त कार्बन के सह उत्पाद के रूप में जो प्लास्टिक दाना प्राप्त होता है वह खाद्य वस्तुओं के साथ ही सभी अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए पैकिंग का जो पॉलिथीन प्लास्टिक बोतल एलुमिनियम जिलेटिन आदि के उपयोग से पूरी दुनिया के जल थल नभ को को दूषित कर दिया। प्लास्टिक और पॉलिथीन यथार्थ में पेट्रो का सह उत्पाद ही है।जो की अधिकांश खाद्य वस्तुओं की पैकिंग के साथ ही अन्य उपभोक्ता सामग्री को को पैक करने के काम आता है ने हीं, जल और थल को अपने पुनः प्रयोग ना हो पाने के कारण ढक दिया है । निसंदेह सारे पेट्रो प्रोडक्ट न हीं वर्तमान में सबसे ज्यादा दुनिया को परेशान कर रखा है जिसके कारण समुद्र से लेकर धरती तक, राम सामान्य जीव जंतुओं को वनस्पतियों को अपने जीवन निर्वाह में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर यह सब मानव की ही आधुनिकता, शीघ्रता का हीं तो परिणाम है जिसने पृथ्वी पर और उसके वायुमंडल को प्रदूषित कर पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर रखा है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग की जाने वाली पेट्रोल डीजल और गैस जो कि धरती से प्राप्त जी जीवाश्म ईंधन का ही अंश है इसके उपयोग से निकलने वाले धुये जिसमें अनेकों प्रकार की अन्य गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, **शेष पेज 6-7 पर**

जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, हल्ला भी वही मचाते हैं, अपने कुकर्मो को छुपाए रखने में

वोट जनता देती है, पूंजीपति नहीं... पूंजीपतियों का हजारों करोड़ प्रतिदिन का फायदा करवा रहे मोदी दानव

विकास पुरुष का दावा करने वाले बन गए विनाश पुरुष

प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के लिये निसंदेह पूंजीपतियों से हजारों करोड़ लेकर जनता से वसूली के लिए कानून बनाकर नोटबंदी करो जीएसटी लगाओ स्मार्ट सिटी बनाओ और देसी विदेशी पूंजीपतियों का हजारों करोड़ प्रतिदिन का फायदा करवाया, जनता को लुटवाया, बेरोजगार किया। मोदी चाहता तो आते ही सबसे पहले रेलवे में 10 लाख, पोस्ट ऑफिस में 1लाख पोस्टमैन की, सेना में 2लाख, आयकर, कस्टम एंड एक्साइज, बीमा, बैंकों, अर्द्ध सैन्यबलों में 5 लाख विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों में 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती कर आसानी से 20लाख लोगों को रोजगार देकर 2 करोड लोगों का दिल जीता जा सकता था। चीन से आयात बंद कर आसानी से देश के 1 करोड से ज्यादा लघु उद्योग को विकसित कर आसानी से 5 करोड लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। इस प्रकार मोदी लोगों के दिलों पर राज करता और अगले 10 नहीं 20 साल राज करता। पर नोटबंदी और जीएसटी से 40 लाख से ज्यादा लघु उद्योग धंधो को बंद कर दिया गया जिससे चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई और 20 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए। जब 50 लाख नए रोजगार पैदा करने की जगह हर साल 10 लाख

नौकरियाँ खत्म होने की नौबत आ जाये तो जोर जोर से भारत माता की जय,भारत माता की जय चिल्लाना शुरू करें। जनता खुश हो जाएगी और लोगों को एक नया रोजगार मिल जायेगा।

जब 3500 करोड़ विदेशी दौरों में खर्च करने के बाद,पैसे देकर मोदी-मोदी चिल्लाने के बाद भी, तीन साल में एक बड़ा विदेशी निवेशक भारत आने को तैयार न हो तो प्रेमी जोड़ों को पकड़कर कूटने लगिये। जनता को लगेगा कि कम से कम सरकार भारतीय संस्कृति को तो बचा रही है।आयात घटने लगे, पर्यटन चौपट होने लगे ,विदेशों में भारत की तुलना सूडान और नाइजीरिया से की जाने लगे तो। **शेष पेज 6-7 पर**

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

संपादकीय

दुनिया के लोकतंत्र डकैत जालसाज पूंजीपतियों की रखैल

विश्व व्यापार संगठन बनाम धूर्त पूंजी पतियों का लोकतांत्रिक राष्ट्रों में सफेदपोश डकैत संगठन

वर्तमान में पूरे विश्व भर में अधिकांश राष्ट्रों में जहां भी लोकतांत्रिक शासन है पूर्णताः धूर्त मक्कार जालसाज पूंजी पतियों की रखैल हैं। इसीलिए अधिकांश राष्ट्रों में दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा है जो वहां के मानव निर्मित एवं प्राकृतिक संपदा स्त्रोतों पर, वहां की सत्ताओं में बैठे मंत्रियों, मंत्रालयों में बैठे अधिकारियों को आसानी से अपने दलालों के माध्यम से खरीदकर पहले कानून बनवाती हैं और फिर वहां के स्त्रोतों पर व्यवसायिक कंपनियों को बना कर पूंजी निवेश कर, उन स्त्रोतों पर पर कब्जा कर वहां की जनता को एक गुलाम बनाकर दूसरी तरफ मोटा लाभ कमा कर नचिोड़ा जाता है। यथार्थ मे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त शैतान संघ है। यहां विश्व के अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने व्यापार को चलाने और दुनिया की जनता को निचोड़ने के लिए एक वैश्विक राष्ट्रों का संगठन इसीलिए बनाया ताकि कानूनो की आड़ में अपना व्यापार जिसमें हथियार, वमिान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, औषधि, चिकित्सा संबंधी उपकरण, उपभोक्ता सामग्री निर्माता कंपनियां आदि अपने आविष्कारों के दम पर पूरी दुनिया में अपने माल को अपनी मनमानी कीमतों पर दूसरे देशों मे बेचकर हजारों गुना लाभ कमा सकें। यहां तक कि इस संगठन के अनुषांगिक संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाम विश्व संघातक संगठन जिसमें दुनिया की मुख्य रूप से अमेरिकी औषधि, चिकित्सा सामग्री निर्माता कंपनियां पहले नई औषधियां तैयार करती हैं फरि उनको बेचने के लिए बीमारियां खड़ी करके उनका भारी दुष्प्रचार कर दहशथ फैैलाती हैं। यह कारोबार 1910 अमेरिकी ब्रिंतानी औषधि निर्माता कंपनियों का पूरी दुनिया पर चल रहा है। उन्हीं का फैलाया हुआ है प्रोटीन, विटामिन, वेरी-वेरी, रिकेटस, हेपेटाइटिस कि ए से लेकर जेड तक के टीकों की श्रृंखला जिसमें 1980 से लेकर सन 2000 तक हेपेटाइटिस की वभिन्नि तरीके की बीमारियों का दुष्प्रचार कर भारी भय फैलाकर लाखों करोड़ की कमाई की गई। वही हाल एड्स और एचआईवी के नाम पर किया गया जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सारी दुनिया के सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों में बैठे मंत्रियों और अधिकारियों को खरीदकर पूरी दुनिया में लाखों करोड की दवाइयां व कंडोम बेंच दी गई। यही हाल विश्व कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व खाद्य संगठन व विश्व व्यापार संगठन का है। यथार्थ में इन संगठनों के माध्यम से दुनिया के लोकतांत्रिक सरकारों को खरीदकर दुनिया के बड़े पूंजीपति अपनी मोटे व्यवसाय के लिए, उस देश में अपने बनवाए कानूनों जो उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसे बीज अधिनियम 1966, जिससे देश की कृषि फसलों पर कब्जा करके राष्ट्र के लाखों साल पुराने खाद्यान्नों जिस में गेहूं, चावल जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहनों जिसमें चना, तूअर, उड़द, मूंग, मसूर, तिलहनों में मूंगफली, सरसों, तल्ली अलसी, अनेको किस्म की सब्जियों पर अमेरिकी कंपनियों ने कब्जा जमा कर अपने बीज भारत में बेचे। कीटनाशक अधिनियम 1968, का ही परिणाम था भोपाल में यूनियन कार्बाइड कांड जिसमें 20000 लोग मारे गए और दो लाख से ज्यादा हमेशा के लिए बीमार हो गए। दुनिया में सब जगह प्रतिबंधित आयोडीन नमक कानून 1972 मे टाटा ने रु 2करोड देकर बनवाया, उसके बाद से देश में ब्रेन हेमरेज, हृदयाघात, किडनी फेल होना केंसर आदि की बीमारियों की बाढ़ आ गई, जिससे विदेशी कंपनियों की हर वर्ष भारत में हजारों को की दवाइयां बिकना शुरु हो गया। भारतीय व्यापारियों का व्यापार खत्म करने एकाधिकार व्यापारिक गतिविधि नियंत्रण कानून 1970, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम2006, जो भारत के पूर्व इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यूरोप के अधिकांश देशों में लगाकर वहां की छोटे लघु उद्योगों और व्यापारियों को हमेशा के लिए समाप्त कर पूरे व्यापार पर कब्जा कर लिया। इसी कानून के कारण अफ्रीका जैसे देशों में शॉपिंग मॉल कल्चर ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर भूखा मारना शुरू कर दिया। वही हाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस कानून ने भारत में भी किया जीएसटी 2016 आदि सारे अधिनियम पूंजीपतियों के इशारे पर भारत की लोकतांत्रिक सरकार ने लगाएं। और जनता को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा गया।

म प्र वाणिज्य कर, जीएसटी के बाद सन्नाटा, बिना वीडियोग्राफी एँटी इवेंजन की वसूली शुरू

पुराने प्रकरणों मे घोर भ्रष्टाचार, एंटी इवेज़न में बैठाये ऐतिहासिक घोर भ्रष्ट उपायुक्त

अनावश्यक स्व कर निर्धारण, डीम्ड योजना के अंतर्गत करो मैं व्यापारियों को छूट क्यों? सूचना अधिकार अधि. की धारा 4 के अंतर्गत सारी जानकारियां 13वर्ष बाद भी साइट पर क्यों नहीं? विभाग को जागीर समझ लिया। लोसूअ पाठक घोर आलसी, सूचना देना बाध्यता ही नहीं मानता। विभागीय पदोन्नति परीक्षा में 3 वर्ष बाद सभी को शामिल करो।

मप्र राज्य का सबसे अधिक राजस्व देने वाली वाणिज्य कर विभाग की 1 अप्रैल 18 से एंटी इंवेजन विंग पुनः चालू कर दी गई हैं। जिसमें इन 6 विन्गों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ट्रकों और बसों को बिना या उचति बिलिंग कें माल का परिवहन करते हैं पकड़ना शुरू कर दिया है जिससे सभी प्रदेश की जिसमें ग्वालियर, सतना, भोपाल, जबलपुर और इंदौर की अ और ब के पास पर्याप्त काम आ जाने से थोड़ी सी चहल-पहल नजर आने लगी है यहां बैठे सभी उपायुक्तों जो की पुराने ऐतिहासिक घोर भ्रष्ट हैं। इसमें इंदौर में उपायुक्त डी पी शर्मा अ मैं, ब मे आर के शर्मा, भोपाल में प्रदीप दुबे, जबलपुर में ओ पी पांडे, सतना मे सलूजा, ग्वालियर में पदस्थ हैं जिनके अपने भ्रष्टाचार के पुराना इतिहास है। स्वाभाविक है कि सब ने मोटा धन दिया है। और वर्षों से एक ही स्थान पर टिके हुए हैं। ने ट्रकों और बसों को पकड़ने से लेकर उनके माल को जांच करवाते समय उसकी नए अधिनियम में वीडियोग्राफी करवाई जानी चाहिए ताकि कम से कम भ्रष्टाचार हो। पर ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ जब जीएसटी लगा दिया गया और उसने किसी भी प्रकार से सूचना अधिकार में किसी भी जानकारी को देने से प्रतिबंधित नहीं किया है। पर यहां पर सूचना अधिकार में जानकारी मांगने पर वही पुराना राग अलापा जाता है कि हमें एंटी इंवेजन विंग की जानकारी देने से राज्यपाल द्वारा सन 2009 की गजट नोटिफिकेशन में छूट दी हुई है, जबकि केंद्र सरकार के एक्साइज विभाग में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अर्थात अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यहां पर औचित्यहीन दलील दी जाती है। वही हाल मुख्यालय में बैठे लोक सूचना अधिकारी पाठक जो घोर आलसी और मक्कार है। सूचना के अधिकार में जानकारी देने की अपेक्षा यह हरामखोर केवल बहाने बनाने के साथ पत्र में स्पष्ट लिखता है की जानकारी देना बाध्यता नहीं है। जैसे यह सब इनके जागीर है। और विभाग बनिए की दुकान होकर जनता से करों के नाम पर लूट इनका मौलिक अधिकार है।अपील और आवेदन सभी पाठक के आने के बाद रद्द या नस्ती किए जा रहे हैं। सूचना के अधिकार मैं जानकारी ना देने के लिए कदम कदम पर हर अधिकारी बहाने और जालसाजियां करता है। जिसमें आयुक्त से लेकर निरीक्षक स्तर तक सभी शामिल हैं। यहां पर भी अन्य विभागों की तरह उपायुक्त को ही अपीलीय अधिकारी बना दिया गया जैसा कि ग्रामीण यांत्रिकी में बाबू को लोक सूचना अधिकारी और कार्यपालन यंत्री को, वही हाल कृषि विभाग में लोक सूचना अधिकारी उपसंचालक को अपीलीय अधिकारी बना दिया गया ताकि वह जानकारी ना दे और अपील लगाने पर हजम कर जाते। जब धारा 19 मे जिला और संभाग स्तर पर कार्यालय प्रमुख लोक सूचना अधिकारी उनका वरिष्ठ अधिकारी अपीलीय अधिकारी हो सकता है पर हरामखोरों ने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए स्वंय ही उल्टे-सीधे कानून बना लिये।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर वाणिज्यकर के मुख्यालय में बैठे घोर धूर्तो और मक्कारों की फौज वैसे तो सूचना अधिकार के आवेदन देख कर ही भारी नाक मुंह सिकोडती है, फिर अगर आवेदन ले भी लिया, तो वहां बैठा लोक सूचना अधिकारी कारपेंटर जो की लाइन अटैच किया गया है। सीधा आवेदन के जवाब में लिखकर भेजता है, की आवेदन का जवाब और जानकारी देना आवश्यक बाध्यता नहीं। धारा 6(3) के अंतर्गत, उस पत्र को मुख्यालय से भी संबंधितों को अंतरित नहीं किया जाता। अर्थात पूरा विभाग हमारे बाप की जागीर है, और हम कुछ भी करें, भ्रष्टाचार करें, लूटपाट करें, कानूनों की आड़ में, व्यापारियों उद्योगपतियों से वसूली करें, जनता को उसकी जानकारी देना या नहीं देना यह हमारी मर्जी पर है, क्योंकि कानून हमारी रखैल, हमारी मर्जी का है। आश्चर्य तब होता है कि मुख्यालय में ऐसे बदतमीज,घोर, निकम्मे, अधिकारियों को आयुक्त की नाक के नीचे बैठा रखा है। वही हाल विभाग के संचालक पद पर बैठे एन एस मरावी यह भी घोर धूर्त और भ्रष्ट जिसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वयं विभाग ने प्राथमकिी लिखवा दी थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई और निलंबन के साथ अभी तक उसे विभाग से बाहर कर देना चाहिए था। उसे संचालक पद पर इसीलिए बैठाकर रखा गया है ताकि उससे भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी आसानी से मनमर्जी से काम करवा सकें। और संचालक के पद की औपचारिकता की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यही कारण है, कि वह हरामखोर जालसाज सूचना के अधिकार में अपील लगाने पर यहां तक की स्वयंभू बिना कानूनी कार्रवाई किए, अनावेदकों से अपील के जवाब मांगे बिना अनावेदकों को बिना अपील में बुलवाए, स्वयं ही अनावेदक की तरफ से पैरवी करते हुए सारी अपील ही रद्द कर देता है।शायद उसकी बदतमीजी और निकम्मेपन का ही उसको पुरस्कार देकर संचालक बनाया गया है। इस प्रकार इस कानून का अपने भ्रष्ट अधिकारियों और स्वयं के भ्रष्टाचार को बचाने मजाक बना दिया है।

2 माह पूर्व वाणिज्य कर में पदस्थ किए गए, भारतीय प्रताडणाा सेवा के अधिकारी महाभ्रष्ट बसंत कुर्रे जिन्होंने जमीनो के मामले में भूमाफियाओं और नेताओं के साथ मिलकर भारी भ्रष्टाचार किए थे, वर्तमान में वाणिज्य कर में एंटी एवेजन ब्यूरो के अपर आयुक्त के रूप में प्रदेश के प्रभारी है। जीएसटी के बाद वैसे तो वाणिज्य कर में चारों तरफ सन्नाटा है एंटी एवेजन केचालू होते ही ट्रक और बस पर होने वाली माल ढुलाई की जांच करने के अधिकार मिलते ही यहां पर खासी ऊपरी कमाई की 35 से40% तक पूर्व की तरह व्यवस्था होने लगी। स्वाभाविक है पूरे प्रदेश की 6 विंग की कमाई का 10 प्रतिशत हस्सिा सीधा हर महीने इन्हें भी मिलता है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने और ना मिलने पर अपील लगाने पर इस हरामखोर जालसाज ने पहले तो अपील की सुनवाई का पत्र नहीं दिया, जब यह खबर कर्मचारियों से मालूम पड़ी, सीधे मोबाइल पर, संदेश भेज कर तारीख बढ़वाई गई। जिसमें 13 जुलाई तारीख 12:00 का समय दयिा। नियत समय पर पहुंचने के बाद में भी बंदा सुनवाई के लिए नहीं आया और अपीलकर्ता अजमेरा को इंतजार करवाने के बाद भी सीधा बाहर निकल गया अपील सुनवाई नहीं की। और अगले दिन नरिस्ती का आदेश जारी कर दिया। जबकि जीएसटी में किसी भी प्रकार से जानकारी देने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। पर हरामखोरो ने अपने भ्रष्टाचार छुपाने अभी तक वेट के नियमों का पालन किया जा रहा है।

सभी राज्य सरकारें यह जानती थी की जीएसटी लगने के बाद उनके राज्य में राजस्व की भारी कमी आने वाली है। परंतु वे मोदी की ब्लैक मेलिंग चमकाने धमकाने के कारण उसके इशारे पर नाचते हुए उन्होंने जीएसटी को स्वीकार किया। इसके साथ ही जीएसटी को शीघ्र लागू करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने पुराने कर बकायादारों, व्यापारियों,फर्मों, देसी विदेशी, बहुराष्ट्रीय कंपनी तक को स्व कर निर्धारणो, एकमुश्त और डीम्ड योजना के अंतर्गत गजट नोटिफिकेशन कर बकायादारों को जानबूझकर कम से कम रु 5हजार करोड़ की वसूली जो सन 90-95से पेंडिंग थी। ओने पोने कर छोड़ दी गई। जिसका भरपूर फायदा यहां बैठे निरीक्षक, कर सहायक, सहायक, वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, अपर आयुक्त, आयुक्त से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी भरपूर उठाया। यहां बैठे कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी तोड़ बट्टा कर मोटी रकम कमाई, ज्यादा भारी फाइलों में वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त तक ने तो मोटी कमाई की है, परंतु सबसे ज्यादा धन कमाने वालों में कर सलाहकारो और दलालों ने मोटी चांदी काटी और इस बीच लेन देन कर अरबों रुपए की फाइलें गायब हो गई या जला दी गई। जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। यही हाल बिना टेंडर बुलाए रद्दी बेचने के नाम पर भी अरबों रुपए की वसुली की फाइलों व्यापारियों से मिलकर और लेनदेन करके फाइलों को रद्दी में बेच दिया गया।

विभाग में पदोन्नति परीक्षा होने की संभावना है। जिसमें जिन कर्मचारियों के पास डिग्री है। उन्हें 3 साल और जो हायर सेकेंडरी पास हैं उन्हें 5 वर्ष बाद पदोन्नति परीक्षा में बैठने की पात्रता दी जानी चाहिए ताकि विभाग को अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध हो सके।

जब सरकार ने 90% खाते स्व कर निर्धारण,और डीम्ड असेसमेंट में डाल दिए, तो फिर वसुली की लयि लगाई सभी टैक्सियों को हटा दिया जाना चाहिए था। परंतु इसके विपरीत टैक्सियों के बिल भारी बढ़ाकर भुगतान करने का जो कि प्रदेश मे करोड़ों रुपए का बिल हर महीने का होता है का भुगतान कैसे और क्यों किया जा रहा है।

आखिर उन टैक्सियों का कहां क्या उपयोग किया जा रहा है जबकि ब्यूरो के छापे मारने ट्रक पकड़ने आदि,के काम पूर्ण तरह से 1 जुलाई के बाद से बंद है। व सीधी वसूली के काम पर पूर्ण तरह से रोक है। स्वाभाविक है, बिना काम के कर्मचारी अधिकारी उन टैक्सियों का अपनी मौज मस्ती में उपयोग कर रहे हैं। वैसे तो अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी जो ब्यूरो में बैठते हैं अधिकांश समय काम ना होने के कारण गायब ही रहते हैं। जो आते हैं वह छोटे-मोटे काम कर करके खाली बैठे रहते हैं। वैसे यह विंग अपनी अवैध वसूलीओ के लिए कुख्यात रही है। जनवरी 17 तक इस विंग में बैठने के लिए कर निरीक्षक से लेकर, सहायक, वाणिज्य कर अधिकारी सहायक आयुक्त, उपायुक्त तक लाखों रुपए खर्च कर यहां नियुक्ति पा पाते थे।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर वाणिज्यकर के मुख्यालय में बैठे घोर धूर्तो और मक्कारों की फौज वैसे तो सूचना अधिकार के आवेदन देख कर ही भारी नाक मुंह सिकोडती है, फिर अगर आवेदन ले भी लिया, तो वहां बैठा लोक सूचना अधिकारी कारपेंटर जो की लाइन अटैच किया गया है। सीधा आवेदन के जवाब में लिखकर भेजता है, की आवेदन का जवाब और जानकारी देना आवश्यक बाध्यता नहीं। धारा 6(3) के अंतर्गत, उस पत्र को मुख्यालय से भी संबंधितों को अंतरित नहीं किया जाता। अर्थात पूरा विभाग हमारे बाप की जागीर है, और हम कुछ भी करें, भ्रष्टाचार करें, लूटपाट करें, कानूनों की आड़ में, व्यापारियों उद्योगपतियों से वसूली करें, जनता को उसकी जानकारी देना या नहीं देना यह हमारी मर्जी पर है, क्योंकि कानून हमारी रखैल, हमारी मर्जी का है। आश्चर्य तब होता है कि मुख्यालय में ऐसे बदतमीज,घोर, निकम्मे, अधिकारियों को आयुक्त की नाक के नीचे बैठा रखा है। वही हाल विभाग के संचालक पद पर बैठे एन एस मरावी यह भी घोर धूर्त और भ्रष्ट जिसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्वयं विभाग ने प्राथमकिी लिखवा दी थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई और निलंबन के साथ अभी तक उसे विभाग से बाहर कर देना चाहिए था। उसे संचालक पद पर इसीलिए बैठाकर रखा गया है ताकि उससे भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारी आसानी से मनमर्जी से काम करवा सकें। और संचालक के पद की औपचारिकता की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यही कारण है, कि वह हरामखोर जालसाज सूचना के अधिकार में अपील लगाने पर यहां तक की स्वयंभू बिना कानूनी कार्रवाई किए, अनावेदकों से अपील के जवाब मांगे बिना अनावेदकों को बिना अपील में बुलवाए, स्वयं ही अनावेदक की तरफ से पैरवी करते हुए सारी अपील ही रद्द कर देता है।शायद उसकी बदतमीजी और निकम्मेपन का ही उसको पुरस्कार देकर संचालक बनाया गया है। इस प्रकार इस कानून का अपने भ्रष्ट अधिकारियों और स्वयं के भ्रष्टाचार को बचाने मजाक बना दिया है।

मुख्यालय में संचालक मरावी के पड़ोस में बैठने वाले अपर आयुक्त राजेश बहुगुणा भी हर अपील के जवाब में अपने संचालक मरावी को अनुसरण करते हैं और उन्हें भी उन्होंने भी हर अपील को सुनने के बाद उसी के अंदाज में भारी निरर्थक दलीलें देते हुए अंत में निरस्त कर दिया। वैसे बहुगुणा जी का भी अपना इतिहास रहा है इसीलिए उन्हें किसी जिले की कलेक्टरी नहीं सौंपी गई और यहां पर यथार्थ में लाइन अटैच करके रखा गया है। 1 अप्रैल से ई वे बिलिंग शुरू होने से प्रदेश की 6 एंटी इवजन में चार पल वापस शुरू हो चुकी है विंग में चहल पहल वापस शुरू हो चुकी है और ट्रकों का पकड़ना प्रारंभ कर दिया गया है क्योंकि अभी व्यापारी यथार्थ में शासन की इन नीतियों को बारीकी से समझ नहीं पाया है इसलिए मात्र एक परसेंट ट्रकों में ही बिलों की गड़बड़ी पाई गई धीरे-धीरे विंग पुनः अपने पुराने तरीके से काम करने ढर्रे पर लौट आएगी और इस प्रकार ट्रांसपोर्टरों से सेटिंग होगा बिना बिलों के माल का अरबों रुपए का अंतरराज्यीय व्यापार चलेगा। इस प्रकार फिर मंत्री संत्री लोकायुक्त आयुक्त आदि सब का करोड़ों का महीना पुनः शुरू हो पाएगा।

दूसरी तरफ इस सूचना अधिकार को लगे हुए 13 साल गुजर गए परंतु अभी तक धारा 4 के अंतर्गत 17 बिंदुओं की जानकारी विभागीय साइट पर लोड नहीं की गई। जबकि सूचना के अधिकार के नाम पर इस विभाग में पूरे मध्यप्रदेश में करोड़ों रुपए हजम कर लिए गए। आखिर मुख्यालय पर बैठे वाणिज्य कर आयुक्त, विभागीय कर्मचारी अधिकारी कर वसूली के लिए तो नोटिस भेजना, कर न मिलने पर जब्ती करना, व्यापारी की संपत्ति नीलाम करना।आदि सब कुछ करते हैं। परंतु सूचना अधिकार मैं जानकारी देने के नाम पर बदतमीजी, कानून को मजाक बनाने की चालबाजी और जालसाजियां यहां देखी जा सकती हैं। **शेष पेज 4 पर**

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों के लिए सूचना अधिकार कानून मजाक

जनधन बाप की जागीर, काहे का सूचना का अधिकार, कैसा जवाब

घोर भ्रष्ट, जालसाज, सत्ता को बाप की जागीर मानने और कानून भी प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों की रखैल

भारत में सत्ता के असली खुदा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। जो घोर मक्कार , धूर्त, चालाक और महा भ्रष्ट होते हैं कानून उनकी रखेल होता है। चाहे वह संसद में कानून बनाने से लेकर विधानसभाओ मैं कानून बनाने, लागू करने और उसे राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाने के काम से लेकर जिला पंचायत तक में उनका साम्राज्य रहता है। ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रीयो, मंत्रियों को अपनी कठपुतली बनाकर अंगुलियों से नचाते रहते हैं। यह जैसा चाहते हैं वैसा ही मुख्यमंत्रियों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नाचना और करना पड़ता है। बेशक यह सबसे ज्यादा न्यायालयों से मुख्य रूप से जिला और सत्र न्यायालय से बहुत डरते हैं परंतु उच्च व सर्वोच्च न्यायालय को भी ये यह खास कुछ नहीं समझते जैसा चाहते हैं वैसा उच्च और सर्वोच्च न्यायालय से अपनी इच्छा और जरूरत के हिसाब से करवा लेते हैं। यह किसी बड़े पूंजीपति से ज्यादा धनाढ्य, काले धन के स्वामी और सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं का विदेशी बैंकों मैं पढ़ा होता है। कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां न्यायालय से पूर्व व पश्चात जमीन व राजस्व के मामलों में यही उड़ाते हैं और उसके बदले में करोड़ों रुपए हजम कर जाते हैं। सत्र वा जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर अधिकांश मामले देखते सुनते व निर्णीत करते हैं। जबकि यह सब तहसीलदार सहायक उप व जिलाधीश रहते हुए लगभग 400 से ज्यादा कानूनों में निर्णय करने की पात्रता रखते हैं। जबकि स्वयं कोई कानून की डिग्री या किसी शिक्षण संस्थान से कानून के स्नातक शिक्षण योग्यता धारी नहीं होते। परंतु 400 से ज्यादा कानूनों में अपने निर्णय से मोटी कमाई करते हुए सत्ता को हाँकते हैं।

सोमवार दिनांक 18 जून 18 को मैं इंदौर के जिलाधीश निशांत वरवड़े के सामने खड़ा हुआ था मेरी सूचना के अधिकार की जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी व जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के विरुद्ध दो अपीलो की सुनवाई करनी थी । परंतु मेरा नाम पुकारा जा चुका था। और मेरे पहुंचने में 2-3 मिनट का विलंब हो चुका था। पिछले 10 सालों से, मेरी सूचना का अधिकार की अपीलों की सुनवाई सबसे पहले रखी जाती है ताकि दुसरे पक्षौ में चल रही दूसरी कार्रवाई को देख व सुन ना सँकु। मेरे बाद जिन लोगों की सूचना के अधिकार में अपीलें लगी हुई थी।

कलेक्टर निशांत वरवड़े नेअपने बाबू को धमकाते हुए बोला सब की अपील रिजेक्ट कर दो और जाने दो इन्हें अयोग तक। क्योंकि जिनके विरुद्ध अपीलें लगाई गई थी इस में अधिकतर से कलेक्टर को भी महीना मिलता है।

अधिकांश आदिम जाति कल्याण विभाग की थीं। जिसकी पिछले 30 सालों की छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण मैं हुए भ्रष्टाचार के बारे में अनेकों बार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ अनेकों जांच लंबित होने के उपरांत भी वहां पर बैठे कर्मचारी और अधिकारी कागजो पर चलने वालों से लेकर 1-2 कमरे में चलने वाले फ़र्जीप स्कूलों कॉलेजों मे फर्जी छात्रों के नाम से करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति के घोटालों से भरा हुआ पड़ा है इसकी जांच पूर्व् के कलेक्टरों ने भी हजारों शिकायतों के बाद भी नहीं की। तात्कालीन भी यही कर रहे हैं। क्योंकि इस इस फर्जीवाड़े में सभी का हिस्सा होता है। इसी इसी फर्जीवाड़े मे छात्रवृत्ति के दम पर पूरे देश में लाखों स्कूल व कॉलेज संचालको अरबों रुपए की संपत्ति की कमाई की है। यह किस्सा इंदौर का ही नहीं, देश और प्रदेश के हर जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण के 3 विभागों के जहां पर हर वर्ष लाखों करोड़ के ऐसे भ्रष्टाचार खुलकर किए जा रहे हैं और सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर, इसी तरह से तीनों विभाग जानकारी देने के नाम पर अभी तो तुमको परेशान करते हैं हर जिलाधीश अपील को खारिज कर देता है। यही हाल खनिज, शिक्षा, महिला बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आदि विभागों के हैं। जहां से जिलाधीश को भी मोटा महीना मिलता है। जबकि छोटे जिलों में जैसे धार देवास उज्जैन व अन्य अधिकांश जिलों में वहां का जिलाधीश स्वयं ऐसी अपील न सुनकर, इन अपीलों की सुनवाई को अपने सहायक व उप जिलाधीशों को सौंप देता है जबकि हरामखोरों की फौज ऐसे अधिकारियों से मोटी वसूली कर जानबूझकर अपील की सुनवाई की सूचना के पत्र जारी कर रख लेते हैं और जब अपील का दनि व समय निकल जाता है । तब इसकी सूचना आवेदक को दी जाती है ऐसी हालत में अपील की सुनवाई में नहीं पहुंच पाता है तो आसानी से उसे खारिज कर दिया जाता है। यही हाल अधिकांश जिलों के जिलाधीश व संभागीय कार्यालयों में पिछले कई सालों से अपने अधीनस्थों को बचाने व भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किया जा रहा है। छोटे जिलों में तो अधिकांश विभागों में जिलाधिकारी को ही जिसमें कृषि विभाग, ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग, जिला पंचायत आदि में लोक सूचना अधिकारी को ही अपीलीय अधिकारी बना दिया गया है और उनके अधीनस्थ बाबू को अधिकारी बनाकर सूचना अधिकार का मखौल उड़ाते हुए जिम्मेदारी सौंप दी गई है जो धारा 19 का खुला उल्लंघन है जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी लोक सूचना अधिकारी होता है और उसका वरिष्ठ अधिकारी जो संभागीय स्तर पर बैठता है या जिलाधीश उसका अपीलीय अधिकारी होता था। इसे जालसाजी मंत्रालय स्तर पर बैठे हरामखोर जालसाज सचिव और प्रधान सचिव ने पूर्ण तरीके से बदल दिया गया। ताकि वह आराम से अपने अधीनस्थों सी महीना वसूलते हुए सारे भ्रष्टाचारों को छुपा सके। वैसे भी मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार जो ईमानदारी का पाखंड करती है। वह सूचना का अधिकार में जानकारी देखने व देने से हर अधिकारी को जानकारी ना देने के लिए मौखकि रूप से निर्देशित कर दिया गया है की जानकारी न दी जाए। इसलिए हर सरकारी विभाग का अधिकारी जानकारी ना देने के बहानों और भ्रष्ट उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के 4 से 8 पन्नों के दलीलों का अंबार लगा देता है। इसके लिए वकीलों को 10 से 20000 का भुगतान कर दिया जाता है परंतु जानकारी नही दी जाती। यह हाल के सभी विभागों का है। किसी भी विभाग जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर 90 से ज्यादा विभागों में किसी ने भी धारा 4 के अंतर्गत सारी जानकारी 13 वर्ष बाद भी अपनी साइट पर हजारों करोड़ हजम करने के बाद भी नहीं डाली जबकि इसका सबसे ज्यादा फायदा सरकार और उसके सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को ही होना था क्योंकि भेजने के नाम पर लाखों कर्मचारी और अधिकारी ही ज्यादा परेशान होते हैं। पर हर कदम फैले भ्रष्टाचार के कारण हर अधिकारी, विभागाध्यक्ष, सचिव प्रधान सचिव से लेकर मंत्री तक सब डरते हैं। फिर चुनकर आए मंत्रियों को 5 साल ही मिलते हैं लूटने हजम करने के लिए, यदि सब कुछ पारदर्शी और इमानदारी से होने लगा बेचारे मंत्रियों को सत्ता में आने का क्या लाभ मिलेगा।

बेशक इंदौर में ही नहीं हर जिले में कलेक्टर, जिला व अन्य अधकिारी, से लेकर् कर्मचारी बनने, मनचाही पदस्थापना पाने के लिए मोटी रॉयल्टी जो करोड़ों रुपए में होती है, हर महीने या एकमुश्त मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष को चुकाई जाती है। स्थानांतरण उद्योग पिछले 20 सालों से प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ का होता है। जसि समयमाया समाचार पत्र कई वर्षों से प्रकाशित करता रहा है। इसलिए जानकारियां कैसे दी जा सकती हैं । एक जिलाधीश, हर विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी सूचना के अधिकार के कानून का कैसी मजाक बनाता है। समझा जा सकता है। जनता से कानूनो का भय दिखाकर जिस प्रकार से लाखों करोड़ की हर महीने विक्रय कर, आयकर के नाम से लूट की जा कर और जनकल्याण के नाम पर यह मुख्यमंत्री, अपनी वाहवाही करवाने, चुनाव जीतने के लिए हजारों करोड़ के विज्ञापन दे, कभी नर्मदा यात्रा निकाली, कभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाले, फरि सारे अधिकारी जिस प्रकार से जन-धन पर डकैती डालकर पैसा हजम करते हैं आखिर क्या इनके बाप की जागीर है जो मन चाहे तरीके से कानूनों को ताक पर रखकर, उडायें खायें। कोई आवेदक जानकारी मांगे तो आंखें दिखाएं।

हजारों भ्रष्टाचार में लूट, अपने कुकर्मो को छुपाने, जनधन से चुनाव के लिए चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा

पेज एक से जारी

गरीबों की राशन आपूर्ति में हजारों करोड़ के घोटाले, म प्र वेयर हाउसिंग कारपोरेशन मैं हजारों करोड़ का अनाज जानबूझकर सड़ाया गया और फिर ओने पोने दामों में शराब कंपनियों को बेचा गया। 13 वर्ष में कोई विभाग ऐसा नहीं बचा जहां अरबों के घोटाले ना हुए हों। जसि समय माया, और प्रदेश के साप्ताहिक समाचार पत्र समय-समय पर छापते रहे है। पर शिवराज व उसके भ्रष्ट गिरोह के मंत्रियों के कानों पर कभी जूं नहीं रेंगी।

पिछले 13 सालों में वाणिज्य कर से प्राप्त कुल राशि का 70 से 80 परसेंट पैसा केवल सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कुकर्मो व भ्रष्टाचार को ढांकने, झूठे वादे करने, समाचार पत्रों और चैनलों का मुंह बंद रखने, अपने प्रचार प्रसार मैं खर्च किया जाता रहा औसतन प्रदेश के बड़े दैनिक समाचार पत्रों को 3 से 5 पेज के विज्ञापन हर दनि बांटे जाते रहे। साथ ही ना केवल देश में पूरी दुनिया में अपनी वाहवाही और तारीफें छपवाने व प्रसार के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए टीवी न्यूज़ चैनल के साथ अमेरिका तक मे होर्डिंग लगवाई गई। नःसंदेह इसमें मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मध्यप्रदेश माध्यम मे बैठे भारतीय प्रसारण सेवा के अधिकारियों ने हर वर्ष सैकडो करोड़ की कमाई की। जिसमें भ्रष्ट भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी मनोज श्रीवास्तव, सुलेमान खान, विवेक अग्रवाल, राकेश श्रीवास्तव, पी नरहरि सभी शामिल हैं इसीलिए यह हरामखोर जनसंपर्क विभाग पिछले 13 सालों में कभी भी सूचना के अधिकार में ना तो जानकारी दे सका और नहीं धारा 4 के अंतर्गत कोई जानकारी साइट पर अपलोड की गई वहां पर छोटी समाचार पत्रों को 50 से 70% कमीशन पर विज्ञापनों की अंधों की रेवड़ी बांटी जाती रही। हर वर्ष इस प्रकार रु. 50 से 70 हजार करोड जनधन के बर्बाद किए जाते रहे और सरकार चलाने के लिए बाजार से कर्ज उठा कर कर्मचारियों का वेतन बांटा जाता रहा।

निवेश के नाम पर विदेश यात्राओ मै स्वयं का निवेश किया, विदेशों में होटले खड़ी की, घूमे फिरे मौज मस्ती की और विदेशी निवेश के नाम पर भारी भरकम यूरोप के समाचार पत्रों में टीवी न्यूज़ चैनल पर विज्ञापन बांटे जाते रहे और अपनी ब्रांडिंग की जाती रही। जसिमे हजारों करोड जनधन के बर्बाद किये गये।फिर भी विदेशों से एक भी उद्योगपति मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने नहीं आया। चारो तरफ भ्रष्टों को सरंक्षण दिया, प्रदेश को अपराधो का प्रदेश बना दयिा।

जब ज्यादा हल्ला मचने लगा, कभी विकास यात्रा, किसान यात्रा, कभी नर्मदा यात्रा, आशीर्वाद यात्रा निकाल कर, कभी रोजगार मेला, विद्युत बिल माफी योजना मेला, जिसमें हजारों करोड़ जनता इकट्ठे करने, भ्रमित करने, अपनी मिट्ठू मियां बनकर तारीफ करने की आयोजनों में बर्बाद किया गया उपलब्धियां रहीम 13 साल की।हर वभिाग में भ्रष्टाचार के कांडों का अंबार। अब चुनाव आने पर इन सारे कुकर्मों को छुपाने दवाने सैकड़ों करोड खर्च कर फिर बेशर्मी के साथ हरामखोर, जालसाज जनधन के रथ पर सवार हो जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकल पड़ा।

अपने 13 वर्ष के अपने बेमिसाल शासन में शक्ल से देहाती भोले दिखने वाले इस मुख्यमंत्री शिवराज ने सैकड़ों जालसाजीयों से हर विभाग में हजारों करोड़ भ्रष्टाचार में धन कमाया, फिर चाहे वह महिला बाल विकास हो जिसमें आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए खाद्य सामग्री आपूर्ति के नाम दिए गए ठेकों मे, रेशम संचानालय, खाद्य आपूर्ति, आदि विभागों जिनकी चर्चा बहुत मुश्किल से समाचार पत्रों में आई। फरि वैध अवैध रेत खनन मे तो चौहान का पूरे प्रदेश पर, खास तौर पर होशंगाबाद, हरदा, सीहोर जिलों में तो खानदानी नर्मदा नदी के किनारों से रेती निकालने मे एकाधिकार रहा जिसमें हजारों करोड़ की कमाई की गई और जिसने भी मुंह खोला उसके खिलाफ वैध अवैध सही तरीके से नेता, अभिनेता, पक्ष के विपक्ष के सभी को परेशान किया गया। पर बंदे ने रेती निकालना बंद नहीं किया। भले ही कानून बदल दिए गए। खनन माफिया राजेंद्र शुक्ला, नरेंद्र सिंह तोमर, व अन्य कई भाजपाई विधायक सब इस खेल मे सत्ता का सुख भोगते हुए मोटी कमाई करते रहे। पर अवैध खनन जिसमें रेती से लेकर, बॉक्साइट, मैगनीज, पन्ना छतरपुर में हीरो तक का अवैध उत्खनन लगातार चलता रहा। दूसरी तरफ विद्युत जिसमें विद्युत मंडल को तोड़कर बनाई गई 5 कंपनीयो का उद्देश्य यही था की बिजली के नाम पर एक तरफ खरीद और बिक्री में हजारों करोड़ का, तो दूसरी तरफ जनता को 10 गुने से 50 गुना तक ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉनिक मीटरो से ज्यादा रीडिंग दिखाकर सैकड़ों गरीबों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, दूसरी तरफ अंट-संट बिलिंग से भारी मोटी कमाई की गई बिल जमा न कर पाने के चक्कर मेंहजारों लोगों को हर साल जेल पहुंचाया गया। और जब चुनावी साल आया तो अपने पाप धोने गरीबों को रु200/- प्रतिमाह का लालच देकर मुंह बंद कर पुनः सत्ता हथियाने की कोशिश की जा रही है। भावांतर के नाम भी एक तरफ बड़ी कंपनियों और मोटे पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए ताकि वह आसानी से किसानों का माल सस्ते कीमतों मे खरीद कर सके। और बदले में मोटा कमीशन हजारों करोड़ में मुख्यमंत्री के पास चुनावी चंदे के रुप में पहुंच जाएं तो दूसरी तरफ किसानों को भाव के अंतर की राशि देकर उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि भाजपा उनकी सबसे बड़ी हितैषी है और इस प्रकार प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को छला गया।हर विभाग की भ्रष्टाचार और जालसाजी की कहानी का एक परसेंट ववरिण छापने के लिए भी कई महाभारत जैसे ग्रंथ लिखने पड़ेंगे तो भी बारीकी से पूरा सच नहीं लिखा जा सकेगा जिसे जनता अगर समझ ले तो यह दिग्गी दानव का भी बाप निकलेगा। वित्तीय भ्रष्टाचार और लूट के तांडव को अगर त्याग भी दयिा जाए। तो भी कुछ मामलों में जिसमें शिक्षा, विद्युत, सड़कों जो अधिकांश बीओटी के ठेकेदारों को दोगुनी, चौगुनी लागत पर स्तर और सुरक्षा हीन सड़के सरकार की गारंटी पर गिरवी कर दी गई है, और करने के बाद हर वर्ष टोल दरें 7% बढ़ाकर जनता को लूटा जा रहा है, वनों को उजाड़ना, भूमाफियाओं कालोनी माफियाओं की लूट में, अपराधो, लूट डकैती चोरी हत्या, बलात्कारो, साइबर क्राइम, आदि में शिवराज की शरण में खूब फल रहे हैं और देश विदेश में मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

मध्यप्रदेश में कोषालय अधिकारियों द्वारा स्टांप वेंडरों से अवैध वसूली और परेशान किया जाना

मध्यप्रदेश में पिछले 5 वर्षों से शासकीय गैर न्यायिक मुद्राकों जो संपत्तियों की खरीद बिक्री से लेकर शासकीय शुल्क अदा करने अनुबंध करने व अन्य कई कार्यो में शासकीय शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रकार की बदतमीजी और तानाशाही के चलते धीरे धीरे रु.10000, 5000, 2000, 1000, से हटाकर मात्र रु.100, 50, 10, 5/- के ही बैंचें जा रहे हैं।उसमें भी हर जिले के कोषालय अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा स्टांप वेंडरों को रु 10000 से ज्यादा का चालान नहीं भरने दिया जाता। और ना ही एक बार में10000 पर ज्यादा के 100 50 10 के इस स्टांप दिए जाते हैं साथ ही हर महीने हर स्टांप वेंडरों को पूरे मध्यप्रदेश में कोषालय कर्मचारी रुपए 2000 से ज्यादा हर महीने ऊपर से वसूलते हैं तब उन्हें जाकर कहीं महीने में दो बार रु 10000 के स्टांप देते हैं। इसके बाद में यहां के महाभ्रष्ट हरामखोर कर्मचारी और अधिकारी उनकी शिकायतों को लेकर उनके बारे में अख़बारों में भी छपवाते रहते हैं। यदि वे उन स्टांप को 10 का स्थान 15 में, 50 का स्टांप 60/-, में और 100 का स्टांप यदि 120/-, में बेचते हैं तो शिकायत होने पर और हंसाने के लिए शिकायत करवा कर उस आधार पर उन पर कार्यवाही भी करते हैं। यह तानाशाही दादागिरी और बदतमीजीयां केवल मध्यप्रदेश में ही सरकार द्वारा मुद्रांक पंजीयक एवं महानिरिक्षक द्वारा की व मोटी कमाइ के लिए करवाई जा रही है जबकि पूरे देश में सभी प्रकार की कीमतों के स्टांप हर राज्य में बेचे जा रहे हैं।

सरकार सबसे ज्यादा परेशान है तो 10, 50, 100, के मुद्रांक जो कि अनुबंध करने शासकीय फीस का भुगतान करने के साथ इन स्टांपस का प्रयोग सूचना के अधिकार में किए जाने के कारण हैं और यह महा भ्रष्ट घोर निकम्मी और जालसाज सरकार जिसने हर

विभाग में अरबों के घोटाले किए हैं जनता का पैसा लूटकर हजम किया है। साथ ही जन धन का उपयोग अपनी नाकामियों को छुपाने, के लिए अरबों रुपए प्रति माह के विज्ञापन समाचार पत्रों को बांटकर उनका मुंह बंद करने के लिए किया जा रहा है इन सब की जानकारियां सूचना के अधिकार में ना देनी पड़े इसलिए वह 10, 20, 50 और 100 के स्टांप भी स्टांप वेंडरों को सप्लाई नहीं करती। जबकि उसके बदले में जिसकी कीमत उसके एक परसेंट से ज्यादा भी नहीं होती और वह उससे सैकड़ों करोड रुपए कमाती है। जानबूझकर स्टांप वेंडरों को परेशान कर रु 10000 से ज्यादा का चालान नहीं भरने देती और सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार आपूर्ति करती है।जिसके लिए भी शासकीय कोषालय के कर्मचारी और अधिकारी हर स्टांप वेंडर को सारे दिन उलझाए रखकर रुपए 10,000 जमा करवाने के बाद भी 3-4 दिन से लेकर सप्ताह भर बाद स्टांप देती है। कोषालय अधिकारियों व मुद्रांक पंजीयकों द्वारा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो पूर्णता जालसाजियां करने के साथ बिना कार्यालय में आए देश विदेश के किसी भी कोने से संपत्ति खरीद बिक्री मध्यप्रदेश में कहीं भी किसी भी जमीन प्लॉट चल अचल संपत्ति की बिक्री को मध्यप्रदेश में किसी भी जिले में पंजीकृत करवा कर करोड़ों की जालसाजीयां की जा रही हैं, इसके साथ ही संपत्तियों की खरीद बिक्री में जो ऑनलाइन जालसाजी की जा रही है जिसमें यदि वास्तविकता में उसका अंकेक्षण किया जाए तो सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले निकलेंगे और यह पैसा विप्रो जिसने रुपए 20- 25लाख का सॉफ्टवेयर और 25करोड का हार्डवेयर 600 करोड़ में पूरे मध्यप्रदेश में आपूर्ति किया गया जानबूझकर सरकार इससे मामले को ऑनलाइन करके सारी अपनी सारी जानकारियों को दस्तावेजों से हटाकर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सहेज लिया गया। ताकि कोई भी जानकारी ठोस रूप में किसी को कागजों पर ना देखें और उनके हजारों करोड़ के घोटाले और जमीनों की खरीद बिक्री जिसमें शिवराज अमित शाह अन्य मंत्री, सभी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारीजिन्होंने अवैध रूप से हजारों करोड़ की संपत्ति कृषि भूमि आदि खरीद रखी है किसी को मालूम ना पढ़ सके। उसके कागजी दस्तावेजों को जनता के सामने ना आ जाए इसलिए सारे काम को कंप्यूटराइज कर ऑनलाइन कर दिया गया जबकि ऑनलाइन में जो भयंकर घोटाले हो रहे हैं जो बीच में पकड़े भी गए जिसमें जमा राशि और उसके स्टंप के अंतर में करोड़ों रुपए का घोटाला था दवा दिया गया

जब एंटी ईवेजन ब्यूरो 1 जुलाई से चुपचाप बैठे हैं तो टैक्सियों पर हर महीने लाखों के भुगतान क्यों? पेज 2 से जारी

जब विभाग में सीधे वसूली के अधिकार नहीं, जब्ती के अधिकार नहीं, ऊपर से स्व कर निर्धारण, डीम्ड योजना आदि की के अंतर्गत ही सारे करो के भुगतान किए जा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में टैक्सियों की क्या उपयोग किया जा रहा है जिस पर शासन के करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष बर्बाद किए जा रहे हैं। यह जानने के लिए जब लॉग बुक की कॉपी सूचना अधिकार में मांगी गई तो हरामखोरों ने स्पष्ट लिख दिया कि हमारे यहां ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरी तरफ मुख्यालय में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे केवल गैलरी व लान में लगा दिए गए हैं। जबकि इन कैमरों को कमरो के अंदर भी लगाया जाना चाहिए था। ताकि अंदर का स्टाफ कमरों में बैठकर, वास्तविकता में कितना काम व क्या करता है, आगंतुकों वसूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वालों से किस प्रकार से बदतमीजी करता है। यह आसानी से रिकॉर्ड देखा जा सकता था। पर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया।हर विभाग में बढ़ती महिलाओ की संख्या, उनके 12 बजे आने और 4 बजे चले जाना के चलते, उनसे कोई भी वरिष्ठ पुरुष अधिकारी पूछताछ नहीं कर सकता, यदि पूछताछ करता है,या कहता है, तो उन पर आसानी से महिलाएं छेड़छाड़ का आरोप लगाकर डराती, धमकाती और ब्लैकमेल करने लगी है,जिससे कोई भी पुरुष अधिकारी कर्मचारी कुछ कहना बोलना, डर से पसंद नहीं करता।जबकि ऐसे वक्त कमरों में कैमरे लगाने से उनको अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए काफी मददगार सिद्ध होंगे।यह कहानी हर विभाग की है। कर्मचारी अधिकारियों की, देर से आना, जल्दी जाना, रिकॉर्ड के आधार पर आसानी से उनकी लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने में पुरुष अधिकारी कर्मचारियों को वीडियो रिकॉर्डिंग काफी काम देगी। वैसे तो पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रखैल, कमीशनखोर भुखेरा जन पार्टी की केंद्र सरकार, अधिकांश सरकारी कार्यालयों को, निजी क्षेत्र में देने के लिए सबका डेटा इकट्ठा कर रही है। और इस कार्य के लिए भी केंद्रीय महालेखाकार के माध्यम से हर विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों, कार्यपद्धती, कार्यक्षमता प्रति व्यक्ति कार्य और उसकी लागत आदि का डाटा इकट्ठा कर, मोटे कमीशन पर यह भी निजी कंपनियों को ठेके पर देना चाहती है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह कार्य पूरे देश के वाणिज्य कर या विक्रय कर विभाग में दिल्ली से आए केंद्रीय दल जोकि महालेखाकार विभाग के थे हर प्रदेश के कर मुख्यालय में जाकर वह पूरा डाटा इकट्ठा कर रहे थे। जैसा कि जनधन से निर्मित रेलवे के स्टेशनों को, सफाई कार्य को, इस बगरा जन पार्टी की सरकार न अरबों रुपए का मोटा कमीशन लेकर ठेके पर निजी क्षेत्र में दे दिया जिससे जनता को हर कदम पर काम करने वाले ठेकेदारों की लूट का सामना करना पड़ रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर निजीकरण के बाद रु5/- की पार्किंग रू25/- में वसूली की जा रही है।वही हाल शीघ्र ही वर्तमान हालातों को देखते हुए वाणिज्यकर में भी होने वाला है। इस विभाग को भी सरकार ठेके पर देकर यहां से भी मोटे वेतन पर काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की इन की हरामखोरी को देखते हुए विदाई कर देगी। जैसा कि वर्तमान गतिविधियों को देखते हुए निष्कर्ष सामने आ रहे हैं। वैसे यहा कई भ्रष्ट बड़े अधिकारी 5 बरसों से ज्यादा समय से ही कुंडली मारे बैठे हुए हैं। इसमें एक नाम उपायुक्त अब्दुल मजीद का भी है।जो कि विवाह के पास अफीम गोदाम की जमीन होने के बाद में भी वहां पर वर्णिका का भवन नहीं बनने दे रहा। इसके विपरीत शासन का वाणिज्य कर विभाग 11 मंजिला बिल्डिंग में करोड़ों रुपए प्रति वर्ष का किराया जरूर चुका रहा है क्योंकि उसमें मोटा कमीशन चेतक चेंबर के मालिक से मिलता है।इसलिए उसकी किराए की बलि अनुबंध की कॉपी, सूचना का अधिकार में आज तक मुझे नहीं दी गई। धारा 6(3) के अंतर्गत भी किसी भी आवेदन को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को नहीं पहुंचाता। इसके बदले में मोटा महीना अपना अधिकारियों से वसूल कर लेता है। रुपए 40 करोड़ से ज्यादा का भुगतान पिछले 11 सालों में चेतक चेंबर के मालिक को कर दिया गया जबकि इस धन में आसानी से शासन के पास पड़ी भूमि अफीम गोदाम की भूमि में एक विशाल कार्यालय बनाया जा सकता था जो कि स्वयं विभाग का होता। पर मोटे कमीशन के चलते इस भूमि का उपयोग जानबूझकर नहीं किया जा रहा है उसके चारों तरफ नेताओं के पठ्ठों ने भूमि पर अतिक्रमण कर किसी ने रिपेयरिंग शॉप तो किसी ने चाय की होटल व अन्य प्रकार की दुकानें खोल रखी है जिसे शासन आंख मीच कर देख रहा है।

निजी क्षेत्र में वाणिज्य कर विभाग में मंत्री से लेकर निरीक्षक तक कोई भी ईमानदारी से काम करने को तैयार नहीं सब को पैसा चाहिए। जो जतिनी बड़े पद पर बैठा हुआ है। उसको ऊतना बड़ा धन चाहिए। जीएसटी लगने के बाद से ही सारी ऊपरी कमाई बंद हो गई। स्वाभाविक था यदि निरीक्षक क रुपए 30 40 हजार का नुकसान हुआ, तो सहायक वाणिज्य कर अधिकारी का लाख रुपए का, वाणिज्य कर अधिकारी का 1.50 से रु2लाख, सहायक आयुक्त का रु3-5लाख का, उपायुक्त का रुपए 10 से 20लाख प्रतिमाह का तो आयुक्त का 5 से 10 करोड रुपए, तो मंत्री व प्रधान सचिव का रुपए 50 से 100 करोड़ प्रतिमाह का नुकसान हुआ। यही कारण है कि अब मंत्री वाणिज्य कर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं उनकी कमाई का स्त्रोत मुख्य रूप से आपकारी की कमाई से है।वर्तमान में क्योंकि वाणिज्य कर विभाग में कोई कमाई का स्त्रोत नहीं रह गया।सारा काम ऑनलाइन हो जाने से यथार्थ में वाणिज्य कर विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों के पास पुरानी वसूली करने, प्रकरंणो को निपटाने फाइलो को खत्म करने कहीं काम शेष रह गया है। इसे धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है। जिसे सरकार जानबूझकर पुराने रिटर्न फाइल करने की तिथि बढ़ा बढ़ा कर लटका रही है यह उसी के लिए घातक हो रहा है। दूसरी और जीएसटी लगने के बाद यथार्थ में सरकार के खाते में बहुत कम धन की प्राप्ति हो रही है जबकि जीएसटी के भुगतान के दोहरीकरण की प्रणाली में मध्यसथ सारे व्यापारियों को जिन्होंनदूसरी तीसरी और चौथी क्रम पर जीएसटी का भुगतान कर दिया है उन्हें पूरा जीएसटी वापस लौट आना है जबकि केंद्र व राज्य सरकार के पास वर्तमान में नियमित खर्च चलाने वेतन बांटने के लिए भी पैसे नहीं है। और केंद्र और अधिकांश राज्य सरकारे बाजार से कर्ज उठाकर कर्म कर्मचारियों अधिकारियों को वेतन बांटने के साथ नियमित्त खर्चे चला पा रही है। निसंदेह उत्पादक, व्यापारी, कंपनियां, इसका भरपूर फायदा उठा रही है। इ वे बिल की व्यवस्था जो सरकार ने फरवरी शुरू करने की कोशिश की थी पहले दिन ही केंद्र व राज्य सरकारों के ढीले और कमजोर सरवर के रहते तहस-नहस हो गई थी। सरकार ने पुनः इसे 1 अप्रैल से लागू किया तब तक व्यापारी, विक्रेता, उत्पादकों ने इस व्यवस्था की बारीकियों को पहचान कर चालाकियों सेरु 50000 के बिलों को टुकड़ों में तोड़ कर बनाना शुरु कर दिया ताकि वह इ वे बिलगि की कंप्यूटराइज व्यवस्था से बचे रहें। इसके चलते सरकार में व्यापारियों को 4 अप्रैल को नगद भुगतान की सीमा 20000 से घटाकर रु.10000/- कर दी।इस तरह से सरकार ने छोटे व्यापारियों, उत्पादकों के व्यापार कौ हर तरह से चौपट करने का प्रयास किया।

नोटबंदी के बाद वैसे भी पूरा भारत का उद्योग धंधे और व्यापार चौपट पड़ा हुआ है भारी बेरोजगारी और मंदी का पूरे देश में माहौल है पर इस धूर्त मक्कार मोदी को चुँकि सभी बड़ी कंपनियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा कमीशन मिल रहा है इसलिए उसे देश के घटते मरते उद्योग व्यापार और बढ़ती बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं। जबकि उसकी नोटबंदी और जीएसटी ने पूरे देश को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया।

क्षे.ग्रा.स.वि.प्रा का कार्य पूरा बंद करो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा पूरा प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर जोड़ा

मुकाअ से लेकर सभी मुख्य व महाप्रबंधक घोर जालसाज

सूचना अधिकार में जानकारी मांगने पर साफ मना कर देते हैं। इंदौर के घोर बदतमीज मुख्य महाप्रबंधक श्रीवास्तव हर आवेदन पत्र में एक ही जवाब प्रश्नात्मक जानकारी नहीं दी जाएगी। सभी इंजीनियर दूसरे विभागों के जिन्हें सड़क निर्माण का अनुभव नहीं। अँदाज लगा सकते हैं कि काम कैसा चल रहा है।

पूरा क्षेत्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सड़क योजना का मध्यप्रदेश में काम देख रहा है पूरे प्राधिकरण में सारे उपयंत्री सहायक यंत्री जो प्रबंधक कार्यपालन यंत्री जो महाप्रबंधक के नाम से पुकारे जाते हैं। इंजीनियरों को यथार्थ में सड़क बनाने का कोई और खास अनुभव नहीं है। सभी विद्युत विभाग, उद्योग, जल संसाधन, लोक-स्वास्थ्य-यांत्रिकीय, ग्रामीण यांत्रिकीय, आदि के वे कार्यरत यंत्री होते हैं जो अपने विभाग में नकारा और निकम्मे माने जाते हैं। इनका मूल उद्देश्य उल्टे सीधे कम गुणवत्ता के कार्य संपन्न कर भ्रष्टाचार से धन कमाना व समय व्यतीत करना होता है। स्वाभाविक सी बात है अपने विभाग में कुख्यात होने के कारण प्रतिनियुक्ति पर इस सड़क विकास प्राधिकरण में आ जाते हैं। और खुलकर भारी भ्रष्टाचार सड़कों के निर्माण और गुणवत्ता में किया जाता है सभी को यह मालूम है कि पकड़े जाने पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा उनके मूल विभाग में भेज दिया जाएगा। जैसा कि हाल ही में ही पकड़े गए इंदौर और उज्जैन के महाप्रबंधक चावला के साथ हुआ। जबकि उन्होंने इस प्राधिकरण में 15 वर्ष तक रहते हुए लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इकट्टी की। लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने पर वे अपने पुनः मूल वभिाग मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में भेज दिए गए। यहां पर आकर सभी उसी कार्यशैली से सड़क निर्माण कार्य संपन्न करते रहते हैं। वैसे भी इस प्राधिकरण का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण करना था। परंतु पिछले 18 सालों में निर्मित सड़कों का रखरखाव भी करने लगे। वैसे भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का धन पिछले 18 सालों से भारत में बिकने वाले पेट्रोल डीजल गैस व अन्य सेवाओं पर लगाए गए 2% उपकर से प्राप्त होता है। जो हर वर्ष लगभग सवा से ड़ेढ़ लाख करोड होता है। पूरे देश की ग्रामीण सड़कों के निर्माण में यही धन उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए अलग से केंद्र व राज्य सरकार को धन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती इसके विपरीत इस धन का सदुपयोग जो कि ग्रामीण विकास के नाम पर सभी राज्य सरकारों को प्राप्त होता है। खुलकर दुरुपयोग किया जाता है। इसीलिए पेट्रोल डीजल पर लगा 2% उपकर का पैसा अब केंद्र व राज्य सरकारों को कम पड़ने लगा है। इसलिए इसमें अब यह प्राधिकरण एशियन विकास बैंक से भी ऋण प्राप्त कर सडकें बना रहा है। स्वभाविक है यह खर्च जनता के सिर पर लिया जा रहा है। इसका

इस प्राधिकरण की उपयोगिता पूरी हो चुकी है अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कमाई के लिए आते हैं काम के लिए नहीं

भुगतान राज्य सरकारों को भी करना पड़ेगा जबकि उपकर से प्राप्त धन पूरे देश में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए पर्याप्त था जबकि रखरखाव और पुनर्निर्माण का काम लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए था। स्वाभाविक है, अधिकांश धन ठेकेदारों के साथ मिलकर रखरखाव उपयंत्री से लेकर महाप्रबंधक मुख्य महाप्रबंधक से लेकर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ग्रामीण विकास के मंत्री तक भारी बंदरबांट होती है। सड़कों की गुणवत्ता जो 2010 तक पाई जाती थी। अब वह गुणवत्ता नहीं रह गई। अब घटिया स्तर का निर्माण रखरखाव व पुनर्निर्माण करने के बाद साल 2 साल में सड़कें खराब होने पर सुधार कार्य कर चलाया जाता है। यही कारण है सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने पर वर्तमान में बैठे भोपाल से आए घोर धूर्त महाप्रबंधक श्रीवास्तव ने पहले अपील निरस्त कर दी। वैसे भी पूरे भोपाल के मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी वभिागों के प्रशासनिक कार्यालयों से लेकर संभागीय व जिला स्तर के सारे हरामखोर अधिकारी इंजीनियर डॉक्टर जानकारी देने की अपेक्षा घोर निकम्मे मक्कारी पूर्ण कार्य करते हुए हर वक्त हर आवेदन में जानकारी ना देने की वहानों की सूची थमा देते है।

धर्म चार में यदि धारा 4 के अंतर्गत 17 बिंदुओं की जानकारी सूचना के अधिकार कानून लगने के साथ ही विभागीय साइट पर लोड करनी चाहिए थी मैं 13 वर्ष के बाद में भी अभी तक उस कार्य को पूरा नहीं किया गया क्योंकि सभी भ्रष्टों को डर रहता है क्योंकि सभी जानकारी अंकित सार्वजनिक हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार पिछले 5 सालों से घोषणा करती आ रही है उसका सारा कार्य पूर्ण रूप से कंप्यूटरइज हो चुका है। पूर्णता बकवास है।

यदि सचमुच धारा 4 के अंतर्गत सारी जानकारी यदि कंप्यूटर की साइटों पर लोड कर दी जाती तो 90 परसेंट आवेदन देने की जरूरत ही नहीं होती पर केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राज्य सरकारों के सभी विभाग जानबूझकर जानकारी साइटों पर लोड करना नहीं चाहते ताकि उन्हें भ्रष्टाचार करने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब यही बात आवेदन में जानकारी ना मिलने पर अपील में हर बार लिखी गई वर्तमान मुख्य महाप्रबंधक श्रीवास्तव ने स्वीकारा और कहा कि यह जानकारी जल्द से जल्द पूरी करवाई जाएगी। पर इसके बाद इस हरामखोर ने इस अपील को ही निरस्त कर दिया। यह भी प्रतिनियुक्ति पर वसूली करने आया है। काम तो बहाना है।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

मध्य प्रदेश कृषि विभागः ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों ने 24 दिन हड़ताल की

भ्रष्ट महानिकम्मे जालसाज मुमँ चौहान और प्रस राजेश राजौरा दिखाई बेरुखी

यह तथ्य भारत की अर्थव्यवस्था का आज भी महत्वपूर्ण है,की भारत की अर्थव्यवस्था पूर्णताः कृषि आधारित और उस पर निर्भर है।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 वें वर्ष भी कृषि कर्मणा पुरस्कार राष्ट्रपति से प्राप्त कर आए हैं। तो उसके पीछे सबसे ज्यादा मेहनत यथार्थ में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की होती है। जो कि ठंड, गर्मी, बरसात मैं भी सुदूर गांवों में रहकर किसानों को कृषि भूमि जोतने, बुवाई करने, उसे समय पर, खाद, बीज, कीटनाशकों को उपलब्ध करवाने, व उनका प्रयोग करने, निदाई-गुड़ाई करने आदि की जानकारी किसानों के बीच रहकर उपलब्ध करवाते हैं। किसानों को अच्छी से अच्छी बाराहमासी फसलें मिल सके। उसे भरपूर फसल प्राप्त हो। यही कारण है आज आम जन को 5 -10/- किलो मे प्याज आलू टमाटर व अन्य सब्जियां, सस्तीस दलहन, तिलहन, खाद्यान्न आदि इतने सस्ते और भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो पा रहे हैं। अर्थात कृषि विभाग में वास्तविकता में सबसे ज्यादा व सबसे बड़ी भूमिका ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ही निभाते चले आ रहे हैं । शासन की सारी योजनाओं विस्तार विकास ग्रामीणों को समझाने में यथार्थ में सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ही होता है। बाकी सब उसके ऊपर जिसमें वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी से लेकर सहायक संचालक, उपसंचालक, संचालक, सचिव प्रधान सचिव मंत्री और मुख्यमंत्री उस के दम पर ही सारी नौटंकी और दावे ठोक पाते हैं। यथार्थ में यह शासकीय कर्मचारी इस देश की आधारभूत उन्नति और विकास का कारण है। जिसे सर्वेयर जो कि भूमि सरंक्षण के बरसों से बंद पड़े होने के कारण अधिकांश समय जिला कार्यालयों में गुजार रहा है। से भी कम वेतन दिया जाना जो कि उससे कम वेतन प्राप्त करता था छठवें वेतनमान में वह उनसे आगे निकल गया इसके संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका में भी न्यायालय ने इन के पक्ष में फैसला दिया और ग्रामीण कृषि अधिकारियों को समान वेतन देने के लिए कहा गया परंतु जानबूझकर मुख्यमंत्री प्रधान सचिव ने इस कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जबकि केंद्र से प्राप्त होने वाले रुपए 40000 करोड़ से ज्यादा के बजट मैं से लगभग 8000 करोड रुपए बंदरबांट में यह हरामखोर प्रधान सचिव राजेश राजोरा जो पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से कृषि विभाग में बैठा है अनाप-शनाप 10 से 20 गुना ज्यादा कीमत पर बीजो जो कि मध्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता के तैयार होने के उपराँत भी यह भ्रष्ट प्रदेश के बाहर की कंपनियों से खास तौर से हैद्राबाद से खरीदी करवा कर किसानों को अनुदान के नाम पर उपलब्ध करवाया जाता है। जबकि किसान को वही बीज 25से 40% की कीमत पर बाजार में मिल जाता है। यही हाल जैविक खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण आदि में किया जा कर 4 से8हजार करोड़ हजम कर लिया जाता है। इसमें कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री का भी हजारों करोड़ का हिस्सा होता है।

जबकि इनके इस भ्रष्टाचार को दबाने छुपाने बाजार में सस्ता माल मिलने पर किसानों की गालियां इन्हें खानी पड़ती है। अभी भी कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय में म प्र के 60000 से ज्यादा गांवों मैं किसानों को बांटने के लिए जो साहित्य पड़ा हुआ है। उसकी 10 से 20% में छपाई की जा सकती थी परंतु 10 गुना ज्यादा कीमत मे छपवा कर इन्हें सौंप दिया गया किसानों को बांटने के लिए। अर्थात ये हजारों करोड़ भ्रष्टाचार में हजम कर जाएं। वह सब चलेगा। पर इन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनके भ्रष्टाचार में साल भर में 50 करोड़ों की कमी हो जाएगी। अब जबकि मानसून आ चुका है। किसानों के खेत खरीफ की फसल बोने के लिए तैयार है खाद बीज चाहिए और यह सब ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पिछले 23 दिन हड़ताल की पर उनकी मांगे पूरी नही की। अन्यथा स्वाभाविक रूप से किसानों को समय पर बीज ना मिलने से मध्य प्रदेश की पूरी खरीफ की फसल बिगड़ जाने की संभावना है इन सब की मांगों पर जानबूझकर मुख्यमंत्री शिवराज जो अपने आप को किसान का बेटा बोलता है पर ध्यान नहीं दिया। जब यह तथ्य भोपाल के पत्रकारों को छापने के लिए, व जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि को व्हाटसएप के माध्यम से ही रात्रि 12:30 बजे भेजा गया। इस पर सरकार नजर रखती है सरकार को मालूम पड़ते ही सरकार न उसी दिन ही कर्मचारियों का 25 दिन का वेतन न काटने की शर्त पर हड़ताल खत्म करवा दी बेशक संघ के सदस्यों को सरकार ने मोटा पैसा देकर मुंह बंद कर दिया बिना किसी आश्वासन और मांग को पूरे किए बिना।

इस हड़ताल के सहयोग में पूरे कृषि विभाग के संयुक्त संचालक से लेकर उपसंचालक संचालक व वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों ने भी 15 जून को सांकेतिक हड़ताल पूरे मध्यप्रदेश में की थी पर सरकार ने उनकी भी नहीं सुनी पर जब समय माया के श्री अजमेरा ने उपरोक्त तथ्यों को व्हाटसएप के माध्यम से चारों तरफ फैलाया तब सरकार ने कर्मचारी नेताओं को बुलाकर इस तरह से हड़ताल खत्म करवाई।

कृषि विभाग में वैसे तो घोर भ्रष्ट जालसाज प्रस राजेश राजोरा से लेकर नीचे तक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तक है तो सभी भ्रष्ट, और यथार्थ में किसानों की आत्महत्या के लिए भी जिम्मेदार। इंदौर में ही बैठाए संयुक्त संचालक सिसोदिया, जिन पर खरगोन में उपसंचालक रहते हुए किसानों को गर्मी में मूंग की फसल उगाने के लिए जो बीज दिया, बेच दिया गया था। की जांच का का नोटिस देने के बाद, प्रधान सचिव राजोरा ने मोटा धन लेकर ऐसे सभी पांचों उप संचालकों को संयुक्त संचालक बना दिया था। तब उ. सं. विजय चौरसिया, जिसे खरगोन में सहायक संचालक और भूमि सरंक्षण अधिकारी रहते हुए, अनेकों बलराम तालाब चोरी करवा दिए थे, तब इनके गुरु उ.सं. सिसोदिया हुआ करते थे। दोनों ने साथ रहते हुए खरगोन में खेत का पानी खेत में, बलराम तालाब, टपक सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर के लिए, पाइप लाइन, आदि में, अनुदान भुगतान और खरीदी में भारी भ्रष्टाचार किए, साथ ही चौरसिया ने वहां पर किसानों के सम्मेलन के लिए भोजन पर खर्च किए गए रु 6.50 लाख हजम करने का मामला आर्थिक अपराध में पंजीबद्ध है, दूसरा प्रकरण भी लोकायुक्त मैं पंजीबद्ध है। मुरैना से उपसंचालक रहते हुए निलंबित कर हटाया गया था। इंदौर में पदस्थ होने के बाद में भी शिकायत होने पर इनका स्थानांतरण भोपाल कर दिया गया था। परंतु सूत्रों के अनुसार चूंकि इंदौर में पूरे मध्यप्रदेश के खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण, पोली हाउस बनाने वाली कंपनियों के वितरक क्षेत्रीय कार्यालय होने के कारण, उनके पंजीयन, नवीनीकरण और पूरे मध्यप्रदेश में कृषि सामग्री आपूर्ति करने के लिए अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाण पत्रों के नाम पर मोटी कमाई होती है इसलिए इस भ्रष्ट धूर्त विजय चौरसिया ने रु30 लाख का मोटा भुगतान कर पुनः यहीं पदस्थापना करवा ली। अब जब गुरु चेले इंदौर में हैं, तो दोनों जालसाज हरामखोर एक दूसरे को संभाल और बचा के चलते हैं। यही कारण है जब भी सूचना के अधिकार में उपसंचालक कार्यालय के विरुद्ध अपील लगाई जाती है यह भ्रष्ट शूकर स.स. सिसोदिया सॉरी अपीलें नरिस्त कर देता है । ताकि इस भ्रष्ट चौरसिया की जालसाजियां जनता के सामने ना जाएं और सुनाओ कोई नया प्रकरण जिसमें दोनों लपेटे में आ जाएं ना शुरू हो जाए। वही हाल देवास, उज्जैन, धार, शाजापुर, खंडवा में, व पूरे प्रदेश में बैठे सभी उपसंचालकों का है। क्योंकि सभी घोर भ्रष्ट मोटी रायल्टी पर ही बैठाए गए हैं। इसलिए इस सरकारी डकैत गरीह को सभी वरिष्ठों का संरक्षण प्राप्त है।

वनों की जमीन, वृक्ष, व अन्य वन संपदा सब की वोटों की खातिर लूट और बर्बादी की पूरी छूट

वृक्षारोपण का नाटक और 53 प्रजाति के पेड़ों की कटाई की छूट

मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ हर वर्ष करोड़ों पेड़ लगाने का नाटक करती है। और जन-धन के प्रति वृक्ष सो रुपए के हिसाब से पिछले वर्ष 600 करोड़ रुपए और इस वर्ष 800 करोड़ रुपए न्यूनतम बर्बाद करेगी।

जबकि पिछले 13 वर्षों से मप्र का यह घोर धूर्त, भ्रष्ट और मिठबोला मक्कार मुमं शिवराज जो पिछले 13 वर्षों से 53 प्रजाति के पेड़ों की कटाई की खुली छूट दे रखी है। जिससे हर वर्ष 40 से 50करोड़ हरे भरे पेड़ कटाई की जा कर आसानी से ना केवल मध्यप्रदेश में वरन यहां के वृक्षों की 5 करोड टन इमारती लकडी पूरे देश में बेची जा रही है। यदि एक वृक्ष रु 25000 में भी बिका तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 करोड़ पेड़ों की कटाई से प्रतिवर्ष कितनी कमाई की जा रही है। जिसे समय माया ने हीं 5 वर्ष पूर्व भी उठाया था और यह मुद्दा गर्माते ही सरकार ने यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि आदेश फर्जी था । फर्जी था तो उसकी जांच क्यों नहीं की गई लकड़ी कटाई क्यों नहीं रोकी गई। जिसका पैसा मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों वन विभाग के प्रधान सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक या वनमंडलाधिकारी उप वन मंडल अधिकारी रेंजर वनरक्षक से लेकर बीट गार्ड तक उन 53 प्रजाति के पेड़ों की कटाई करवा कर मोटी अरबों करोड़ की कमाई कर वाले वाले ही हजम की जा रही है। इसका कड़वा सच इंदौर के प्रदेश के सबसे बड़े लकड़ी के टिंबर मार्केट में धार रोड पर और पूरे प्रदेश की सभी आरा मशीनों पर तत्काल के ताजे हरे कटे हुए पेड़ों की लगातार आवक से जाना जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार हर वर्ष इसीलिए जनता को दिखावे के लिए जनता के धन से ही 6 और आठ करोड़ छह प्रजाति के 8इंच से 2 फुट तक के पौधे लगाने का नाटक करती है। जबकि पिछले वर्ष लगाए गए छह करोड़ के 10% अर्थात 60 लाख पौधे भी वर्तमान में जीवित नहीं है। जो यह सिद्ध करता है की जनता का न्यूनतम 600 करोड रुपए भ्रष्टाचार में हजम कर लिया गया। यह है। वर्तमान की भुखेरा जन पार्टी की सरकार का सच।

दूसरी तरफ वोटों की खातिर, जानबूझकर पहले वन भूमि पर अवैध कब्जे करवाए जाते हैं, फिर उस भूमि पर कृषि, लघु उद्योगो और निवास के लिए पर पट्टे बांटकर, हर वर्ष हर जिले में हजारों हेक्टेयर भूमि वन विभाग की इस तरह भूमाफियाओं और जंगल माफियाओं से पेड़ कटवा कर हथिया ली जाती है जिस पर मामा पट्टी बांट कर लोकप्रियता के सहारे चुनाव जीतता है ।

जबकि हर माह हर बन मंडल को वृक्षों के रखरखाव के लिए हर रेन्ज की बीट और कूपे मे जल की व्यवस्था, कच्चे आने जाने के मार्गो की व्यवस्था, अग्नि से बचाव की व्यवस्था, वृक्षों कि देखभाल व वनों में साफ सफाई व अन्य कार्यों के लिए मजदूरों के भुगतान के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन प्राप्त होता है। उस आवंटन का 50% पैसा कागजो पर ही हजम कर लिया जाता है निसन्देह वर्तमान में अब यह पैसा संबंधित मजदूरों के बैंक खातों में जमा होने के कारण भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की गई है परंतु सरकार डाल-डाल तो कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार के लिए पात पात चलकर फर्जी खातों के माध्यम से भी पैसा निकाल कर हजम कर लेते हैं। फिर पैसा हजम करने के लिए बाले बाले वनोपज, पेड़ों की कटाई, वन भूमि पर चल रहे अवैध खेती से भी क्षेत्र का वनपाल वनरक्षक उपमंडलाधिकारी, वनमंडलाधिकारी वन संरक्षक से लेकर मंत्री तक सभी की मोटी कमाई होती है। अकेले इंदौर वन मंडल में रेंजर खुर्शिनद के पास 4 रेन्ज के प्रभार हैं। यही हाल पूरे मध्यप्रदेश का है।

घोर विवादास्पद व भ्रष्ट भा प्र अ अनुराग जैन पुनः प्रदेश में

प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत घोर भ्रष्ट भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अनुराग जैन जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में थे स्थानांतरित कर के दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ हुए किए गए थे वहां से भी धकिया दिया गया। तो पुनः प्रदेश के मुखिया के कार्यालय में लौट आये। यह भैया अनुराग जैन है जिसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से मोटा कमीशन खाकर पूरे प्रदेश के सभी विभागों के लाखों रुपए के सॉफ्टवेयर को सैकड़ों करोड में बनवाने का ठेका दिया था टीसीएस के बनाए हुए सारे सॉफ्टवेयर जिसमें मध्यप्रदेश कोष एवं लेखा, ई टेंडरिंग, लोक निर्माण विभाग आदि के सबसे ज्यादा विवादित सॉफ्टवेयर बरसों बाद बहुत ही परेशानी जनक बनाकर शासन को सौंपी गई। यह वही है जिन्होंने विद्यासागर मेडिकल कॉलेज के नाम पर भोपाल में शासन से जमीन लेकर और जैन समाज से मोटा सैकड़ों करोड़ में धन लेकर दिल्ली चले गए थे। ऐसे ही अनुराग जैन के बहुत सारे विवाद इतिहास में कुलांचे मार रहे हैं। इनकी कारण पूर्व में भी मुख्यमंत्री चौहान को कई बार विवादों में उलझना पड़ा। पर शायद मुख्यमंत्री को चुनावी वर्ष में अधिकारी को चुनावी वित्त प्रबंधन के लिए बुलाना पड़ा।

आखिर जनसंपर्क में क्या कर रहा आई पी एस

ससुर जी मुख्यमंत्री है तो वह एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को जो कि गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस विभाग में काम करने के लिए प्रदेश में नियुक्त किया जाता है। अपने दामाद को जो कि उनकी भतीजी वाणिज्य कर अधिकारी रीतु चौहान का पति है, को जनसंपर्क विभाग में अतिरिक्त संचालक बनाकर भोपाल में नियुक्त कर दिया। जहां पर यथार्थ में ससुर जी अपने दामाद का भविष्य ही चौपट कर रहे हैं। आई पी एस होने के नाते आप इस युवा अवस्था में अधिकारी को अच्छी मैदानी पोस्टिंग में काम करना चाहिए था। ताकि ज्यादा अनुभव प्राप्त होता परंतु दामाद प्रेम के चलते, जनसंपर्क में पदस्थ कर दिया गया। हो सकता है ससुरजी को को इसमें चुनावी वर्ष के चलते कोई मोटा लाभ नजर आ रहा है। वैसे इस वाणिज्य कर अधिकारी रितु चौहान की भर्ती भी संदेहास्पद थी जो कि काका के मुख्यमंत्री होने के कारण प्राप्त हुई।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

भारतीय वायु सेना मे हर साल बिना युद्ध के औसतन 20 युद्धक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं

कितने युवा जांबाज भारतीय पायलटों को बलि चढ़ाएगी, खटारा मिग-21 में

विश्व भर में, भारत में सबसे ज्यादा युद्धक विमान प्रशक्षिण और नियमित उड़ान के दौरान बिना युद्ध के ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जिसके मूल कारणों में समयबाधित और नियमित्त जहाजो का मैनुअल के अनुसार रखरखाव न किया जाना होता है परंतु यह तथ्य न तो कभी म महालेखाकार ने अपनी टिप्पणी में की और ना ही यह बात वायुसेना के अधिकारीयो मैं अपनी कमी को छुपाने के लिए सरकार या जनता को बताइ। वैमानिकी में अत्यधिक सतर्कता और विमानों की नियमित्त अवधि में पूरी इंजन की खोलकर साफ सफाई ग्रीसगि, तेल, पानी, और आवश्यक कल पुर्जे बदलना आवश्यक होता है। जो कभी भी ढंग से और पूरा नहीं होता यथार्थ में यही दुर्घटनाओं का कारण भी होता है। पर यह सच कभी स्वीकार नहीं जाता और हमेशा जांच के बाद मानव त्रुटि बता कर मामले की इतिश्री कर दी जाती है।

मिग-21 रूसी वायु सेना का दूसरे विश्व युद्ध का एक हजार से ज्यादा समय बाधित और स्क्रैप हुए विमानों का युद्धक विमानों का बेड़ा था। जिसे भारतीय वायु सेना ने मिग-21 सुपरसोनिक जेट 1960 में 872 युध्दक जहाजों का खरीदा था। बेशक इसने चीन से 1962 में और पाकिस्तान से 1965 में भारतीय वायुसेना की लाज रखी परंतु तब से 14 अक्टूबर 2014 तक 314 मिग-21 और 162 दूसरे जिसमें जगुआर ब्रिटेन से, मिग-23- एमएफ व बीएंन, 25, 27, सुखोई 30 जो 1980 से कबाड़ में खड़ा था 1990मे रूस से, मोटे कमीशन के चलते दोहरी पूंछ वाले इस जहाज को खरीदा। भारतीय वायुसेना के जहाज 690 युद्धक विमान दुर्घटनाओं की भेंट चढ़ चुके हैं। जिसमें देश के 500 से ज्यादा युद्धक पायलट बिना युध्द के मारे गए। हर बार 1985 के बाद से लगातार यह कहा जाता रहा यह फ्लाइंग काफैन बन चुका है। इसके बाद में भी उसको अभी तक सेना से बाहर नहीं किया गया। जो इस देश की वायु सेना का अभिशाप बन चुका है। हर विमान दुर्घटना के बाद जांच में यह कभी नहीं कहा जाता कि हमने मोटे कमीशन के चलते विदेशों से समय बाधित और कबाड़ा जहाज खरीदें। हर जांच के बाद मानव त्रुटि और प्रशिक्षण में कमी को दोषी ठहरा कर जांच बंद कर दी जाती है।

रूस भारत से दोस्ती मात्र अपना हथियारों का जिसमें युद्धक, माल ढोने वाले विमान, टैंक बंदूकें विमान वाहक पोत आदि का कबाड़ा खरीदने और अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए निभाता है। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, चेक गणराज्य, सभी हथियार निर्यातक कोई भी अपनी नई तकनीकी का अग्रिम पंक्ति का वमिान, जहाज, टैंक, तोप, मिसाइल से लेकर बंदूके तक नहीं बेंचता।सब अपने कबाड़े को जो समय बाधित और तकनीकी से बाहर हो गया होता है बेंचता है। इसलिए दोस्तीस का स्वांग करता है। और इसीलिए भारत कें प्रधानमंत्री का विदेशों में स्वागत सत्कार किया जाता है ताकि वह हथियारों का कबाड़ा खरीद कर ले जाए।

जबकि सच यह है कि हर विमान की निर्माता कंपनी अपनी मशीन के रखरखाव और अच्छे संचालन के लिए उसकी कार्य पद्धति की उस पुस्तक देती है। जैसे कि हर वमिान की 200 घंटे की उड़ान के बाद उसका इंजन ऑयल बदला जाएगा। 1000 घंटे के बाद उसकी इंजन की खोलकर पूरी साफ सफाई और फिर से फर्टिंग की जाएगी। 30000 घंटे की उड़ान के बाद उसका इंजनि बदला जाएगा। पर रूस जैसे धूर्त देश ने 872 मिग-21 के 60 साल की उड़ान के बाद में भी असली नये इंजन की आपूर्ति नहीं की। पुराने इंजनों की मरम्मत और साफ-सफाई से ही काम चलाया जाएगा तो क्या होगा। जो हो रहा है वही तो हो होगा। यही हाल रूस के हर समयबाधति वमिान का है। भारत में वायुसेना की वर्कशॉप की इंजीनियरों की रखरखाव की टीम ने भी शायद आज तक पूरे मैनुअल जो हर विमान की अलग-अलग हजारों पन्नों की होती है। का पूरा बारीकी से अध्ययन नहीं किया होगा। जबकि हर विमान की खरीद के बाद की बारीकियों को समझने के लिए निर्माता कंपनी के पास जाकर पूरे तकनीकी लोगों की टीम को महीनों बारीक प्रशिक्षण लेना होता है जो शायद भारत में कभी पूरा नहीं हुआ।

वैसे भी हमारे देश में सभी युद्धक और यात्री विमान विदेशी वायु सेना और कंपनियों द्वारा वायुसेना और कंपनियों द्वारा खरीदे जाते हैं। जब वे वहां से अपनी आयु पूर्ण कर लेते हैं और चलन से बाहर हो जाते हैं। अर्थात भारत के आसमान में उड़ने वाले 95% जहाज समय बाधित और चलन से बाहर हो चुके हुए होते हैं। बेशक रूसी सारे मगि सीरीज के जहाज सुपर सोनिक जेट होते हैं। दुनिया की अधिकांश कंपनियां अब बाहरी पंखों के विमान नहीं बनाती हैं बाहरी पंखों के विमान को बनाना लगभग दुनिया की हर कंपनी ने हीं छोटे विमानों को छोड़कर बंद कर दिया है। अधिकांश यात्री विमान और युद्धक विमान आंतरिक प्रोपेलर सिस्टम से ही ही बनाए जा रहे हैं। पर भारत के आसमान पर अभी भी बाहरी पंखों वाले जो प्लेन उड़ रहे हैं। वह सभी क्या है? सभी पाठक समझ सकते हैं।

यह तथ्य मेरी कंपनी जिसे मैंने माइक्रोलाइट और पावर्ड पैराशूट आदि छोटे विमानों की आम भारतीय युवाओं को उड़ान सिखाने और शौक पूरे करने के लिए खड़ी की थी। जिसमें पांच वायु सेना के सेवानिवृत्त विंग कमांडर थे उन्होंने मुझे बताये थे। मेरी कंपनी धनाभाव में कागजों से निकलकर उड़ान नहीं भर पाई परंतु वह अनुभव आज भी काम दे रहा है। जिसे मैं गाहे-बगाहे अपने समाचार पत्र और अपनी न्यूज़ साईट से आमजन को प्रस्तुत करता रहता हूं।

भारतीय वायुसेना के युवा जांबाज पायलटों को इस तरह मरते हुए देख बहुत दुख होता है इसलिए यह लेख लिखा है मैंने।

सभी को चाहिए कि सरकार से कहें कि कम से कम अब हमारे युवा पायलटों को मिग-21 रूपी मृत्यु के जहाज में ना बैठा ले वैसे भारतीय वायु सेना स्वयं मिग-21 को फ्लाइंग कॉफ़िन हीं बोलती है। इसके विपरीत सच बहुत गंदा घिनौना है जिस पायलट की अकाल मृत्यु निश्चित करनी होती है। जो अपने अधिकारियों की मांगों पर खरा नहीं उतरता या अपनी सुंदर बीवी को अधिकारियों के क्लब में ले जाकर उन्हें उनके हवाले नहीं करता। उसे इस में बैठा दिया जाता है। और नीचे उसकी मौत का इंतज़ार किया जाता है। क्योंकि शाम होते ही हर वायु, थल,जल सेना के मुख्यालय पर बने अधिकारियों के क्लब में हर अधिकारी को अपनी बीवी, बेटी के साथ जाना पड़ता है और वहां जाते ही बीवियों की अदला बदली चलती रहती है। यह सच ना केवल भारत के, बल्कि दुनिया के सेना के हर अधिकारियों के क्लब का होता है। यहां स्थानांतरण पोस्टिंग पदोन्नति सब इसी योनाचार के दम पर होती है।

यह तथ्य लगातार बड़े समाचार पत्रों में बरसों से प्रस्तुत हो रहा है। परंतु रक्षा मंत्रालय जागने को तैयार नहीं क्योंकि मिग-21 के बेड़े को हटाने से अचानक वायु सेना की विमानों की संख्या कम हो जाएगी।

दुख की बात तो यह है हमारा लोहा हमारे देश से ही खरीद कर कबाड़ हुए युद्धक विमानों के रूप में सोने के भाव हमारे देश की सरकार 2-5- 10 करोड़ के जहाजों को हजारों करोड़ में खरीद लेती है। वहां मोटा 90% कमीशन होता है। यही कांड मोदी ने भी अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन रूस आदि हाल ही में खरीदे गए युद्धक विमानों में भी किया आखिर क्या होता है युद्धक विमानों में दो उच्च श्रेणी के इंजन और मजबूत तीव्र गति से उड़ान योग्य अधिकतम भार 2 से3 टन के पेट्रोल, बम और मिसाइल भार लेकर उड़ान क्षमता हल्की मिश्र धातु का ढांचा। यथार्थ में लागत तो नये जहाजों की भी 25-40 करोड से ज्यादा नहीं होती।

विकास पुरुष का दावा करने वाले बन गए विनाश पुरुष

पेज एक से जारी

जब सरकारी रिपोर्ट कहने लगे कि भ्रष्टाचार 67 % बढ़ गया। जब हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी नदियाँ ज्यों की त्यों रहें तो उनकी परिक्रमा और आरती का आडम्बर शुरू कर दीजिए,लाखों लोगों को उद्गम स्थल पर बुलाकर भाषणबाजी करिये। लोगों को लगेगा कि आप सच्चे गंगा पुत्र हो।

न खाऊंगा, ना खाने दूंगा, के चक्कर में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक वक्त भी भरपेट भोजन नहीं मिल रहा,इसके विपरीत पूरे देश में एक करोड़ से ज्यादा शौचालयों के नाम से 70 लाख से ज्यादा शौचालय केवल कागजों पर बना कर ही लगभग रुपए 1,40,000 करोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। जिसमें सारे सरपंच सचिव भी करोड़पति हो गए। सफाई के नाम एक लाख से ज्यादा मिनी ट्रक 20000 से ज्यादा ट्रक निगमों पालिकाओं को खरीदवा कर टाटा मोटर्स हिंदुजा के अशोक लीलैंड, महनिद्रा को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। और जनता पर तीन तरफ से सफाई के नाम पर हजारों करोड़ प्रतिदिन की वसूली की गई।

"आक्सिजन के अभाव मे गरीबो के बच्चे मर रहे है, रेल दुर्घटनाओ मे लोग बेमौत मर रहे है, ऊचित मूल्य न मिलने की वजह से किसान मर रहे है, सरहद पर जवान मर रहे है, स्वाईन फ्लू से हजारो मरीज मर रहे है, GST से व्यापारी परेशान है, मंहगाई से जनता परेशान है, रसोई गैस दूगने दाम पर होने से गृहिणी परेशान है, मोदीजी काम कम करते है और प्रचार अधिक, कैशलेस के नाम पे ट्रांजेक्शन चार्ज लेकर लूटा जा रहा है, आधार कार्ड के विरोधी उसे आवश्यक बना रहे है, 51% FDI के विरोधी अब 100% की पैरवी कर रहे है, मनरेगा की हंसी उडाने वाले अब उसमे अधिक बजट दे रहे है, सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढाकर देश लूंट रही है, नोटबंदी के नुकसान छूपा रही है, 370 दूर करने का प्रवचन देनेवाले देश के गद्दारो संग सरकार चला रहे थे, राममंदिर को कोर्ट का मामला बताकर खुद को बचा रहे है, .. *विकास अब विनाश हो चुका है। स्मार्ट सिटी के नाम पर देश में कम से कम 50लाख लोगों को उनके मकान, उनके ठेले, गुमटियां, दुकाने तोड़ कर सड़कों पर पटक दिया गया। फुटकर व्यवसाय में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश लाकर वॉल-मार्ट जैसी कंपनियों का पेट भरने उनके शॉपिंग मॉल चलाने के लिए 40 लाख से ज्यादा ठेले वालों फेरी वालों फुटपाथ धंधा करने, उद्योग चलाने वालों को विकास के नाम विनाश कर विकास पुरुष ने अपनी दानवीयता सिद्ध कर दी। सोचिए गुजराती राक्षसो जिसकमे मोहन करमचंद गांधी के बाद भारत में नया अवतार मोदी है। आजादी के पहले गांधी ने क्रांतिकारियों को और निर्दोष हिंदुओं को मरवाया, आजादी के समय देश के तीन टुकड़े करवा दिए, और लाखों हिंदुओं को मरवा दिया गया देश की आजादी गांधी के कारण नहीं मुंबई की जल सेना की बगावत और भारतीय जल सैनिकों द्वारा 312 सैनिक नावो को डुबो देने और सैकड़ों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देने, व द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के दिवालिया होने के कारण अंग्रेजों को देश खाली करना मजबूरी बन गया था पर कांग्रेस ने आजादी के नाम सत्ता हथियाने मे मोहन गांधी किया गया वही हाल नरेंद्र दामोदर मोदी का भी अपने आप को महान बताने रऔर सत्ता पर अपनी पकड बनाये रखने के लिये है।

काला धन लाने की तो दूर उल्टा ही बढ़ा, चुनावी जुमला पूँजीपतियों का वादा पूरा करने में बदल गया स्विस बैंकों और विदेशों में सात नहीं 7 लाख करोड बढ़ा अधिकांश काला धन, भाजपा के मुख्यमंत्रियों केंद्रीय मंत्रियों 15-20 पूंजी पतियों और देश के 5000 से ज्यादा भारतीय प्रताड़ना सेवा, भारतीय आगम सेवा पुलिस सेवा और वन सेवा के अधिकारियों का भुखेरा जन पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से सन 2013 से 14 मे चुनाव जीतने तक, देश के बड़े नामी गिरामी जालसाज 30 से 40 पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, जिसमें अदानी अंबानी टाटा बिरला, सुनील मित्तल, वॉलमार्ट, आईटीसी आदि से लाखों-करोड़ों में धन लेकर जनता को सारे प्रसार् माध्यमों,फेसबुक, टवीट्रर,गूगल को खरीदकर भ्रमित किया। जीतने के बाद काले धन के नाम, नोटबंदी की गई और कहा गया, काला धन बाहर आएगा, जबकि 1000का नोट बंद करके, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, भू और कॉलोनी माफियाओं, खनन माफियाओं, नेताओं, मंत्रियों, भारतीय प्रताड़णा सेवा, आगम लूट सेवा, भारतीय अपराध प्रोटेक्शन सेवा, वन सेवा आदि के अधिकारियों का काला धन, व कम स्थान पर सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए रु 2000/- नोट जारी किया गया। जिसके सार्थक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। जो विदेशों में धन भेजने की कांग्रेस के समय सीमा रुपए 75000 सवा लाख और बाद में ढाई लाख कर दिया गया। यथार्थ में नोटबंदी पूंजीपतियों के लाभ उनके शॉपिंग मॉल चलाने और छोटे व्यवसाइयों को खत्म करने के लिए ही लागू की गई थी । उद्देश्य था अधिकतम लेन देन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा ताकि पेटीएम, रलियांस वॉलेट, मोबाइल, भीम ऐप, बैंकों के एटीएम, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर हर लेनदेन पर मोटा कमीशन बैंकों को को मिलेगा जो न्यूनतम 5 लेन-देन की बाद हर लेन देन पर रु175/- की वसूली का नया खेल शुरू करो एक तरफ अपने बापों, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, जेपी एसोसिएट, व अन्य सैकड़ों देसी कंपनियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, वॉलमार्ट, आदि को लाखों करोड़ के बैंकों द्वारा दिए गए कर्जों की डूबंत रकम की भरपाई की जा सके जिसमें हजारों करोड जिनसे मोदी ने अपने चुनाव के लिए गया था।

साथ ही अपने धन को सभी पूंजीपति, उद्योगपति, शासकीय अधिकारी, मंत्री, नेता, अपना धन आसानी से भारत में कमा कर विदेशी बैंकों में सुरक्षित कर सकें और यह धन 7000 करोड़ नहीं वरन 70000 करोड़ से ज्यादा था। फिर केवल स्विट्जरलैंड विदेश नहीं है, भारतीय मुस्लिमों का पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे शत्रु राष्ट्र में भी निवेशित किया गया है, इसके साथ ही अनेकों उद्योगपतियों ने भारतीय बैंकों से लोन लेकर, जिसमें अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला,, मित्तल आदि शीर्ष पर हैं, विदेशों में जिसमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि से लेकर अफ्रीकन देशों मैं भी उद्योग व्यवसाय और ठेकों मैं निवेशित किया गया है इसका अधिकांश काला धन ही है। मोदी ने अधिकांश देशों की यात्राएं केवल अपने पूंजीपति मित्रों के व्यापार संवर्धन के लिए देश के पैसे से, देश की जनता को मूर्ख बनाकर कि वह भारत मैं विदेशी और उद्योगपतियों के निवेश को लाने के लिए, विदेशों में भारत की छवि सुधारने, संबंधों को मजबूत करने के लिए यात्राएं कर रहा है। यह सरासर झूठ था जो सामने आ चुका है।

भारत की राजनीतिक वैचारिक कमजोर बुद्धिहीन, बिकाऊ, लालची, भ्रष्ट और आपराधिक विपक्षी नेता भी इस महत्वपूर्ण मुद्दों और तथ्यों को, जनता के सामने लाने और प्रसार माध्यमों में प्रस्तुत करने में असक्षम रहे।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

मोहन गांधी, जवाहर नेहरू महा धूर्त, घोर मक्कार, अंग्रेजी एजेंट हिंदुओं के दुश्मन और घोर अय्याश थे। अपने दुष्कर्मों को छुपाने, अपनी लोकप्रियता भुनाने, देश को बांटकर नेहरू प्रधानमंत्री और घोर अय्याश गांधी महात्मा बन गया

विदेशों में मोहन करमचंद गांधी की कथित यौनाचार

उच्च श्रृंखला पर एक बार फिर से बहस

मेरे पाठकों ने पर के लेखों में गांधी की आजादी की दास्तान पढ़ ली है नेहरू के बारे में भी उस की अय्याशी के किस्से भी भारत के अखबारों में खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब मोहन गांधी की अय्याशी और कामुकता के बारे में जानिए

आपको बता दें मोहन गांधी ने भारत की पट्टे की आजादी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के 55 देशों में फैले साम्राज्य को संभालने और वहां पर अपनी सेना रखने और देश को नियंत्रण करने में भारी आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था जबकि विश्व युद्ध के कारण इंग्लैंड दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। उस समय उसने अनेकों देशों से बिना शर्त अपनी सेना बुलाकर देश को आजाद कराया था उनमें भारत भी एक था यहां पर पूरे देश में सेना को संभालने से इंग्लैंड के सामने भारी आर्थिक और तंगी और अपने किए की विश्व की विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड भारत को आजाद कर देगा और जब इंग्लैंड ने 20 विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद करने से मना कर दिया मुंबई की जल सेना में भारतीय सिपाहियों ने लगभग 320 से ज्यादा इंग्लैंड की युद्धनौका डुबोने के साथ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी थी जिससे पूरी तरह घबरा चुका था और भारत को बिना शर्त आजाद करने का मन बना चुका था पर इन तीनों इंग्लैंड में पढ़े अंग्रेजी के गुलाम अय्याश धूर्तों मोहन गांधी, जवाहर नेहरू और अली जिन्ना को लेडी माउंटबेटन के साथ अश्लील हरकतों के फोटो में फसाकर पट्टे की आजादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा कर देश को 14 अगस्त की रात्रि में 99 साल के पट्टे की आजादी पर सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। इस प्रकार हमारे लाखों आजादी के दीवानों की कुर्बानी तीनो ने बर्बाद करते हुए पट्टे पर सत्ता प्राप्त की गई। नेहरू और जिन्ना की अय्याशियों के बारे में तो पहले भी काफी कुछ आ चुका है पर गांधी के बारे में महात्मा के नाम से लोगों को उसकी अय्याशियों विविध प्रतिष्ठित स्त्रियों के साथ यौंनाचार व यौनाकांक्षाओ का इतिहास नहीं पड़ा अन्यथा यह वर्तमान का राम रहीम और आसाराम से भी बड़ा महात्मा सिद्ध होता। और वर्तमान राजनीति के चलते यह भी तिहाड़ या जोधपुर की जेलों में आसाराम के साथ भजन मंडली भजन गा रहे होते।

लंदन के प्रतिष्ठित अख़बार "द टाइम्स" के मुताबिक गांधी को कभी भगवान की तरह पूजने वाली 82 वर्षीया गांधीवादी इतिहासकार कुसुम वदगामा ने कहा है कि गांधी को सेक्स की बुरी लत थी, वह आश्रम की कई महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोते थे ।

वह इतने ज़्यादा कामुक थे कि ब्रम्हचर्य के प्रयोग और संयम परखने के बहाने चाचा अमृतलाल तुलसीदास गांधी की पोती और जयसुखलाल की बेटी मनुबेन गांधी के साथ सोने लगे थे। ये आरोप बेहद सनसनीख़ेज हैं क्योंकि किशोरावस्था में कुसुम भी गांधी की अनुयायी रही हैं। कुसुम, दरअसल, लंदन में पार्लियामेंट स्क्वॉयर पर गांधी की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रही हैं।

बहरहाल, दुनिया भर में कुसुम के इंटरव्यू छप रहे हैं।

वैसे तो महात्मा गांधी की सेक्स लाइफ़ पर अब तक अनेक किताबें लिखी जा चुकी हैं। जो ख़ासी चर्चित भी हुई हैं। मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार जेड ऐडम्स ने पंद्रह साल के गहन अध्ययन और शोध के बाद 2010 में "गांधी नैकेड ऐंबिशन" लिखकर सनसनी फैला दी थी।

किताब में गांधी को असामान्य सेक्स बीहैवियर वाला अर्द्ध-दमित सेक्स-मैनियॉक कहा गया है। किताब राष्ट्रपिता के जीवन में आई लड़कियों के साथ उनके आत्मीय और मधुर रिश्तों पर ख़ास प्रकाश डालती है। मसलन, गांधी नग्न होकर लड़कियों और महिलाओं के साथ सोते थे और नग्न स्नान भी करते थे।

देश के सबसे प्रतिष्ठित लाइब्रेरियन गिरिजा कुमार ने गहन अध्ययन और गांधी से जुड़े दस्तावेज़ों के रिसर्च के बाद 2006 में "ब्रम्हचर्य गांधी ऐंड हिज़ वीमेन असोसिएट्स" में डेढ़ दर्जन महिलाओं का ब्यौरा दिया है जो ब्रम्हचर्य में सहयोगी थीं और गांधी के साथ निर्वस्त्र सोती-नहाती और उन्हें मसाज़ करती थीं।

इनमें मनु, आभा गांधी, आभा की बहन बीना पटेल, सुशीला नायर, प्रभावती (जयप्रकाश नारायण की पत्नी), राजकुमारी अमृतकौर, बीवी अमुतुसलाम, लीलावती आसर, प्रेमाबहन कंटक, मिली ग्राहम पोलक, कंचन शाह, रेहाना तैयबजी शामिल हैं। प्रभावती ने तो आश्रम में रहने के लिए पति जेपी को ही छोड़ दिया था। इससे जेपी का गांधी से ख़ासा विवाद हो गया था।

तक़रीबन दो दशक तक महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सहयोगी रहे निर्मल कुमार बोस ने अपनी बेहद चर्चित किताब "माई डेज़ विद गांधी" में राष्ट्रपिता का अपना संयम परखने के लिए आश्रम की महिलाओं के साथ निर्वस्त्र होकर सोने और मसाज़ करवाने का ज़िक्र किया है।

निर्मल बोस ने नोआखली की एक ख़ास घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है,

"एक दिन सुबह-सुबह जब मैं गांधी के शयन कक्ष में पहुंचा तो देख रहा हूं, सुशीला नायर रो रही हैं और महात्मा दीवार में अपना सिर पटक रहे हैं।"

उसके बाद बोस गांधी के ब्रम्हचर्य के प्रयोग का खुला विरोध करने लगे। जब गांधी ने उनकी बात नहीं मानी तो बोस ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया।

ऐडम्स का दावा है कि लंदन में क़ानून पढ़े गांधी की इमैज ऐसा नेता की थी जो सहजता से महिला अनुयायियों को वशीभूत कर लेता था। आमतौर पर लोगों के लिए ऐसा आचरण असहज हो सकता है पर गांधी के लिए सामान्य था।

आश्रमों में इतना कठोर अनुशासन था कि गांधी की इमैज 20 वीं सदी के धर्मवादी नेता जैम्स वॉरेन जोन्स और डेविड कोरेश जैसी बन गई जो अपनी सम्मोहक सेक्स-अपील से अनुयायियों को वश में कर लेते थे।

ब्रिटिश हिस्टोरियन के मुताबिक गांधी सेक्स के बारे लिखना या बातें करना बेहद पसंद करते थे। इतिहास के तमाम अन्य उच्चाकाक्षी पुरुषों की तरह गांधी कामुक भी थे और अपनी इच्छा दमित करने के लिए ही कठोर परिश्रम का अनोखा तरीक़ा अपनाया।

ऐडम्स के मुताबिक जब बंगाल के नोआखली में दंगे हो रहे थे तक गांधी ने मनु को बुलाया और कहा

"अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मुस्लिम चरमपंथी हमारा क़त्ल कर देते। आओ आज से हम दोनों निर्वस्त्र होकर एक दूसरे के साथ सोएं और अपने शुद्ध होने और ब्रह्मचर्य का परीक्षण करें।"

किताब में महाराष्ट्र के पंचगनी में ब्रह्मचर्य के प्रयोग का भी वर्णन है, जहां गांधी के साथ सुशीला नायर नहाती और सोती थीं।

ऐडम्स के मुताबिक गांधी ने ख़ुद लिखा है,

"नहाते समय जब सुशीला मेरे सामने निर्वस्त्र होती है तो मेरी आंखें कसकर बंद हो जाती हैं। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। मुझे बस केवल साबुन लगाने की आहट सुनाई देती है। मुझे कतई पता नहीं चलता कि कब वह पूरी तरह से नग्न हो गई है और कब वह सिर्फ़ अंतःवस्त्र पहनी होती है।"

दरअसल, जब पंचगनी में गांधी के महिलाओं के साथ नंगे सोने की बात फैलने लगी तो नथुराम गोड्से के नेतृत्व में वहां विरोध प्रदर्शन होने लगा। इससे गांधी को प्रयोग बंद कर वहां से बोरिया-बिस्तर समेटना पड़ा। बाद में गांधी हत्याकांड की सुनवाई के दौरान गोड्से के विरोध प्रदर्शन को गांधी की हत्या की कई कोशिशों में से एक माना गया।

ऐडम्स का दावा है कि गांधी के साथ सोने वाली सुशीला, मनु, आभा और अन्य महिलाएं गांधी के साथ शारीरिक संबंधों के बारे हमेशा गोल-मटोल और अस्पष्ट बाते करती रहीं। उनसे जब भी पूछा गया तब केवल यही कहा कि वह सब ब्रम्हचर्य के प्रयोग के सिद्धांतों का अभिन्न अंग था।

गांधी की हत्या के बाद लंबे समय तक सेक्स को लेकर उनके प्रयोगों पर भी लीपापोती की जाती रही। उन्हें महिमामंडित करने और राष्ट्रपिता बनाने के लिए उन दस्तावेजों, तथ्यों और सबूतों को नष्ट कर दिया गया, जिनसे साबित किया जा सकता था कि संत गांधी, दरअसल, सेक्स-मैनियॉक थे। कांग्रेस भी स्वार्थों के लिए अब तक गांधी के सेक्स-एक्सपेरिमेंट से जुड़े सच छुपाती रही है। गांधी की हत्या के बाद मनु को मुंह बंद रखने की सख़्त हिदायत दी गई।

उसे गुजरात में एक बेहद रिमोट इलाक़े में भेज दिया गया। सुशीला भी इस मसले पर हमेशा चुप्पी साधे रही। सबसे दुखद बात यह है कि गांधी के ब्रम्हचर्य के प्रयोग में शामिल क़रीब-क़रीब सभी महिलाओं का वैवाहिक जीवन नष्ट हो गया। बेशक भाजपा के कब्र से गांधी के निकालें यह कारनामे कांग्रेस को चारों तरफ से घेरकर हर प्रकार से बर्बाद करने की रणनीति का चुनावी हिस्सा है।

विश्व में प्रदूषण के लिए यूरोपियन बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार

पेज एक से जारी

कार्बन डाई ऑक्साइड, गैसों की प्रचुरता ने पृथ्वी के वायुमंडल का ऑक्सीजन और उसकी ओजोन परत को भारी नुकसान पहुंचाया और पहुंचा रही है।

साथ ही ठोस प्लास्टिक की बोतलें पैकिंग पॉलीथिन की थैलियां, नालियों से लेकर सभी जलस्त्रोतों के साथ धरती पर फैल कर कर वनस्पतियों, जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। दुनिया को अब इसकी चिंता सताने लगी है पर यह चिंता खोखली और दिखाऊं है क्योंकि जो कंपनियां इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। वे ही ज्यादा हल्ला मचाती है जबकि स्वयं अपने उत्पादन कभी बंद नहीं करती जो की अधिकांश अमेरिका और यूरोप की है इनकी देखादेखी एशिया महाद्वीप के देशों में भी इस जीवाश्म इंधन के उपयोग की गति अधिक तेज गति से बढ़ रही है जिसमें बाइक्स कारें ट्रक बसें, वायुयान, जलपोतों जिस जीवाश्म इंधन जो की पेट्रोल डीजल के रूप में उपयोग करते हैं यह सभी यथार्थ में प्रदूषण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। पर इसके विपरीत कार कंपनियों, बाइक्स, ट्रक बसें जलपोत और वायुयान कंपनियों ने अपने उत्पादन बंद कर दिए जो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से सबसे ज्यादा वायुमंडल को नष्ट करने को तुले हुए हैं।

दुनिया के अधिकांश देश अमेरिका और यूरोप के साथ एशिया महाद्वीप के चीन भारत जापान सबसे ज्यादा कार, बसों, ट्रकों का आवागमन के लिए उपयोग करते हैं। इसके उपयोग से जो धुआं निकलता है वह वायुमंडल को दूषित करने के साथ ही उसने अधिकांश देशों में मौसम का चक्कर भी बिगाड़ दिया है जिससे अल्प वर्षा अधिक तेज गर्मी, शीत पढ़ने के साथ ही भारी बर्फबारी, हिमालय के ग्लेशियरों का खत्म होना, सूख जाना,नदियों के बहाव का कम होना, या अत्यधिक बाढ़ आना, छोटी नदियों, नालों जो कि इन बड़ी नदियों के जल के स्त्रोत हुआ करते थे गायब या सूख जाना।यह सब मानव की लालची प्रवृत्ति का ही परिणाम है। दुनिया और विशेष तौर से अमेरिका और यूरोप की सरकारें प्रदूषण को लेकर हल्ला तो भारी मचाती हैं । बड़े-बड़े कार्यक्रम, सभाएं और सम्मेलन करती हैं। जिन्हें उन देशो में बैठी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं।इन नेताओं और सरकारों को वित्तीय सहायता देकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजित भी स्वयं ही करती हैं ताकि मानव वह पृथ्वी के वायुमंडल के हितैषी होने कापाखंड कर सकें।

निसंदेह बढ़ते प्रदूषण के कारण हर देश की सरकारों में अपने यहां प्रदूषण नियंत्रण मंडल का सरकारी कार्यालय खोल रखा है परंतु यह सभी प्रदूषण मंडल या विभाग इस प्रदूषण नियंत्रण की आड़ में मोटी वसूली कर प्रदूषण फैलाने का कार्यक्रम चलाते हैं बेशक यह सच भारत चीन अमेरिका और जापान व अन्य देशों में तो सच है परंतु स्विट्ज़रलैंड व अन्य अनेकों राष्ट्र प्रदूषण के प्रति काफी गंभीर भी है। हर वर्ष पूरी दुनिया में पॉलिथीन, प्लास्टिक, एलुमिनियम जिलेटिन, आदि के पेकिंग सामग्री के कचरे से लगभग 30लाख टन कचरे से धरती के साथ यह पॉलिथीन,प्लास्टिक, एल्युमीनियम फाइल का यह कचरा नदी नालों से बहता व होता हुआ समुद्रों के गर्भ में एकत्रित हो रहा है जिससे हर वर्ष करोड़ों जलीय जीवो और वनस्पतियों की प्रजातियां नष्ट होने के साथ ही बची हुई प्रजातियों की प्रजनन क्षमता भी कम होती जा रही है। जिससे समुद्र का जल अत्यधिक प्रदूषित होने के साथ ही विषैला भी होता जा रहा है। यही हाल धरा पर जीवित प्राणियों यथा मानव के साथ ही वन्य प्राणी पशु पक्षियों कीटो के साथ वनस्पतियों को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि ना केवल वायुमंडल में ऑक्सीजन व जल की कमी के साथ आद्रता की भी कमी होती जा रही है।पिछले 50 वर्षों में हजारों पशु पक्षियों और वनस्पतियों की प्रजातियां धरती से लुप्त हो गई है। भारत के वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन लगभग 20 पशु पक्षियों व अन्य प्राणियों की, वनस्पतियों की प्रजातियां भी नष्ट हो रही है जो केवल मानव रूपी गिद्ध के भारी लोभ-लालच और मौत का परिणाम ही है। भारत में ही हमारे देश के महा धूर्त, और सरकार को पिछाड़ू जेब मैं रखकर चलने वाले अंबानी बंधुओं न हीं मोदी सरकार को दबाव डाल कर प्लास्टिक को जो कि उसकी रिलायंस रिफाइनरी का सह उत्पाद है और हर दिन हजारों टन क्रूडपेट्रो के डीजल पेट्रोल शुद्धिकरण से प्राप्त होता है। की विपणन व्यवस्था भारी खपत के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक को पुनः पिघलाकर दूसरे शब्दों में प्रयोग लाने की के कार्य को बंद करवा दिया ताकि उसके रिलायंस रिफाइनरी से निकले हजारों टर्न प्लास्टिक दाने का उपयोग लगातार होता रहे और उसकी बिक्री लगातार बनी रहे जो उसके लाभ का एक बड़ा हिस्सा है ।

यथार्थ में पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक सरकारे बड़े पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ही चलाई जाती है यह सच पूरी दुनिया में एक समान लागू होता है यह पूंजीपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जनता की जेब पर डाका डालने, लूटने,शोषण करने, मोटे लाभ के लिए सरकार में बैठे मंत्रियों अधिकारियों को मोटी रिश्वत बांटकर,खरीदकर सरकारों पर दबाव डालकर अपनी मनमर्जी से कानून बनवाती हैं। फिर सरकार को नचा कुदा कर अपने प्रतिद्वंदियों, छोटे व्यापारियों को नष्ट करने के लिए मनमर्जी से शासकीय तंत्र का उपयोग करती है हाल ही में इंदौर मध्य प्रदेश और देश में छोटे व्यवसाइयों, ठेले वह सड़क पर माल बेचने वालों को व्यवसाय बंद करने, उनका रोजगार छुड़ाने, प्रतिद्वंदिता खत्म करने देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव, सचिव, क्षेत्रीय स्तर के मंत्रियों, महापौरों, पार्षदों व नगर निगमों, पालिकाओ,परिषदों के निगम आयुक्त, व अन्य अधिकारी कर्मचारियों, जिले के जिलाधीशों, उप जिलाधीशों से लेकर थानेदार पुलिस अधीक्षक, आदि को खरीदकर. नगर की स्वच्छता के नाम, स्मार्ट सिटी के नाम व अन्य कई तरीकों से सड़क पर फुटपाथ पर छोटे व्यापारियों पर पतली पॉलीथिन के नाम पर ठेले वालों सड़क पर माल बेचने वालों छोटे दुकानदारों आदि के ठेले व सामान जप्त कर, सामान में लूटपाट हुई, बाद में उनके ठेले तोड़ दिए गए उन्हेंउसकी बिक्री लगातार बनी रहे जो उसके लाभ का एक बड़ा हिस्सा है ।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

पुलिस खाकी वर्दी के सरकारी गुंडे, अपराध रोकने नहीं, अपराध होने का करते हैं इंतजार

दोष, पुलिस का नहीं खाकी वर्दी का है, अपराध रोकने, नहीं संरक्षण देने का काम

मध्यप्रदेश में, विशेष रूप से इंदौर औद्योगिक विकास के साथ अपराधों की राजधानी भी बन गया जनता चिल्लाती रहती है। पुलिस धकियाती रहती है। जब अपराध हो जाता है तो फिर कार्यवाही करने की बात करती है। सिपाही अधिकारी तक सबका पावन उद्देश्य कानूनो और वर्दी की आड़ में मोटी कमाई करना है।

प्रदेश की इंदौर व्यवसायिक राजधानी होने के साथ-साथ उच्च शिक्षा का गढ़ बन जाने के कारण, अपराधो, मादक पदार्थों की बिक्री की भी राजधानी बन चुका है। स्वाभाविक है औद्योगिक व्यावसायिकता उच्च शिक्षा के कारण यहां पर युवा वर्ग जो बाहर से शिक्षा अध्ययन व रोजगार की तलाश में यहां आता है। यहां पर चकाचौंध मैं उलझ कर युवा वर्ग नशे, वेश्यावृत्ति मैं भी उलझता है। बाहर से आने वाले शिक्षार्थी जो माता पिता के भेजे हुए धन को शीघ्र ही खर्च कर देने के कारण धन कमाने के लिए नशा बेचने, वेश्यावृत्ति करवाने, अन्य प्रकार से अवैध तरीके से धन कमाने लग जाता है। इसके लिए उसे ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करने पड़ते। क्षेत्रीय बाजार में आसानी से एक चोरी की या पुरानी गाड़ियां, खरीद कर वह आसानी से इंदौरीअन बनकर आसानी से किराए के लोभी मकान मालिकों से ऊंचे किराए पर मकान लेकर, कामवाली को रोटी बनाने के काम पर रखकर अपने मिलने जुलने वालों को बुलाकर वेश्यावृत्ति से कमाई करने लग जाता है। उसकी आड में आने वालों को नशे का भी कारोबार करता है। साथ ही उसके बाहर से आने वाले मित्र जो अपराधी प्रकृति के होते हैं आसानी से ऐसे कमरो में फरारी भी काटते रहते हैं। धर्मशाला में चलते हुए मकान ऐसे आने-जाने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक रहते हैं। जहां मकान मालिक रहता हो। वहां आसानी से लड़कियां और औरतें लाना सामूहिक भोगाचार करना। बहुत सामान्य सा कार्य है। यह सब कुछ पुलिस अच्छी तरह से जानती है। पहले पुलिस की सो नंबर वेन हर गली मोहल्ले में चक्कर काटकर हालात का जायजा लेती थी वर्तमान में यह सारी व्यवस्थाएं भी ठंडी पड़ी हुई है। जबकि कानूनन हर मकान मालिक को किसी भी किराएदार को मकान देने से पहले उसकी अच्छी तरह से खोजबीन करनी चाहिए उसका आधार कार्ड वोटर कार्ड लेकर यह पता करना चाहिए कि जो मकान ले रहा है उसका सही नाम पता क्या है कहां का रहने वाला है। जो गाड़ी उसके पास है उसके पास वैध कागजात है भी या नहीं। वह सारी जानकारी उसे तत्काल संबंधित निकटवर्ती थाने को उपलब्ध करवानी चाहिए। 99 परसेंट मामलों में कोई भी मकान मालिक यह जानकारी संबंधित थाने को कभी नहीं देता। उस की आड़ में अपने मकान में ऐसे ही किरायेदारों को खुला सरंक्षण देकर इस अपराध की नगरी में ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है। यदि कोई अडोसी पड़ोसी उसके बारे में पुलिस को या क्राइम ब्रांच को सूचित करते हैं। 99% मामलो मे पुलिस आवेदन लेकर रख लेती है और कोई भी कार्यवाही नहीं करती। यही कारण है कि शहर में दिनों दिन नशे का कारोबार बहुत तेजी से फल-फूल रहा है। चौराहे पर लगे आर एल वी डी कैमरो से चालानी कार्रवाई कर कर चालंन घर भेज रही है। परंतु शहर में दौड़ रही 25% अवैध गाड़ियों के बारे में पिछले 5 सालों में आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकी न हीं इन कैमरों के माध्यम से किसी चोरी की गाड़ी को या चोर को पकड़ा गया। जबकि गाड़ी चोरी करके चोर सड़को पर से ही चौराहो से ही गुजरता है। परन्तु गाड़ी पकड़ने की तो दूर, उसकी शिकायत भी कोई थाना नहीं लेता। जबकि अधिकांश अपराध चेंन खींचना, छेड़छाड़, घरों में घुसकर लूटपाट करना, अपहरण करना आदि सब के अपराधी सड़कों से ही इन केंमरो के सामने से ही गुजरते हैं इन केंमरों के माध्यम से ऐसे अपराधी आसानी से पकड़े जा सकते हैं।

इंदौर में तो आई जी से लेकर डीआईजी, एसपी, डीएसपी, सीएसपी, टीआई, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक से लेकर कांस्टेबल तक की पोस्टिंग मुफ्त में नहीं होती, थाने बिकते हैं। तो अपराध रोकने के लिए नहीं, वरन अपराधियों को संरक्षण देकर उनसे कमाई करने के लिए आते है, यहां फरि शासन मैं बैठा गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय प्रभारी मंत्री, सांसद विधायक से लेकर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव सब अपनी भरपूर सेवा चाकरी के लिए ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी शहर में आने पर तन मन धन से सेवा चाकरी कर सके उस की आड़ में वह सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि सब कुछ नहीं करेगा तो अपने आकाओं की सेवा कैसे करेगा अपने आकाओं की सेवा करने के लिए उन के पाले हुए नेताओं, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण देना आवश्यक है क्योंकि वही उसी कमाई का साधन भी है। यही कारण है कि शहर में भूमाफिया, शिक्षा माफिया, ड्रग माफिया, चकला माफिया, सट्टा माफिया, अवैध वसूली,खनन माफिया, सभी का धंधा पुलिस को महीना पहुंचा कर ही फलता-फूलता है। यदि यह सभी माफिया धन नहीं कमाएंगे तो नेताजी को चुनाव लड़ने के लिए धन कहां से आएगा। दूसरी ओर यदि पुलिस इन सब को संरक्षण ना दे, तो वह अपने आकाओं को खुश कैसे रखेगी, कहां से महीना देगी । कहां से उनकी सेवा चाकरी करेगी फिर पुलिस यथार्थ में सरकारी सफेदपोश खाकी के गुंडे है।, सत्ताधीशों जो स्वयं सफेदपोश लोकतंत्र के गुन्डे होते हैं। जिन पर अनेकों पर अपराध होते हैं। सत्ता में आते ही पुलिस को कठपुतली बनकर अपने उपयोग के लिए नचाते हैं। तो स्वाभाविक है कि पुलिस ईमानदारी से काम करना चाहे, तो भी सत्ता में बैठे मंत्रियों सांसदों विधायको और उनके चेले चपाटी अपना आधार खसिकते देख पुलिसकर्मी अधिकारी को वहां रहने नहीं देते। भारत की पुलिस का तो इतिहास है, वर्तमान यथार्थ भी यहां अपराध रोकने से ज्यादा जरूरी है यहां पर जब तक कोई बड़ा अपराध न हो जाए, जनता सड़कों पर न निकरले ,तब तक माल आने दो। पुलिस को मोटी वसूली मिलती रहे। अपराध हो जाने के बाद सारे नेता मंत्री विधायक सांसद आसानी से पीड़ित को घड़ियाली आंसू दिखाते हुए सहानुभूति के 4 शब्द बोल कर अपनी वीडियो क्लिपिंग TV चैनल पर दिखा कर अपनी वाहवाही लूट सके। पुलिस की आपराधिकता के बारे में रोज देश की हजारों सत्र न्यायालय, उच्च, सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणियां करते हैं, समाचार पत्र , न्यूज चैनल पर उनकी भ्रष्टाचार लूट और वसूली की कहानियां पूरे देश में चला करती है परंतु इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता यह उनकी बेशर्मी, ढीठता का हीं पुरस्कार होता है। जनता पीड़ित चिल्लाते चिल्लाते मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है। उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। हजारो निर्दोषों पर मुकदमे लादकर अवैध वसूली की जाती है, देशभर के अधिकांश न्यायालयों को झूठे मुकदमों में उलझाकर रखा जाता है और हजारो दोषी शान से छल बल और धन के दम पर जिंदगी को मौज मस्ती मे गुजारते हुए निकल जाते हैं। यही सब अपराधियों को बढ़ावा देता है। इसी कारण इंदौर अपराधियों का भी पुलिस के संरक्षण में बड़ा अड्डा बनता चला जा रहा है। पुलिस की वर्दी का मतलब संयम, सेवा और सुरक्षा नहीं केवल इसकी तो नौटंकी करनी है। शाम होते ही मुफ्त की सुरा सुंदरी का जुगाड़ हो, मौज मस्ती हो, वह सब वह सब अपराधी गरिह उपलब्ध करवाता है। निसंदेह सिपाही और हेडसाब स्तर के कर्मियों को अवश्य दिन में 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, उन्हें कोई ज्यादा घास डालता भी नहीं। पर सहायक, उप,थाना, निरीक्षक से ऊपर तक सबके अपने2 मौज मस्तीन के नेताओं के संरक्षित आपराधिक माफियाओ के सन्चालति अड्डे होते है। जहां पर अधिकांश पुलिस निरीक्षक अपनी ड्यूटी में से समय निकालकर मौज मस्ती करने के लिए गायब हो जाते हैं ऐसे अपराधियों को इनका पूर्ण सरंक्षण मिलता रहता है। यह कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन भोपाल ग्वालियर से लेकर अधिकांश नगरों की है और यही कहानी पूरे देश के नगरों की है। निसंदेह देश में बेरोजगारी बढ़ने से अपराधियों का बोलबाला बड़ा है सब मोटी कमाई का साधन भी है पुलिस वालों के लिए।

सरकारी खाकी के पुलिसिया गुंडों का यथार्थ

एक बार एक दरोगा जी का मुंह लगा नाई पूछ बैठा –

"हुजूर पुलिस वाले रस्सी का साँप कैसे बना देते हैं ?"

दरोगा जी बात को टाल गए।

लेकिन नाई ने जब दो-तीन

बार यही सवाल पूछा तो दरोगा जी ने मन ही मन तय किया कि इस भूतनी वाले को बताना ही पड़ेगा कि रस्सी का साँप कैसे बनाते हैं !

लेकिन प्रत्यक्ष में नाई से बोले - "अगली बार आऊंगा तब

बताऊंगा !"

इधर दरोगा जी के जाने के दो घंटे बाद ही 4 सिपाही नाई की दुकान पर छापा मारने आ धमके - "मुखबिर से पक्की खबर मिली है, तू हथियार सप्लाई करता है। तलाशी लेनी है दूकान की !"

तलाशी शुरू हुई ...

एक सिपाही ने नजर बचाकर हड़प्पा की खुदाई से निकला जंग लगा हुआ असलहा छुपा दिया !

दूकान का सामान उलटने-पलटने के बाद एक सिपाही चिल्लाया - "ये रहा रिवाल्वर"

छापामारी अभियान की सफलता देख के नाई के होश उड़ गए - "अरे साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता ।

आपके बड़े साहब भी मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं !"

एक सिपाही हड़काते हुए बोला - "दरोगा जी का नाम लेकर बचना चाहता है ? साले सब कुछ बता दे कि तेरे गैंग में कौन-कौन है ... तेरा सरदार कौन है ... तूने कहाँ-कहाँ हथियार सप्लाई किये ... कितनी जगह लूट-पाट की ...

तू अभी थाने चल !"

थाने में दरोगा साहेब को देखते ही नाई पैरों में गिर पड़ा - "साहब बचा लो ... मैंने कुछ नहीं किया !"

दरोगा ने नाई की तरफ देखा और फिर सिपाहियों से पूछा - "क्या हुआ ?"

सिपाही ने वही जंग लगा असलहा दरोगा के सामने पेश कर दिया - "सर जी मुखबिर से पता चला था .. इसका गैंग है और हथियार सप्लाई करता है.. इसकी दूकान से ही ये रिवाल्वर मिली है !"

दरोगा सिपाही से - "तुम जाओ मैं पूछ-ताछ करता हूँ !"

सिपाही के जाते ही दरोगा हमदर्दी से बोले - "ये क्या किया तूने ?"

नाई घिघियाया - "सरकार मुझे बचा लो ... !"

दरोगा गंभीरता से बोला - "देख ये जो सिपाही हैं न ...साले एक नंबर के कमीने हैं ...मैंने अगर तुझे छोड़ दिया तो ये साले मेरी शिकायत ऊपर अफसर से कर देंगे ...

इन कमीनो के मुंह में हड्डी डालनी ही पड़ेगी ...

मैं तुझे अपनी गारंटी पर दो घंटे का समय देता हूँ , जाकर किसी तरह बीस हजार का इंतजाम कर ..

पांच - पांच हजार चारों सिपाहियों को दे दूंगा तो साले मान जायेंगे !"

नाई रोता हुआ बोला - "हुजूर मैं गरीब आदमी बीस हजार कहाँ से लाऊंगा ?"

दरोगा डांटते हुए बोला - "तू मेरा अपना है इसलिए इतना सब कर रहा हूँ तेरी जगह कोई और होता तो तू अब तक जेल पहुँच गया होता ...जल्दी कर वरना बाद में मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा !"

नाई रोता - कलपता घर गया ... अम्मा के कुछ चांदी के जेवर थे ...चौक में एक ज्वैलर्स के यहाँ सारे जेवर बेचकर किसी तरह बीस हजार लेकर थाने में पहुंचा और सहमते हुए बीस हजार रुपये दरोगा जी को थमा दिए !

दरोजा जी ने रुपयों को संभालते हुए पूछा - "कहाँ से लाया ये रुपया?"

नाई ने ज्वैलर्स के यहाँ जेवर बेचने की बात बतायी तो दरोगा जी ने सिपाही से कहा - "जीप निकाल और नाई को हथकड़ी लगा के जीप में बैठा ले .. दबिश पे चलना है !"

पुलिस की जीप चौक में उसी ज्वैलर्स के यहाँ रुकी !

दरोगा और दो सिपाही ज्वैलर्स की दूकान के अन्दर पहुंचे ...

दरोगा ने पहुँचते ही ज्वैलर्स को रुआब में ले लिया - "चोरी का माल खरीदने का धंधा कब से कर रहे हो ?"

ज्वैलर्स सिटपिटाया - "नहीं दरोगा जी आपको किसी ने गलत जानकारी दी है!"

दरोगा ने डपटते हुए कहा - "चुप र बाहर देख जीप में

हथकड़ी लगाए शातिर चोर बैठा है ... कई साल से पुलिस को इसकी तलाश थी ... इसने तेरे यहाँ जेवर बेचा है कि नहीं ? तू तो जेल जाएगा ही .. साथ ही दूकान का सारा माल भी जब्त होगा !"

ज्वैलर्स ने जैसे ही बाहर पुलिस जीप में हथकड़ी पहले नाई को देखा तो उसके होश उड़ गए,

तुरंत हाथ जोड़ लिए - "दरोगा जी जरा मेरी बात सुन लीजिये!

कोने में ले जाकर मामला एक लाख में सेटल हुआ !

दरोगा ने एक लाख की गड्डी जेब में डाली और नाई ने जो गहने बेचे थे वो हासिल किये फिर ज्वैलर्स को वार्निंग दी - "तुम शरीफ आदमी हो और तुम्हारे खिलाफ पहला मामला था इसलिए छोड़ रहा हूँ ... आगे कोई शिकायत न मिले !"

इतना कहकर दरोगा जी और सिपाही जीप पर बैठ के

रवाना हो गए !

थाने में दरोगा जी मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे - "साले तेरे को समझ में आया रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं !"

नाई सिर नवाते हुए बोला - "हाँ माई-बाप समझ गया !"

दरोगा हँसते हुए बोला - "भूतनी के ले संभाल अपनी अम्मा के गहने और एक हजार रुपया और जाते-जाते याद कर ले ...

हम रस्सी का सांप ही नहीं बल्कि नेवला .. अजगर ... मगरमच्छ सब बनाते हैं .. बस असामी बढ़िया होना चाहिए"।

...हमारे देश की पुलिसा का कटु सत्य

WhatsApp, Facebook

अत्यधिक घातक विश्वव्यापी बर्बादी की बीमारी

मोबाइल पर चिपकने और WhatsApp के चक्कर में आपकी स्वयं की परिवार की समाज की राष्ट्र की और दुनिया की कैसे बर्बादी हो रही है इस वीडियो को देख कर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं और सबसे ज्यादा बर्बादी महिलाओं और बच्चों की हो रही है।

जो अपनी पढ़ाई और गृह कार्य को छोड़कर इसमें चिपक कर अपनी यथार्थ मानसिक शारीरिक सामाजिक और आर्थिक बर्बादी पर तुले हुए हैं ।

संभालिए अन्यथा इस बर्बादी से आप स्वयं के साथ अपने परिवार समाज राष्ट्र और दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं।

आपकी स्वयं की उत्पादकता, सोचने की क्षमता, आपका शारीरिक और मानसिक विकास मुख्य रूप से 5 से 25 साल के युवाओं का, बर्बाद हुआ जा रहा है। यहां तक की आप अकर्मण्य और पौरुष हीन हुए जा रहे हैं।

समझे इस कटु सत्य को अन्यथा यह बीमारी सभी अन्य बीमारियों से ज्यादा घातक का लाइलाज हुई जा रही है।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

केंद्र-राज्य और निगमों में भाजपा की सरकारें, ऋण लो- घी पीओ। देश से धन बटोरो, विदेशी बैंकों में जमा करो

आखिर इंदौर नगर निगम को बांड जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी?

चारों तरफ लूट मची हुई है नगर निगम में सफाई के नाम 400 गाड़ियां खरीदी गई, प्रतिदिन रु12 से 15लाख का पेट्रोल डीजल के आधे हजम, खूब सड्कों के सुधार और मूत्रालयों, शोचालय, कचरा निष्पा दन केन्द्रो के, नालियों के निर्माण के नाम, सड़कों पर डिवाइडर के नाम अरबों रुपए हजम किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सभाओ में बर्बाद करो। 2015से मार्च 18 तक 21034 मवेशी पकडे। हाई कोर्ट में बताया मात्र साढे सात सौ पकड़े। उज्जैन में 15000खालें पकड़ी। इंदौर के मवेशीयो को कसाईयो बेंचा गया।

पूरे शहर में खूब कंक्रीट की सड़कें पहले बिना नाली के बनाई है। बाद में फिर नाली के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद करके उनको तोड़फोड़ दियाा। एक बार 8 इंच की पाइप लाइन डाली। उसका बिल भुगतान खा जाइए इसके बाद में पानी भराा तो फिर 1 फुट की पाइप लाइन डाली है। उसका भुगतान हजम। जब फिर पानी भरा डेढ़ फुट की पाइप लाइन डाली है सड़के फोड़ी। सडके खोदी तोड़ी-फोड़ी और खुले छोड़ दी गई। उस पर लोग और वाहन चालक गिरते-पड़ते रहें और मरते रहे पर इन गिध्दों की बला से कोई भी मरे । पहले काम होता है टेंडर जारी होते हैं ऑर्बिटल हो जाते हैं कोई नियम कानून नहीं प्रतिवर्ष 10 400 करोड़ से ज्यादा सड़कों पर बर्बाद कर दिए जाते हैं आखिरी वह पैसा किसका है। इसी प्रकार सफाई के नाम पी 400 से ज्यादा वाहन खरीदे गए जिसमें प्रतिदिन 12 से 15लाख रुपए का डीजल और पेट्रोल खर्च दिखाया जाता है जिसका आधा पैसा हजम कर लिया जाता है पहले दिन में 1-1 गाड़ी सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक 8 से 10 तक का लगा दी थी और वही गाड़ी दनि मे एक या दो बार ई कचरा उठाने आती है सारा पैसा कहां जाता है।

पहले जल आपूर्ति की पाइप लाइन तोड़िए फोड़िए, जनता को पानी के लिए चल्लि्ाने के लिए वबिस कीजिए टैंकर चलाइए उसमें भी डीजल पेट्रोल हजम कीजिए पानी बेचिए, और मोटी कमाई कीजिए। सड़कों की लाइटों को लगाने, सफाई के ठेके

में, और अनाप-शनाप बिना नियोजन के सड़कों का भवनों का निर्माण करवाइए। बाद में उन में तोड़फोड़ करवा दीजिए बगीचों में अनाप-शनाप उल्टे सीधे निर्माण कीजिए मोटे बिल बनाइए डकार जाइए। 70% सफाई कर्मी जो केवल कागजों पर ही है उनका धन हर माह करोड़ों में हजम कीजिए।

नगर निगम इंदौर ने सन 2015 से मार्च 2018 तक सूचना के अधिकार में दी गई जानकारी के अनुसार 21034 गाय इंदौर की सड़कों से पकड़ी। इसके विपरीत उच्च न्यायालय में लगी याचिका में नगर निगम ने जवाब में कहा साढे सात सौ गाय पकड़ी। जब गायों के बारे में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जितेंद्र ठाकुर ने अगला आवेदन लगा कर ही पूछा कि ये गाए कहां पर है और कैसी हैं उन पर निगम का कितना खर्च हो रहा है तो जानकारी देने में टालम टोली की जाती रही। और पत्र के जवाब मैं तो लिख दिया गया की जानकारी संकलति कर देने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि इन घोर भ्रष्ट धूर्त और मक्कारों की फौज ने हीं करोड़ों रुपए कमाकर गौ वंश अर्थात 20000 X10000= रु 20करोड़ नगर निगम आयुक्त मनीष सिंह, महापौर मालिनी गौड़, पार्षदों के साथ अधिकारियों ने भी बंदरबांट की । सूत्रों के अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर उन गायों का सौदा कसाइयों से किया उन्होंने गायों को काटकर मांस बैंच दिया और खालें जो हाल ही में उज्जैन के कंटेनर से 15000 पकड़ी गई। जो बेचने के लिए इंदौर से हैदराबाद ले जाई जा रही थी। अखलि हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की भनक लगते ही उन्होंने उज्जैन पुलिस को सूचित कर पकड़वा दिया। इंदौर में नगर निगम में पिछले 15 वर्ष से भाजपा के पार्षद व महापौर बैठे हुए हैं। यह है भुखेरा जन पार्टी का गोवंश प्रेम।

इस प्रकार से सभी पार्षद और अधिकारी, कर्मचारी मिलकर अरबों रुपए का हर साल घोटाला कीजिए और हजम कर जाइए और जब धन की कमी पड़े तो जनता के सिर माथे पर बांड खरीद लीजिए। किसी की कोई जांच लोकायुक्त कार्रवाई भ्रष्टाचार की नहीं होगी। क्यों कि सभी ने हीं हर साल अरबों रुपए की बंदरबांट में हिस्सा डकारा है।

अपनी लूट छुपाने और नक्कारखाने में तूती बजाने के लिए जनता के सर माथे पर जनता के धन से करोड़ों रुपए के कार्यक्रम करवाइए। जनता को लूटीये। हजम कर जाइए। सफाई, सड़क, नालियों, डिवाइडरों के नाम, और अपनी बदनामी बचाने के लिए अरबों रुपए साल के विज्ञापन बांटिए ताकि अपने को लूट के कुकर्मों का चिट्ठा समाचार पत्र वाले नहीं छापे, उन्हें 2-2-4 पेज के विज्ञापन दीजिए धन खत्म हो जाए तो बांड लीजिए ।

सरकारी संपत्तियों को गिरवी कीजिए। अरबों का धन डकार, फिर वेतन बांटने खूब चारों तरफ से ऋण लीजिए। यही हाल देश, प्रदेश और निगम की भूखेरा जन पार्टी की सरकार का है। अंत में हाथ पौंछकर चले जाइए । मुख्यमंत्री मंत्री, महापौर पार्षद निगम आयुक्त सारे इंजीनियर और सभी कर्मचारीयों ने क्या पार्षद बनने के पहले क्या थे वह वर्ष भर में उनकी कितनी संपत्तियां बढ़ गई किसी ने पूछने की जरूरत समझी। समाचार पत्र वाले डींगे हांक रहे निगम को राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में बांड के लिए ऋण मिल गया।

आखिर इंदौर नगर निगम को बांड जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी?

चारों तरफ लूट मची हुई है नगर निगम में सफाई के नाम 400 गाड़ियां खरीदी गई, प्रतिदिन रु12 से 15लाख का पेट्रोल डीजल के आधे हजम, खूब सड्कों के सुधार और निर्माण के नाम, नालियों के निर्माण के नाम, सड़कों पर डिवाइडर के नाम अरबों रुपए हजम किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सभाओ में बर्बाद करो।

पूरे शहर में खूब कंक्रीट की सड़कें पहले बिना नाली के बनाई है। बाद में फिर नाली के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद करके उनको तोड़फोड़ दियाा। एक बार 8 इंच की पाइप लाइन डाली। उसका बिल भुगतान खा जाइए इसके बाद में पानी भराा तो फिर 1 फुट की पाइप लाइन डाली है। उसका भुगतान हजम। जब फिर पानी भरा डेढ़ फुट की पाइप लाइन डाली है सड़के फोड़ी। सडके खोदी तोड़ी-फोड़ी और खुले छोड़ दी गई। उस पर लोग और वाहन चालक गिरते-पड़ते रहें और मरते रहे पर इन गिध्दों की बला से कोई भी मरे । पहले काम होता है टेंडर जारी होते हैं ऑर्बिटल हो जाते हैं कोई नियम कानून नहीं प्रतिवर्ष 10 400 करोड़ से ज्यादा सड़कों पर बर्बाद कर दिए जाते हैं आखिरी वह पैसा किसका है। इसी प्रकार सफाई के नाम पी 400 से ज्यादा वाहन खरीदे गए जिसमें प्रतिदिन बरस 1500000 रुपए का डीजल और पेट्रोल खर्च दिखाया जाता है जिसका आधा पैसा हजम कर लिया जाता है पहले दिन में 1-1 गाड़ी सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक 8 से 10 तक का लगा दी थी और वही गाड़ी दनि मे एक या दो बार ई कचरा उठाने आती है सारा पैसा कहां जाता है

इस प्रकार से सभी पार्षद और अधिकारी, कर्मचारी मिलकर अरबों रुपए का हर साल घोटाला कीजिए और हजम कर जाइए और जब धन की कमी पड़े तो जनता के सिर माथे पर बांड खरीद लीजिए। किसी की कोई जांच लोकायुक्त कार्रवाई भ्रष्टाचार की नहीं होगी। क्यों कि सभी ने हीं हर साल अरबों रुपए की बंदरबांट में हिस्सा डकारा है।

अपनी लूट छुपाने और नक्कारखाने में तूती बजाने के लिए जनता के सर माथे पर जनता के धन से करोड़ों रुपए के कार्यक्रम करवाइए। जनता को लूटीये। हजम कर जाइए। सफाई, सड़क, नालियों, डिवाइडरों के नाम, और अपनी बदनामी बचाने के लिए अरबों रुपए साल के विज्ञापन बांटिए ताकि अपने को लूट के कुकर्मों का चिट्ठा समाचार पत्र वाले नहीं छापे, उन्हें 2-5-7 पेज के हर दिनय विज्ञापन दीजिए धन खत्म हो जाए तो बांड लीजिए ।

सरकारी संपत्तियों को गिरवी कीजिए। अरबों का धन डकार, फिर वेतन बांटने खूब चारों तरफ से ऋण लीजिए। यही हाल देश, प्रदेश और निगम की भूखेरा जन पार्टी की सरकार का है। अंत में हाथ पौंछकर चले जाइए । मुख्यमंत्री मंत्री, महापौर पार्षद निगम आयुक्त सारे इंजीनियर और सभी कर्मचारीयों ने क्या पार्षद बनने के पहले क्या थे वह वर्ष भर में उनकी कितनी संपत्तियां बढ़ गई किसी ने पूछने की जरूरत समझी। समाचार पत्र वाले डींगे हांक रहे निगम को राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में बांड के लिए ऋण मिल गया।

सूचना के अधिकार के आवेदनों में हरामखोर लिखते हैं। की जानकारी संकलित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसी कौन सी जानकारी है? जो आवेदक मांगे और वहीं की टेबल पर से उठा कर यह आसानी से उसे दे दें। फिर अगर ईमानदार हैं। तो धारा 4 में इन भ्रष्ट गध्दिों की फौज ने अधिनियम के लागू होने के 13 वर्ष बाद भी अभी तक सारा हिसाब किताब, कितनी प्राप्तियां हुई कितना कहां खर्च किया। कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी, पार्षद, महापौर की व्यक्तिगत संपत्तियां और कुल आय व प्राप्तियां आदि का ब्यौरा अभी तक साइट पर सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। जनता का धन, बाप की जागीर है। जनता को लूटो, सफाई के नाम, पार्किंग के नाम, वह अन्य तरीके से और मनमर्जी से लूटो खाओ और खर्च करो।

आखिर मनीष रस्तोगी को क्यों दबाव से छुट्टी पर भेजा गया

हम भ्रष्टन के, भ्रष्ट हमार।
ईमानदारों को धक्का मार, कर बाहर।।

ईमानदारों के लिए मध्यप्रदेश और देश में कोई जगह नहीं। लाखों करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केवल लूट के लिए बनाए गए। इंदौर भोपाल के बीच एक्सप्रेस हाईवे 3500 करोड़ का केवल लूट के लिए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनीष रस्तोगी ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया में चलने वाले 2015 से 18 तक टेंडरों में हुए 5 लाख करोड़ के टेंडरों में हुए घोटालों को उजागर कर दिया था. जो कि मध्य प्रदेश लोक-स्वास्थ्य-यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश घर निर्माण मंडल, मध्य प्रदेश रोड डकैत कारपोरेशन, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश जल निगम, मध्य प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण प्रदेश के नगर निगमों नगर पालिकाओं, सिहस्थ, आदि में जारी हुए पिछले 3 सालों के लाखों-करोड़ के टेंडर जो सभी लोक निर्माण विभाग के बनाए हुए टेंडर के सॉफ्टवेयर के आधार पर काम करते थे।

यह टेंडर के सॉफ्टवेयर भी जो कि मात्र रू30-40 लाख में बनना चाहिए था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा 500 करोड़ रुपए में बनवाया गया। स्वाभाविक था 99.5% पैसा हजम कर लिया गया आखिर सॉफ्टवेयर में होता क्या है। केवल सॉफ्टवेयर बनाने वालों को चार छह महीने की नौकरी देकर जो कि मात्र रुपए 20 से 50000 में रखे जाते हैं बनवा लिए जाते हैं यही सॉफ्टवेयर सीडैक द्वारा 20 से 25 लाख रुपए मे बनाए जाते थे। यही हाल कोषालय के लिए बनाई गई सॉफ्टवेयर मैं भी हुआ रुपए 400 करोड़ में बनवाया गया टीसीएस से।

सन 2015 से सभी टेंडर जो रु10 लाख से ज्यादा होते हैं उन सभी को ऑनलाइन भरना पड़ता है। जिनके सभी ऑनलाइन भरे गए टेंडरों में जो कि सभी विभागों के मुख्यालयों मैं ही सारे विभागीय टेंडर भरे जाते थे। जिसमें वहां बैठे लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के सौगरिया, जल संसाधन विभाग के सुकलीकर, नर्मदा घाटी के सदस्य अभियांत्रिकी मालवीय, सड़क विकास डकैती निगम में वहां का प्रबंध संचालक, लोक निर्माण विभाग के परियोजना क्रियान्वयन इकाई में पि्र संचालक वर्मा, गृह निर्माण मंडल में आयुक्त रविंद्र सिंह, औद्योगिक केंद्र विकास निगम में जे एन व्यास, नगर निगमों और पालिकाओं के आयुक्त और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो घोर धूर्त मक्कार और भ्रष्ट हैं, अपने मनचाहे ठेकेदार को निविदा देने के लिए न्यूनतम निवदिा कर्ता को पीछे करने के लिए भरे गए निविदाओ मैं अपने खास लोगों से फेर बदल करवा कर अपने खास लोगों को टेंडर दिया जाता था। इस कार गुजारी से भरे गए टेंडरों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्रॉस का लाल निशान बन जाया करता था। जिसे मनीष रस्तोगी ने पकड़ कर उसे समझा और जानकारी निकालने पर मालूम पड़ा कि जिंन टेंडरों में फिर बदल किया जाता है। उसमें लाल निशान आ जाता है। इसकी खोजबीन करने पर मालूम पड़ा, यहां इस प्रकार पिछले 3 साल में 5 लाख करोड़ के टेंडर हुए थे। उनमें भारी फेरबदल कर हर प्रकार के टेंडरों में हजारों करोड़ का लेनदेन किया गया है। वैसे भी मुख्यालय जिसडमे मप्र के सभी कार्य

विभा ग टेंडर खोलने का मुख्य कारण हर टेंडर पर निवदिा कर्ता को कार्यादेश देते समय 2 से 5% की वसूली कर ली जाती है। यह रकम वह छोटी नहीं होती, जिसमें महा धूर्त मक्कार मुख्यमंत्री शविराज से लेकर से लेकर सभी विभागीय मंत्री यथा रामपाल सिंह, कुसुम मेहदेले, माया सिंह, लाल सिंह आर्य, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, रुस्तम सिंह, प्रधान सचिव, आजमगढ़ीया सुलेमान, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, सचिव, प्रमुख अभियंता, आयुक्त, प्रबंध संचालक, आदि सभी हिस्सेदार हैं। सभी ने हीं अपने खास लोगों को ठेकेदारों को टेडर देकर अरबों रुपए में धन हजम किया है।

मध्य प्रदेश के सड़क डकैती विकास निगम, नर्मदा घाटी, गृह निर्माण मंडल, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम, प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, देवास, उज्जैन आदि के विकास प्राधिकरणो मैं कालोनियों के विकास के नाम पर भी इसी प्रकार हर टेंडर जो सैकड़ों से हजारो के करोड रुपए के टेंडर में, वही स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों रुपए के हर टेंडर मैं जो पिछली 3 सालों में 50000 करोड़ से ज्यादा के थे। पूरे मध्यप्रदेश में भोपाल के मुख्यालयों में हजारों करोड़ रुपए हजम किए गए बदले में जनता पेट्रोल डीजल गैस पर 32 से 36% की हर दनि हजारों करोड़ में लूट की जाती रही इसलिए यहां पर पेट्रोल डीजल और गैस देश में सबसे ज्यादा महंगी बिक रहे हैं। यह पोल खुलते ही, आने वाले चुनाव में भाजपा की धज्जियां बिखर जाएंगी। इसलिए उसकी जड़ पकड़ मनीष सिंह को ही जबरन छुट्टी पर भेज कर सारे कांड पर लीपापोती कर दी गई। बेशक इस कहानी का छोटा सा अंश पत्रिका ने भर छापा, ताकि वसूली भी पूरी हो और हडकंप भी चारो तरफ मच जाएं। जबकि यह खेल सॉफ्टवेयर बनाने के साथ ही उसमें यह व्यवस्था कर दी गई थी ताकि आसानी से यह फेरबदल आवश्यकता अनुसार किया जा सके। अपनों को टेंडर देकर उपकृत किया जा सके। इसमें सबसे बड़ा खेल कुछ खास कंपनियों L&T, दिलीप बिल्डकॉन, आदि के लिए विशेष तौर से किया गया। सड़कों और पुलों के अधिकांश ठेके दिलीप बिल्डकॉन के पास में है।

भड़ुवे भास्कर, नई दुनिया व अन्य सभी बड़े समाचार पत्र व न्यूज़ चैनल्स सब चुप बैठे हुए हैं सब महीने से बंधे हुए हैं।

कांग्रेसियों को चाहिए इस मुद्दे की गहराई से छानबीन कर मध्यप्रदेश में स्मार्ट सिटी, बड़े सड़क निर्माण, पुलो, बड़ी हाउसिंग कालोनियां झुग्ग्र्र्यो को हटाकर गरीबों के नाम बनाई गई, हजारों करोड़ की नर्मदा घाटी की नहरों के निर्माण के नाम, एक तरफ जो हजारों करोड हडपा गया और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल में 32 से 36 परसेंट की लूट की गई के बारे में जनता को सच बताएं भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

नघा भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण मे मुमं, प्रस, अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, आयुक्त, संचालकों, सदस्यों से उपयंत्रियों तक सब का जालसाजी से विकास। 25 से ज्यादा उद्ववहन परियोजनाएं केवल लूट के लिए।

नर्मदा घाटी, शासकीय भ्रष्ट जालसाज डकैतों का विकास प्राधिकरण का अड्डा

घाटी विकास प्राधिकरण यथार्थ में भ्रष्टाचार विकास का कार्य चल रहा है। यहां तक कि पिछले 40 सालों से स्थापित कृषि संचालक जो भूमि संरक्षण का कार्य देखते हैं अभी तक उसका विभाग की साइट पर नामोनिशान नहीं है जिसके मध्य प्रदेश में करीबन 13 कार्यालय कार्य करने के उपरांत भी विभाग की साइट पर आज तक संचालक कृषि के नाम से ही कोई पद नहीं बताया गया जबकि नर्मदा घाटी कृषि संचानालय में इंदौर खंडवा जबलपुर मैं उपसंचालक स्तर के संभागीय भूमि संरक्षण अधिकारी जो कि खंडवा इंदौर खरगोन में बैठते हैं सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी मनावर, कुक्षी क्रमांक 7, कसरावद क्र. 17, बड़वानी क्र.11, हरदा, खंडवा क्र.1, हरसूद क्र.2, सेंधवा क्र.14, महेश्वर क्र.6, में बैठते हैं।जो कि संचालक मंडल का सदस्य भी है। संचालक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर कौन है और उसका आधिकारिक कार्यालय कहां पर है। यह भी इस साइट पर आज तक नहीं दिखाया गया। सन 2000 तक इस पूरे विभाग का आवंटित धन ऊपर का ऊपर ही हजम किया जाता रहा। जब मध्य प्रदेश महालेखाकार की टीम इसका ऑडिट करने पहुंची तब तक न विभाग का पता था और न ही कर्मचारियों का। संचालक कृषि एवं भूमि संरक्षण का सारा पैसा आवंटित होने के बाद में भी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान सचिव अध्यक्ष उपाध्यक्ष आयुक्त उस धन का जो कि कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन भत्तों से लेकर कार्यालयों के किराए व अन्य कार्यों के लिए मिलता था। हजम कर लिया जाता था। वर्तमान में भी यहां बैठा अध्यक्ष महा धूर्त निकम्मे और महाभ्रष्ट घोर लालची राकेश साहनी जिसे मुख्य सचिव से रिटायर हुए10साल से ज्यादा गुजर चुका है। परंतु शासकीय सुख सुविधाओं और इस घाटी में होने वाले भ्रष्टाचार से प्राप्त होता, धन प्राप्त करने के लिए मृत्यु तक यही जमा रहेगा क्योंकि उसके पास मुख्यमंत्री शिवराज की अनेकों भ्रष्टाचार की जानकारियां हैं जिनलके दम पर मुख्यमंत्री शिवराज को ब्लैकमेल कर किसी न किसी पद पर जमा रहता है। वही हाल रजनीश वैश्य का भी है। पिछले 7 वर्षों से ज्यादा समय से ही यह घोर निकम्मा और भ्रष्ट वर्तमान में इस विभाग में उपाध्यक्ष, सदस्य पुनर्वास, प्रधान सचिव, आदि के पद संभाल रहा है। बेशक यह भी पिछ ले साल सरदार सरोवर में किए गए डेढ़ सौ से ज्यादा पुनर्वास केंद्रो पर अरबों रुपए विकास में खर्च किए गए। हजम कर लिया गया जबकि जिन विभागों से जिसमें लोक निर्माण विभाग का धार बड़वानी झाबुआ संभाग, इंदौर विद्युत यांत्रिकी संभाग जिसने वहां पुनर्वास केंद्र स्थापित किए थे। लाइटिंग पंखो टीनशेड आदि की व्यवस्था 150 से ज्यादा स्थानों पर लगभग 5लाख लोगों के लिए की थी का पूरा पैसा आज तक भुजतान नहीं किया गया है। इस पुनर्वास व पुनर्निर्माण का पैसा इंदौर संभागायुक्त और पुनर्वास आयुक्त के द्वारा खर्च किया गया हजम कर लिया गया। विस्थापितों के लिए बसाहट की कॉलोनाइजेशन की व्यवस्था में लगे हुए बड़वानी क्रमांक 1, धर्मपुरी संभाग क्रमांक 2 लोक निर्माण विभाग नर्मदा घाटी का अरबों रुपए का काम पिछले कई वर्षों से विस्थापितों को स्थाई रूप से बसाने के लिए चल रहा था।निर्मित किए गए भवन प्लॉट और नगरीय विकास न केवल स्तरहीन, और कामचलाऊ थे। जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार बरसो से चल रहा है। यही हाल इस

> घाटी के विकास व निर्माण के काम करने वाले ठेकेदारों को जो कि अत्यधिक धीरे कार्य करते हैं विभागीय यंत्री जानबूझकर समय वृद्धि, कीमतें बढ़ने का लाभ देकर स्वंम भी मोटा धन कमाते हैं। सभी कार्य न करने वाले 10वर्ष से ज्यादा लंबित कार्य न करने वाले ठेकेदारों काली सूची में क्यों नहीं।

A VIEW OF R.M. 3 AT R.D.1000 M.

विभाग के विद्युत यांत्रिकी का भी है जिसका मुख्य अभियंता, कई वर्षों तक सेवानिवृत्ति के बाद में भी परिहार बैठा हुआ है जो वर्तमान में सलाहकार के रूप में शासकीय वेतन-भत्तों का उपयोग कर सुविधाओं का उपभोग कर रहा है। सदस्य अभियांत्रिकी पद पर महाभ्रष्ट, मूढ़, आर पी मालवीय कोई भी आर्थिक मामलों की, वित्तीय प्रबंधन की अ,ब, स, द नहीं आती फिर भी वित्तीय सदस्य बना दिए गए। बलवाड़ा 5000 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए 52.78 करोड, मालवा गंभीर 50000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए2187.21 करोड छैगांव माखन 35000है. सिंचाई के लिए रू 784.10 करोड, अलीराजपुर 35000 हेक्टेयर के लिए रुपए 833.35 करोड, छिपानेर रु 516.11 करोड, भीकनगांव बाँजेवाड़ा रु745 करोड, चौड़ी जामनिया रू68.36करोड, बलकवाड़ा रु123.96करोड, जावर रु466.91करोड,, अंबा रोडिया रु138.29करोड, सिंमरोल अँबाचंदन रु59.13करोड, ढीमरखेड़ा रु256.16 करोड, चिंकी सूक्ष्म सिंचाईरु1494.64 करोड, अधिकांश जल उद्ववहन सिंचाई परियोजनाएं केवल दिखाने देखा नहीं और धन हजम करने के लिए की बनाई जाती है क्योंकि अधिकान्श उद्ववहन भारी रखरखाव और बिजली के भारी खर्च के कारण ज्यादा बरसों तक चल नहीं पाती। फिर भी मोटा धान हजम करने के लिए ऐसी योजनाओं को लगातार यह भ्रष्टाचार प्राधिकरण बना रहा है। इन परियोजनाओं में बताई गई सिंचित भूमि का लक्ष्य भी निर्धारित से 60% से ज्यादा कभी पूरा नहीं हुआ। वह भी जब सिंचाई के लिए लगातार 24 घंटे 7 दिन लगातार बिजली मिलने पर यदि पंप चालु रखे गये। तब भी निर्धारित प्राक्कलन मैं दिखाई गई भूमि का सिंचित होना संभव नहीं होता जबकि अधिकांश जल उद्ववहन परियोजनाओं में मैंने कभी भी 24 घंटे सातो दिन पंप नहीं चलाये जाते। यही कारण है पूरे भारत में सभी राज्य सरकारों की जल संसाधन विभाग ने 1980 के बाद से उद्ववहन परियोजना पर काम करना बंद कर दिया। क्विकर भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में हजारों करोड़ की जल उद्धवहन परियोजनाओं पर जबलपुर और इंदौर संभागों में कर दलित किया जा रहा है तो केवल मोटा धन हजम करने के लिए जो लगभग हर योजना का 25% होता है। इस बंदरबांट में मुख्यमंत्री, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य अभियांत्रिकी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण, कार्यपालन सहायक उपयंत्री तक सब का मोटा हिस्सा होता है। 2014 में निर्मित की गई नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना में यह देखा जा सकता है। वर्षा ऋतु के 4 महीने छोड़कर, यहां पर भी 8 महीनों के 5800 घंटों में 200 घंटे भी पंप नहीं चलाये गये। जब की परियोजना पर रुपए ढाई हजार करोड खर्च कर दिया गया।

साथ ही विभाग की साइट पर ओमकारेश्वर की दाँई बाँई तट नहर जिसमें 10 साल बाद अभी काम पूरा नहीं हुआ और ठेकेदार को स्वीकृत लागत से दुगनी से ज्यादा भुगतान करने के साथ ही 18 वा समय विस्तार देने की तैयारी चल रही है। घोर हरामखोर जालसाज ठेकेदारों जिसमें करण सिंह सोम बिल्डर्स, बी के बियानी भुसावल,जैसे नर्मदा घाटी के दामाद ठेकेदारों जिसने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की हर योजना को लंबित कर दोगुने से ज्यादा भुगतान लिया और निर्धारित समय से 4 गुना समय में भी किसी भी कार्य को पूरा कभी नहीं किया इसके बाद में भी इन ठेकेदारो को न तो ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और ना ही उस पर क्षतिपूर्ति का प्रकरण दर्ज किया गया। इस विभाग में कदम कदम पर सहायक यंत्रियों, कार्यपालन यंत्री जिसमें एस एन मीणा 25-28 नंबर संभाग में बरसों से जमे हैं यही हाल संभाग क्रमांक 30 में मैं बैठे उइके का भी है। दोनो ने भारी भ्रष्टाचार किया है परंतु जब नीचे से ऊपर तक सभी भ्रष्ट हैं तो भ्रष्टो को पालना और मोटा धन कमाना आवश्यकता बन चुका है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर मुख्यालय पर बैठे हुए शूकर आर पी मालवीय अपने मुख्य अभियंताओं, अवंती सागर नहरे, मुख्य अभियंता बांध जबलपुर, निम्न नर्मदा परियोजना इंदौर, इंदिरा सागर नहर सनावद, के विरुद्ध अपील लगाने पर क्योंकि सबसे महीना मिलता है सब को निरस्त कर देता है। साथ ही इस विभाग में सूचना के अधिकार में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी, आदि के विरुद्ध अपील की सुनवाई की कोई व्यवस्था नहीं। वही हाल संचालक कृषि, मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी, पर्यावरण और वन, सदस्य पुनर्वास, ऊर्जा, आदि सभी जानकारी न मिलने पर अपील लगाने की कोई व्यवस्था नहीं और ना ही इनका उपाध्यक्ष या अध्यक्ष इनकी सुनवाई की औपचारिकता भी पूरी करता है। बदले में ऐसी भेजी गई सारी अपील और आवेदन कचरे की टोकरी में डाल दी जाते हैं। क्योंकि नर्मदा घाटी यथार्थ में भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण है। जहां कार्य से नहीं, परियोजनाओं, विस्थापन, वनीकरण ऊर्जा विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार से धन हजम करने से है। यहां तक कि इन हरामखोरों ने जालसाजों ने सूचना का अधिकार को लगे हुए 13 साल गुजर जाने के बाद में भी अपनी विभाग की साइट पर भी न तो पूरी जानकारियां डाली हैं। धारा 4 के अंतर्गत 17 बन्दिुओ की हर विभाग की, हर संभाग की, उपयोग किए गए धन की,वहां बैठे स्टाफ की, पूरी जानकारी डालनी चाहिए थी। मात्र भ्रष्टाचार बचाने और जालसाजियां करने के लिए नहीं डाली जाती और ना ही इस पर कभी कोई न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया।

ये धूर्तों की फौज सूचना के अधिकार को मजाक समझ मुश्किल से ही आवेदन पत्र का जवाब देने की जहमत उठाते हैं। फिर इन मक्कारो से यह उम्मीद करना कि इन्हें भेजे गए आवेदन पत्र मैं चाही गई जानकारी उपलब्ध ना होने पर यह निकम्मे भ्रष्ट शूकरो की फौज धारा 6(3) के अंतर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अंतरित करेगी। संभव ही नहीं क्योंकि वे ही सब अधीनस्थ कार्यालय इनके द्वारा भेजे गये धन का कागजी जमा खर्च दिखाकर 30 से 40% तक इन्हें वापस लौटाएंगे। तो यह कैसे संभव है कि वह फर्जी जमा खर्च के दस्तावेज सूचना का अधिकार में इस सच्चाई को उजागर करने, जन हितों की रक्षा करने वाले घोर दुष्ट पत्रकार अजमेरा को चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार में दे दी जाए।वैसे ही इस पत्रकार अजमेरा को पूरा नर्मदा घाटी विकास विभाग का हर इंजीनियर सामने भले ही कुछ न बोलें पर पीछे तो न केवल गालियां बकते हैं। वरन उसे निपटाने के लिए भी सोचते हैं।

जबकि यहां बैठे हुए घोर बेशर्म, मक्कार, हरामखोरों की फौज जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नर्मदा घाटी विकास मंत्री अध्यक्ष राकेश साहनी, उपाध्यक्ष रजनीश वैश्य, मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य प्राणी जी पी वर्मा, सदस्य वित्त एवं अभियांत्रिकी आर पी मालवीय ऊर्जा से लेकर संभागों में उपसंभागों में बैठे, भूमि संरक्षण कार्यालयों में, आयुक्त कार्यालय में बैठे आयुक्त, संयुक्त संचालक, सदस्य, भू अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अलीराजपुर, बड़वानी, कुक्षी, मनावर, भीकनगांव, खरगोन, धर्मपुरी, ठीकरी, न केवल सरकार की सुख सुविधाएं भोगते, जनधन को हजम करते हुए, विद्युत और सिंचाई की सेवाओं से करोड़ों किसानों को वंचित भी कर रहे हैं। जबकि इन परियोजनाओं में जबलपुर के बरगी बांध और नहरों, इंदिरा सागर बांध और नहरों, ओंकारेश्वर बांध और नहरों, सरदार सरोवर बांध की डूब में 50लाख से ज्यादा लोग विस्थापित किए गए और लगभग 2लाख हेक्टेयर जमीन जिसमें एक लाख से ज्यादा अच्छी कृषि भूमि थी डुबो दी गई पर इन हरामखोरों को इससे अरबों रुपए की कमाई ही हुई और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि सरदार सरोवर में तो प्रदेश को भीषण तबाही ही झेलनी पड़ी। पर शिवराज पर भ्रष्टाचार, जालसाजियोन, कुकर्मो की गठरी इतनी भारी थी की वह तानाशाह मोदी के सामने मुंह भी नहीं खोल सका और उसकी इच्छा के अनुकूल सरदार सरोवर में 300 से ज्यादा गांव को डुबोकर बांध को भरा गया इसके लिए जबलपुर के बरगी बांध, पुनासा के इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर के बांध के द्वारों को खोलकर वर्षा कम होने के विपरीत भी पानी खाली कर दिया गया। जिससे मध्य प्रदेश के जबलपुर भोपाल इंदौर के साथ 20 से ज्यादा छोटे शहरों और तटों के दोनों तरफ बसे हुए 5000 से ज्यादा गांवों की पेय जल, सिंचाई के साथ मछली पकड़ने वन एवं दुग्ध उद्योग धंधों को की व्यवस्था चौपट किया गया। वर्ष 2016-17 स्वीकृत किए गए रु2487.62 करोड मै से रु1392.23 करोड खर्च किए गए। मात्र रु300 करोड़ की बंदरबांट हुई। वैसे भी नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण सभी मुख्यमंत्रियों के लिए सबसे मोटी दुधारु गाय सिद्ध हुआ है

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

वरिष्ठता को नकार रुपए तीन करोड़ मैं प्रभारी प्र.अ.बनाया सोनगरिया को,

लो. स्वास्थ्य मंत्री, प्र.स.,प्रअ. भ्रष्टाचार सुधार रहे स्वास्थ्य, निकम्मी, भ्रष्ट, बीमार मंत्री के रहते पूरे विभाग का स्वास्थ्य ही चौपट

मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अपने भ्रष्टाचार पूर्ण कार्य शैली के लिए प्रारंभ से ही बदनाम रहा है उस पर निहायत निकम्मी भ्रष्ट और बीमार रहने वाली कुसुम मेहदेले के हाथ में ऐसे विभाग की कमान सौंप देने से पूरे विभाग का स्वास्थ्य ही चौपट हो चुका है। इसी के भ्रष्टाचार और जालसाजों का ही परिणाम 2017 जीएस डामोर जैसा 6 हत्याओं को अंजाम देकर और सैकड़ों भ्रष्टाचारों से सैकड़ों करोड इकट्ठा करने, जिसमें भोपाल और झाबुआ का पेट्रोल पंप, झाबुआ में दुकानों का पूरा मार्केट व सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि इंदौर का 54 नंबर का बंगला,भोपाल इंदौर झाबुआ मैं अनेको अन्य संपत्तियां आदि है।

बेशक श्रीमती सूरज डामोर ने भी हर पद और स्थान पर रहते हुए भारी भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए, सचिव स्वास्थ्य रहते हुए सैकड़ों स्वास्थ्य विभाग की जाचो पर जिसमें अनेकों डॉक्टरों जांच के बाद कारवाही करने की अनुशन्सा कर दी गई थी। अप्रैल मई-जून के चार महीनों में सबसे लाखों की वसूली की गई बाद में स्वास्थ्य विभाग या इस भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस वाले मुख्य-मंत्री ने अपना मोटा हिस्सा डकार ऐसी महाभ्रष्ट को अंबेडकर विश्वविद्यालय महु का कुलपति बना दिया। बेशक इसके अपराधिक, महाजालसाज पति डामोर से स्वयं मुख्यमंत्री, लोक-स्वास्थ्य-यांत्रिकी मन्त्री कुसुम मेहदेले प्रधान सचिव मनोज गोविल ने रुपए 5 करोड़ हजम कर 30.4.17 को सेवानिवृत्ति से पूर्व 11 माह का सेवा विस्तार देने की तैयारी पूरी कर ली थी। पर इस अपराधिक भ्रष्ट से त्रस्त पूरे स्टाफ ने भोपाल से गुहार लगाई की इसकी विदाई सुनिश्चित करो वरना यह और भ्रष्टाचार करेगा अंत में सारे राजधानी में टीवी च समाचार सेवा के पत्रकारों को कहानी बता घेरने के लिए निवेदन किया तब राजधानी भोपाल के अधिकांश टीवी चैनलो ने प्रसारण किया और समाचार पत्रों ने छापा तो 4 मई तक भी मंत्री मेहदेले प्र.स. गोविंल और मुख्यमंत्री उस धूर्त की सेवा विस्तार देने पर अड़े रहे। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शिकायत की गई, ए्और प्रधानमंत्री कार्यालय से पुछताछ प्रारंभ हुई तब डामोर की विदाई निश्चित की गई तब भी उसने अपने ही खास सलाहकार व वफादार मित्र सोंन्गरिया को जो उसके साथ कई भ्रष्टाचारों में शामिल रहा, उसके सभी भ्रष्टाचारियों को बचाया। साथ ही उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वालों को श्याम दाम दंड भेद के साथ इंदौर मेकेनिकल के कार्यपालन यंत्री चेतन रघुवंशी को जो कि उसके खिलाफ हाईकोर्ट में इंदौर और जबलपुर में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में विभाग की तरफ से प्रभारी था, को परेशान करने में भी मुख्य भूमिका निभाई। जबकि उनके विरुद्ध हैंड पंप लगाने और खुदाई करने की जांच मैं लोकायुक्त ने 18.3.18 को जांच में कुछ ना पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री चेतन रघुवंशी को निर्दोष करार दिया।

विभागीय मंत्री कुसुम महदेले भ्रष्टाचार और बदतमीजी के अनेको किस्से् अखबारों में छप चुके हैं। मोटा धन नहीं तो काम नहीं। भूतपूर्व सलाहकार प्रमुख अभियंता डाबर सेवानिवृत्ति के बाद में भी चैन से नहीं बैठा हुआ है। उसके परम शत्रु रहे अधीक्षण यंत्री सी के सिंह की पदोन्नति का लिफाफा जो इस हत्यारे जालसाज भ्रष्ट और मक्कार डाबर ने हीं, विभागीय पदोन्नत समिति की बैठक में पदोन्नत सीके सिंह का लिफाफा2013 से रखवाया गया है ताकि वह पदोन्नत होकर इसके पुराने भ्रष्टाचार के ढेर सारे कांडों की जांच ना खोल दी जाएं मुख्य अभियंता ना बन जाए। सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 5-6 पत्र भेजने और उस लिफाफे को लौटाने के लिए लिखा। परंतु इस धूर्त मक्कार मंत्री महदेले ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया इसके पीछे मात्र धन ही एक कारण था। अर्थात बिना पैसे के कुछ भी काम करने से इंकार कर दिया है।

इसलिए वरिष्ठता में मुख्य अभियंता संकुले को नजरअंदाज कर रु3 करोड़ की मोटी डील कर सोन्गरिया को प्रभार सौंपा गया। पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। जिसे जानबूझकर प्रदेश के धुर्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भारी जन धन खर्च कर सामान्य वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों के साथ छल करते हुए अटका रखा है। उसके कारण प्रदेश में सेवानिवृत्ति के बाद अधिकांश अधिकारी, कर्मचारी 2-3 पदों का कार्यभार संभाल रहे हैं।वही हाल इस विभाग का भी है। यहां पर भी सोन्गरया कार्यभारित प्रमुख अभियंता के पद के साथ इंदौर के मुख्य अभियंता भी है। जबकि यहां पर भी किसी अधीक्षण यंत्री को मुख्य अभियंता का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए था परंतु यहां ऐसा नहीं किया गया। अर्थात सोन्ग्रिया जो डाबर के काफी वफादार है, भोपाल में बैठकर इंदौर के मुख्य अभियंता पद का भी कार्य चला रहे हैं। इस प्रकार पूर्व प्रभारी प्रमुख अभियंता डाबर के कुकर्मों को जो इन्होंने इंदौर और भोपाल में किए थे को बचाने का व ठंडा करने का कार्य करवाया जा रहा है। क्योंकि डाबर के विरुद्ध अभी भी लोकायुक्त की कार्यवाही लंबित है।यही कारण है, कि यहां पर भी सूचना का अधिकार में जानकारी मांगने पर यहां बैठे हरामखोर कर्मचारी और अधिकारी न तो धारा 6(3) में आवेदन की प्रतियां अपने अधीनस्थ अधीक्षण व कार्यपालन यंत्री को भेजते हैं।न ही यह शुकरो की फौज आवेदन पर कार्यवाही करते हैं। अपील लगाने पर भी अपील की सुनवाई के लिए प्रमुख अभियंता भोपाल बुलवाता है। ताकि अरबों रुपए के भ्रष्टाचारों का दस्तावेजी सबूत देने से हर हाल में बचा जाए। वैसे तो पूरा विभाग सूचना का अधिकार में जानकारी देने के नाम पर जालसाजियो से बचने के अलावा कुछ नहीं करता। जैसे पूरा विभाग उसकी सारी जानकारियां उनके बाप की जागीर हो। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहने के कारण इन हरामखोरो ने धारा 4 के अंतर्गत विभाग की 13 साल के बाद में भी जानकारी साइट पर अपलोड नहीं की। मुख्य अभियंता कार्यालय और अधीक्षण यंत्री कार्यालय में जानकारी मांगने पर यहां बैठे घोर निकम्मे और मक्कार अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज कभी भी धारा 6(3) में उसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में नहीं पहुंचाती और हर समय हरामखोर इकबाल अहमद के फैसले की दलील देते हैं। जैसे इकबाल अहमद का फैसला जो कि पैसे लेकर करता था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की तरह कानून बन गया हो। इसकी आड़ में यह हरामखोरों की फौज और मुख्यालय की फौज कभी भी पत्रों को अंतरित नहीं करती। और इस प्रकार पूरा विभाग ना तो स्वयं जानकारी साइट पर अपलोड करता है और ना ही आवेदकों को उसकी जानकारी पत्रों के माध्यम से देता है।

यही कारण है, कि उसके खास चेले कार्यपालन यंत्री संतोष श्रीवास्तव को इंदौर में भारी भ्रष्टाचार करने के कारण, गांव में पेयजल की व्यवस्था के लिए बनाए गए स्टॉप डैमो जो कागजों पर ही बनाए गए का अधिकांश पैसा हजम कर लिया गया । जिसमें महू गांव के 55 गांव की नल जल योजना का पैसा हड़पने, विभाग के पाइपों को कबाड़ में बेचने, यह पुनरावृत्ति संतोष श्रीवास्तव जब सहायक यंत्री नगर निगम इंदौर हुआ करते थे। तब भी की गई थी कि उन्होंने टनो से नगर निगम के जी आई पाइप तुडवाकर कबाड़े में बैचकर पैसा हजम कर लिया था। उनकी यही भ्रष्टाचारी कार्यपद्धती खरगोन संभाग में भी यथावत चल रही है। उसके स्थानांतरण के बाद यहां पर पदस्थ की गई कार्यपालन यंत्री श्रीमती मंजू सिंह भी सूचना के अधिकार में दयि पत्रों के जवाब ही नहीं देती हैं और जब अपील लगाई जाती है तो पुरानी तारीख में पत्र का जवाब देना दिखला कर, जिसमें राशि की मांग की गई होती है । अपील के समय प्रस्तुत कर के आसानी से बच लेती हैं जिसे यह धूर्त रत्नावत स्वीकार कर लेता है। बाद में अपील के निराकरण की जवाब में पैसे जमा करो और जानकारी ले जाओ का आदेश कर देता है। इस प्रकार से यह महिला अधिकारी भी जालसाजी पूर्ण तरीके से जानकारी देने से बचती हैं।

अपने पुराने पापों को धोने जोकि जो कि डाबर ने करोड़ों के घोटाले की है। धार, उज्जैन, खरगोन व अन्य संभागो में रहते हुए किये थे जिसके पीछे लोकायुक्त जांच लंबित है। कार्यपालन यंत्री संतोष श्रीवास्तव को खरगोन में पदस्थ कर दिया गया। दूसरी तरफ धार में बैठे 5 साल से ज्यादा जमे कार्यपालन यंत्री राजीव खुराना जिसने वहां बरसों से बैठकर कई घोटालों का अंजाम दिया। कई विभागीय इंजीनियरों के रिश्तेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के बाद में भी काम करवाए गए। साथ ही पेयजल के लिए नल जल योजना, स्टॉप डैम आदि में भी करोड़ों के घोटाले किए और सबको पैसा बांटा इसलिए उसे 5 वर्ष के बाद में भी वहां से स्थानांतरित नहीं किया जा रहा। इस हरामखोर से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हरामखोर हमेशा लंबे चौड़े ब---- भेजकर जानकारी देने से बचता रहा है। पिछले 5 सालों से ही जितनी भी अपील धार संभाग के विरुद्ध लगाई गई। किसी भी अपील में यह भ्रष्ट खुराना कभी उपस्थित नहीं हुआ जबकि वह स्वयं लोक सूचना अधिकारी था और हर बार अधीक्षण यंत्री ने मोटा पैसा लेकर उसे बचाने के लिए कोई ना कोई कारण लेकर अपनी नरिस्त कर दी।

वैसे तो यह कहानी पूरे मध्यप्रदेश के हर संभाग की है। और यदि संभागीय कार्यपालन यंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो अपने अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता से लेकर प्रधान सचिव और मंत्री को कहां से मोटी टिप मार अपने आप को बचाएगा। इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और लूट ऊंची कीमतों पर अनावश्यक रुप से पाइपों हैंडपंपों आदि की खरीदने की जाती है। अनावश्यक खरीद प्रकरण अरबों रुपए प्रतिवर्ष का स्टॉक खराब हो जाता है जिससे ओने पोने में बैच कर पैसा हजम कर लिया जाता है। सिहस्थ 2004र्और 2016 मैं भी यह कहानी दोहराई गई इसमें यहां बैठे महाभ्रष्ट और जालसाजी कार्यपालन यंत्री धर्मेंद्र वर्मा अधीक्षण यंत्री रत्नावत, मुख्य अभियंता सोन्गरमया,ने अनावश्यक रुप से रुपए ढाई सौ करोड़ से ज्यादा के लोहे प्लास्टिक विभिन्न साईजो के पाइप खरीदने के आदेश नवंबर दिसंबर 2015 में ही जारी कर दिए थे इसके बावजूद भी फरवरी 2016 में भी आवश्यकता बता कर लगभग रुपए 100 करोड़ से ज्यादा की और खरीदी की गई उस पाइप की डिलीवरी अप्रैल 2016 में प्राप्त हुई। जब सिहस्थ खत्म होने के लिए आ गया था। वह करोड़ों रुपए का लोहे और प्लास्टिक का पाइप कोई काम नहीं आया। पर खरीदी में 25 से 30-40% का कमीशन सबसे मुख्य कारण था ।यह पद्धति 40 साल पुरानी होने के साथ इसमें जितने भी सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता से लेकर प्रधान सचिव और मंत्री तक सब बहुत ही आसानी से बिना जरूरत के अरबों की मोटी खरीदी करके करोड़ों का कमीशन हजम कर जाते हैं।

यही हाल इंदौर के नगर निगम में पेय जल हेतु नर्मदा जलापूर्ति में बैठे कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव का भी है जो कि पिछले 5 साल से एक ही स्थान पर जमा रहकर भारी भ्रष्टाचार कर रहा है वह भी भारी खरीदी जिसमें हर खरीदी में जीएसटी के पूर्व लगने वाले वक्रियकर और एक्साइज की छूट रहती थी। के विपरीत हर बलि पर करों का भुगतान किया जाता था। बाद में उन करों में आपूर्तिकर्ता के साथ मिलकर भारी बंदर बांट कर ली जाती थी और यह कार्य पिछले 40 सालों से चल रहा था। यहां पर भी झूठे, और छोटी टूट-फूट मरम्मत के बिलो के भारी भरकम भुगतान किए जाते रहे हैं। हाल ही में संजीव श्रीवास्तव के 2 कर्मचारियों के दौहरे वेतन से ज्यादा भुगतान के प्रकरण सामने आए हैं। नर्मदा चतुर्थ चरण के पानी आने से पूर्व यह कहा जाता था कि नगर के अधिकांश क्षेत्रों में 24 घंटे पानी मिलेगा बाद में आते आते वह पानी प्रतिदिन 1 घंटे हो गया और बाद में जब नर्मदा का पानी इंदौर के आने लगा तो वही पुराना 2 दिन में एक बार आधा घंटे पानी दिया जाने लगा। आखिर वह 80 एमएलडी पानी कहां चला गया इसमें उस समय के नर्मदा के प्रोजेक्ट इंजीनियर रहे प्रभात सांखला, राजवाड़े, संभागायुक्त, जिलाधीश, निगम महापौर निगम आयुक्त 1 इंजीनियरों ने मिलकर वह पानी नर्मदा के तृतीय चरण की शुरुआत होने से पूर्व भी इंदौर के चारों तरफ बाईपास, राउ, ए बी रोड पर बसी 300 से ज्यादा कॉलोनियों में अरबों रुपए भू माफिया और कॉलोनी माफिया से लेकर वह पानी उनकी कॉलोनी में पहुंचा दिया। जबकि शहर के बीच शहर के हर दिन 50 से 60% लोगों को आधे घंटे भीपर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। पर बिल पानी मिले ना मिले सालों से बलि भेजा जा कर वसूली की जा रही है शिकायतों पर कोई सुनने वाला नहीं। पानी मिले ना मिले परंतु बिल अवश्य मिलेगा और उसे भरना भी पड़ेगा अन्यथा वह कुर्की आर्डर निकाल देंगे। पानी के नाम खुली गुंडागर्दी और वसूली का तांडव पार्षदों से लेकर निगमायुक्त और महापौर का खुले में चलता है इसकी आड़ में टैंकर चलाने का पूरा मौका मिलता है और टैंकरो से टैंकर ड्राइवर से लेकर पार्षदों, अधिकारियों-कर्मचारियों और

वैदिक संस्कृति के प्रतीक गुरुकुलों की अवनति कॉन्वेंट स्कूलों के कारण

राजीव दीक्षित

भारत की वैदिक शिक्षा को समाप्त कर अंग्रेजी थोप कर, भारतीयों को हमेशा के लिए मानसिक अपाहिज बना दिया गया।

1858 में Indian Education Act बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग *'लोर्ड मैकोले'* ने की थी। लेकिन उसके पहले उसने यहाँ (भारत) के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था, उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी।

अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. Litnar और दूसरा था Thomas Munro, दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग-अलग समय में सर्वे किया था।

1823 के आसपास की बात है ये Litnar , जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ *97% साक्षरता है*और Munro, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा कि यहाँ तो *100 % साक्षरता है।*

और उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है और मैकोले का स्पष्ट कहना था कि यदि भारत को हमेशा-हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो इसकी "देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था" को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह *"अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था"* लानी होगी और तभी इस देश में शरीर से हिन्दुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे।

और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में ही काम करेंगे और मैकोले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है: *"कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी।"*

इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित किया, जब गुरुकुल गैरकानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज के तरफ से होती थी वो गैरकानूनी हो गयी ।

फिर संस्कृत को गैरकानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर ख़त्म कर दिया उनमे आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा- पीटा, जेल में डाला...

1850 तक इस देश में '7 लाख 32 हजार' गुरुकुल हुआ करते थे* और उस समय इस देश में गाँव थे *'7 लाख 50 हजार',* मतलब हर गाँव में औसतन एक गुरुकुल और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में *'Higher Learning Institute'* हुआ करते थे उन सबमे 18 विषय पढाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल के चलाते थे न कि राजा, महाराजा, और इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी।

इस तरह से सारे गुरुकुलों को ख़त्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया, उस समय इसे *'फ्री स्कूल'* कहा जाता था।

इसी कानून के तहत भारत में *कलकत्ता यूनिवर्सिटी* बनाई गयी, *बम्बई यूनिवर्सिटी* बनाई गयी, *मद्रास यूनिवर्सिटी* बनाई गयी और ये तीनों गुलामी के जमाने के यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में हैं।

और मैकोले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी बहुत मशहूर चिट्ठी है वो, उसमें वो लिखता है कि....

"इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने परम्पराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे, जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाएँ इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी।"

उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ़-साफ़ दिखाई दे रही है और उस एक्ट की महिमा देखिये कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, अंग्रेजी में बोलते है कि दूसरों पर रोब पड़ेगा, अरे हम तो खुद में हीन हो गए हैं जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रोब क्या पड़ेगा..?

लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है, फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है।

शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजों की जो बाइबिल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईशा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे।

ईशा मसीह की भाषा और बाइबिल की भाषा *"अरमेक"* थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी, समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गयी।

संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है वहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहां का सारा काम *'फ्रेंच'* में होता है।

जो समाज अपनी मातृभाषा, परम्परा, संस्कृतियों, और मूल से कट जाता है उसका पतन निश्चित है और आखिर यही तो मैकोले की रणनीति थी।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

सरकार क्यों हिंदू मंदिरों का दान हड़पती है। चर्च और मस्जिदों में प्राप्त धन को छूने की औकात नहीं

मंदिरों का दान सत्ताधीशों के बाप की जागीर नहीं, वेदाध्ययन संस्कृत आयुर्वेद के विकास में हो

पुनः प्रारंभ की जाए गुरुकुल शिक्षा पद्धति जहां पर हमारे शास्त्रों पुराणों के के गूढ़ रहस्यों का पठन पाठन हो और वर्तमान में इसका उपयोग किया जाना चाहिए जिसे मैकाले ने नष्ट कर दिया था

हिंदुओं का शोषण सहस्त्रों वर्षों से मात्र इसलिए होता आया है की हिंदू संगठित नहीं है और आज भी इसीलिए उसका घोर शोषण हो रहा है कि वह वर्तमान में भी जाती पाती ऊंच-नीच मैं उलझ कर आपस में ही लड़ मर कर नष्ट हुआ जा रहा है। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए, पिछली 10वीं शताब्दी से जब से मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया, इसके बाद 16 वीं शताब्दी से अंग्रेजों, पोर्तुगीज डच, ने ईसाई धर्म को फैलाने में, आजादी के बाद से ही कांग्रेस सरकारों ने जो ईसाई धर्म को फैलाने कें जो षडयंत्र किए और बर्तमान में भी गरीब आदिवासियों निम्न जाति के लोगों और उच्चच जाति के गरीबों को पैसे बांट, स्वच्छंद यौनाचार आदि में उलझाकर अभी भी लगातार मुस्लिम ईसाई धर्म फैलाया जाकर हिंदुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें भी बर्तमान की भाजपा सरकार ने क्योंकि अपने आपको हिंदुओं का घोर हतिषी बताती है और इसी दम पर उसने सत्ता हथियाई है। हिंदुओं की आबादी घटाने, दो बच्चों तक परिवार को सीमित कर हिंदुओं को समाप्त करने के, उनकी महिलाओं बच्चियों को भगाकर शादी करने, उनकी बस्तियां खाली करवाने, जो कि पूरे देश के हर शहर में चल रहे षड्यंत्रों को रोकने की अपेक्षा उल्टे ही वह मुस्लिम और ईसाई वोटों को हथियाने के लिए उनका अंध सहयोग कर रही है। जबकि कम से कम मंदिरों से प्राप्त दान के धन को हिंदुओं के धर्म के विस्तार के लिए हिंदूओं के वेदों, पुराणों, पौराणिक ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों, संस्कृत भाषा आदि के सूक्ष्म अध्ययन, उनके विस्तार उनकी महत्ता, जिसमें आयुर्वेदिक, खगोल, भौतकी, रसायन, वैदिक गणित, कालगणना, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, मौद्रिक शास्त्र, विधिशास्त्र, विमानन शास्त्र, युद्ध कला, पाककला, प्राणी व वनस्पति विज्ञान आदि की वर्तमान संदर्भ में उनकी उपयोगिता का सूक्ष्म अध्ययन किया जाना चाहिए। जिसके आधार पर जर्मनी अमेरिका ब्रिटेन व अन्य कई देश हमसे आगे बढ़ चुके हैं। यथार्थ में परमाणु विज्ञान भी भारत की ही देन है। पर हम हमारे ही पुरातन ज्ञान को भूलकर विदेशों पर आश्रित हो गए यूरोप के अधिकांश विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन करवाया जाता है उन्होंने हमारी पुरातन शास्त्रों से अनेकों नए अविष्कार किए। हमारी आयुर्वेदिक औषधियों, मसालों, शल्य चिकित्सा योग आदि पर अनेकों पेटेंट सुरक्षित करवा लिए और हमारी सरकार हमारे बुद्धिजीवी सब देखते रह गए। यह अंग्रेजों का और यूरोपियन षडयंत्रकारियों का 18 वीं शताब्दी से चलने वाला भारतीय संस्कृति ज्ञान विज्ञान संस्कृत भाषा के विरुद्ध चलने वाला षड्यंत्र था। इसके अंतर्गत

18 वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजों ने दीर्घगामी षड्यंत्रों की की रचना की। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारे देश की गुरूकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट किया गया। हजारों गुरुकुल के आचार्यों को जिंदा जला दिया। पूरे देश की गांव में फैले डेढ़ लाख से ज्यादा गुरुकुलों को नष्ट किया गया। संस्कृत का पठन पाठन गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अवैध करार दे दिया गया। उसके स्थान पर कान्वेन्ट रूपी अनाथालयों को प्रचलन में लाया गया जहां अंग्रेजी माध्यम से यूरोप के टूटे-फूटे आधे अधूरे ज्ञान इतिहास की शिक्षा दी जाती थी जिसका उद्देश्य था भारतीयों को जीवनपर्यंत सैकड़ों वर्षो तक गुलाम बनाए रखने के लिए उनके पौराणिक ज्ञान विज्ञान इतिहास नष्ट कर यूरोपियन म्लेच्छों की म्लेच्छता में डालकर उनकी श्रेष्ठता पर कब्जा जमा कर स्वयं को श्रेष्ठ बनाया जाए। उसमें भी वे सफल भी रहे। और हम भारतीय भाषाई, सांस्कृतिक, शैक्षिक सामाजिक रूप से हम मानसिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम उनके चले जाने के बाद में भी बने हुए हैं। पिछले 65 सालों से कांग्रेस के कब्जे में सत्ता रहने के कारण, उन्होंने भी पूर्णताः अंग्रेजों की इन अवैध औलादों ने जानबूझकर हिंदुओं को प्रताड़ित करने, उनकी जनसंख्या घटाने, हिंदू मंदिरों में प्राप्त दान, संपत्तियों, जमीनों के अरबों के धन को कानून बनाकर हड़पना शुरु कर दिया। अब जबकि भाजपा शासन में है चाहिए हिंदुओं के मंदिरों में प्राप्त दान कें धन से पुनः गुरुकुलों की स्थापना कर हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत का, हमारे पुराने ज्ञान को, वेदों पुराणो उपनिषदों के सूक्ष्म अध्ययन की पुनः व्यवस्था करवाएं हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ा कर उनके बच्चों को गुरुकुलों में शिक्षा दी जाए और उसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़ा जाए । हमारे देश के हिंदू विद्यार्थियों मैं पौराणिक विज्ञान का, योग से मस्तिष्कीय की तरंगों का उपयोग कर अदृश्य शक्तियों का विकास और ज्ञान प्राप्ति की दिशा में बहुमुखी विकास कर पुनः अपने राष्ट्र की श्रेष्ठता को स्थापित करना होगा।

भारत के केंद्र और राज्य की सरकारों में अगर दम है तो मस्जिदों में और चर्चो में प्राप्त धन जो अधिकांशतः विदेशी संस्थाओं से देश में आतंक फैलाने धर्म परिवर्तन करने देश की अखंडता को नष्ट करने कें काम आता है। पर निगरानी कर उस धन को जप्त करें और गरीब हिंदुओं का मुस्लिम और ईसाइयत मैं धर्मपलायण रोको । वहां तो सरकार की ना तो पहुंच है न हीं हिम्मत। स्वयं सरकारें केंद्र व राज्य की हिंदूओं का धन हडपने के लिए ही अभी तक कानून बना पाई।

वहां पर अपने रिसीवर बैठा दिये। जो बरसों से पूरे देश में हिंदुओं जैनियों के मंदिरों की संपत्ति व प्राप्त दान के धन की बन्दरबांट में लगे रहते हैं। यह कब रुकेगा हिंदू क्या हिंदुओं की सरकार में भी लुटता ही रहेगा।

यहां तक किया गया कि जितने भी मंदिरों के नाम से जो जमीन थी जो वहां के पंडितों के नाम से थी हाल ही के कुछ महीनों में उन सब पर वहां के जिला कलेक्टरों ने षडयंत्र से अपने नाम कर ली है। और जमीन पर कब्जा ले लिया इस प्रकार से यह हरामखोर सरकारी कलेक्टर मंदिरों की जमीन को भी अब हड़पकर बेचने की तैयारी में आ गए हैं यहहै । भाजपा का हिंदुत्व प्रेम। किस प्रकार से सभी बड़े मंदिरों में वहां के जिला कलेक्टरों ने अपने नाम की दानपेटी लगा रखी हैं जिसमें जोधन हिंदुओं द्वारा चढ़ाया जाता है वह सारा कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारी हड़प जाते हैं और बाद में हरमंदिर का बजट घाटे का बना कर दिखाया जाता है।

विनाश पुरुष मोदी: भारत में बाजार व्यवस्था और मंडिया बंद करने की तैयारी

भाजपा का प्रमं मोदी 50 करोड़ जनता को भिखारी बना देगा

भुखेरा जन पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजी पतियों की रखैल पूंजीपतियों के इशारे पर देश की जनता का खून पीने उसकी 50 करोड जनता को भूखा मारने पर तुला हुआ है जैसा कि सूकर सेमुअल मूरे वाटसन दुनिया में वॉलमार्ट स्टोर का मालिक है।जिसने कांग्रेस को 5500 करोड़ डॉलर देकर इस देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 लागू करवा दिया। भाजपा का प्रमं मोदी 50 करोड़ जनता को भिखारी बना देगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपना व्यापार समेट लो, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो बिना धन के कौन खरीदेगा तुम्हारा माल।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब उसकी कृषि, कृषि उपज मंडी किसानों की जमीनों कृषि भूमि पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों कब्जा हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, की भारत के 20करोड किसान, कृषि उत्पादन से जुड़े व्यापारी, खाद्य सामग्री से जुड़े व्यापारी विक्रेता व अन्य लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि इस व्यापार पर सारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरुप बेरोजगारी के चलते 50 करोड़ लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। तो वह क्या मोबाइल गाड़ियां कारें मोटरसाइकिल एयर कंडीशन फ्रीज, ट्रैक्टर मकान व अन्य सामग्री कोई कैसे खरीदेगा। तो इनके उत्पादन बढाने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जीने के लिए पहले पहले भोजन चाहिए मोबाइल मोटरसाइकिल सुंदर वस्त्र, आभूषण व अन्य महंगी वस्तुएं कैसे खरीद पाएगा, बच्चों को पढा पाएगा। अर्थात धन के अभाव में चीनी माल भारत में बिकना बंद हो जाएगा। जब लोगों के पास कंप्यूटर मोबाइल ही नहीं होंगे तो कैसा इंटरनेट कैसे गूगल की सर्च, गूगल के ऐप्स डाउनलोड करेगा कोई। भारत सरकार बहुत जल्दी भारत के अंदर पूरे देश में कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था को खत्म कर कृषि विपणन का व्यवसाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने जा रही है। यह एक राक्षस पूंजीपति बहुराष्ट्रीय कंपनियां वॉलमार्ट अंबानी टाटा बिरला पहले किसानों की फसल को आधे से भी कम कम कीमत पर खरीदेंगे। बाद में किसान बैंकों और साहूकारों के कर्ज के चलते अपनी जमीन पूंजीपति आधुनिक राक्षसों को सौंप देगे या पूंजीपति राक्षस उसकी जमीनों को हजम कर जाएंगे। स्वभाविक है कि आम 50 करोड़ लोग जो खेती-बाड़ी खाद्य वस्तुओं सब्जी भाजी पैदा करने से लेकर पेकिगह बिक्री से जीवन यापन करते हैं। बेरोजगार होकर मरने के लिए सड़कों पर आकर लूटमार चोरी डकैती और अपराध करेंगे। स्वाभाविक है कि भारत में बिकने वाला चीनी माल जिसमें मोबाइल कंप्यूटर साड़ियां कपड़े खेल खिलौने विद्युत सामग्री लाइटिंग कॉस्मेटिक जो चीनी माल का सबसे बड़ा बाजार है। जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लूटमार के चलते खत्म हो जाएगा सेमसंग, एपल, विवो, अप्पो आदि की बिक्री खत्म हो जाएगी। बजाज, टीवीएस, टाटा, होंडा, सुजुकी, महिंन्द्रा की कारें मोटरसाइकिल स्कूटर, विद्युत की सामग्री सबका व्यवसाय चौपट होने के लिए अधिकतम 3 से 4 साल लगेंगे। फिर भूखा मरने वाला हर आदमी नक्सली बन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों और पूंजीपतियों की लूटमार चोरी डकैती और अपराध से गुजर-बसर करेगा।

Facebook के जुकरबर्ग ने दुनिया के 300 करोड़ से ज्यादा लोगों का डेटा उपयोग किया उसे बेचा और उससे मोटी कमाई की साथ ही उसने Facebook उपयोग करने वाले लोगों का अपने उपभोक्ताओं का ना केवल डाटा बेचा वरन उनके वॉल पर राजनीतिक पार्टियों से मोटा धन लेकर उनके खातों में झूठी तारीफें झूठे वादे भय दिखाकर मोदी जैसे लोगों ने सत्ता हथियाई जिसमें रूस अमेरिका ब्रिटेन जैसे अग्रिम पंक्ति के लोग अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रपति है इस संबंध में अमेरिकी सीनेट में जो जुकरबर्ग की पेशी दिखाई गई यह पूरी निर्धारित नौटंकी थी। जिसमें हर सीनेटर को मोटा पैसा देकर जानबूझकर पूछताछ के लिए मात्र हर सीनेटर को 5 मिनट दिए गए बदले में अमेरिकी सीनेट में सच में उसको बचाने की जो नौटंकी की गई उससे सिद्ध हुआ, पूरी दुनिया के सामने अमेरिका ने ही अपने आप की छवि सुधारने के लिए जुकरवर्ग की पेशी जरुर की, पर उसे बचाने के लिए भी पूरे हथकंडे अपनाए गए। जबकि जुकरबर्ग ने स्वयं ही अमेरिका के मामले में स्वीकार किया कि उसने आठ करोड़ 36 लाख लोगों का Facebook डेटा का उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया। यह कहानी थी जिसमें अमेरिकी सीनेट ने अपने देश की छवि को सुधारने और जनता को आगह करने के लिए यह डाटा चोरी का यथार्थ दुनिया की जनता के सामने लाकर दुनिया को बता दिया कि यह सारी सोशल साइट किस प्रकार से जनता की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग कर कैसे मोटी कमाई कर रही हैं यह सच जो समय माया अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर रहा था किस प्रकार से फ़ेसबुक, टवीटर गूगल जनता को जो मुफ्त की सेवाएं दे रहे हैं

यथार्थ में उसके पीछे का सच क्या है जब अमेरिका जैसे देश में 8.36करोड लोगों का डेटा का उपयोग व्यापारिक स्तर पर जुकरबर्ग ने करके भारी मोटी कमाई की साथ ही फेसबुक प्लेटफार्म का सदुपयोग कर अमेरिका में ट्रंप ने भी सत्ता हथियाई। निसंदेह भारत में यह काम पहले कांग्रेस ने और फिर लाखों करोड़ों खर्च करके भाजपा ने मोदी ने 2014 के चुनाव में देश की सत्ता हथियाई थी। इसमें बकायदा श्याम दाम दंड भेद एक तरफ आतंकवादी और मुस्लिम का भय दिखाकर हिंदुओं को हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण किया गया तो दूसरी तरफ झूठी तारीफें महंगाई कम करना रोजगार देना आतंकवाद खत्म करना देश की सीमाओं को सुरक्षित करना का शुभ फल देने के साथ-साथ जनता के खाते में विदेश में पड़ा हुआ काला धन लाकर रुपए 15लाख जमा करने का प्रलोभन दिया गया यह सारा खेल भारत में फेसबुक के माध्यम से हुआ उसी प्रकार फ़ेसबुक, टवीटर गूगल का भी भुखेरा जन पार्टी के लोगों ने भारी सदुपयोग किया और लोगों को डराने धमकाने और लालच देने का पूरा खेल लगातार सितंबर 2013 से लेकर मई 2014 तक चलता रहा जिसमें भारत के 30 करोड उपभोक्ताओं का डाटा और खातों का उपयोग किया गया पूरी दुनिया में चीन को छोड़कर लगभग इसी प्रकार फ़ेसबुक, टवीटर गूगल ने 300 करोड़ लोगों का डेटा उपयोग कर न केवल मोटी कमाई की वरन आइएसआइ जैसे संगठनों में आतंकवादी मुस्लिम युवाओं की भर्ती करने,स्वयं ही लव जिहाद के लिए गैर मुस्लिम महिलाओं के खातों में जो कि बौद्ध ईसाई और हिंदू थी मुस्लिमों के हाथों, जोड़कर उनकी बात पहुंचाकर झूठी तारीफे करवा कर गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का कांड भी इसी सूअर जुकरबर्ग ने किया और करवाया जिसे बाद मैं उसे स्वीकार भी किया के लिए फ़ेसबुक, टवीटर गूगल ने हीं आंख मीच कर अपने प्लेटफार्म का सदुपयोग करने दिया और अरबों डॉलर की कमाई की।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर। मोबा. 9425125569, 9479535569